R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth
पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 I अंक : 22
16 से 31 अगस्त 2025
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

1947 से 2025 तक 78 साल की विकास यात्रा

विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना भारत

एक गरीब मुल्क से आज हिंदुस्तान बन गया है वैश्विक आर्थिक शक्ति

पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक 14 प्रधानमंत्रियों का अमूल्य योगदान

मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प

अक्षय जल, सुरक्षित कल

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

जल गंगा संवर्धन अभियान

"जल की हर बूंद में आने वाले कल का भविष्य छिपा है। इसलिए इस अमूल्य धरोहर की किसी भी मूल्य पर रक्षा करना हमारा दायित्व है।"

\- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

जल संरक्षण का 'जन संकल्प'

जल संचय में वृद्धि

- ₹2048 करोड़ लागत के 83 हजार से अधिक खेत तालाबों का निर्माण पूर्ण, जिनसे खेत का पानी खेत में सिंचित होगा
- ₹254 करोड़ लागत से 1 लाख से अधिक कूप रीचार्ज
- अमृत सरोवर 2.0 के तहत ₹ 354 करोड़ लागत से 1 हजार से अधिक नए अमृत सरोवरों का निर्माण
- शहरी क्षेत्रों में 3200 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, 2200 नालों की सफाई एवं 4000 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण पूर्ण

जनभागीदारी

- 40 लाख लोगों की भागीदारी से 5 हजार से अधिक जल स्रोतों का हुआ जीर्णोद्धार
- My Bharat पोर्टल के माध्यम से 2.30 लाख से अधिक जलदूत बनाए गए
- ग्रामीण क्षेत्रों में पानी चौपाल का आयोजन

तकनीकी नवाचार

- GIS आधारित SIPRI सॉफ्टवेयर के उपयोग से जल स्रोतों का चयन एवं AI आधारित मॉनिटरिंग की गई
- नर्मदा परिक्रमा पथ एवं अन्य तीर्थ मार्गों के डिजिटलीकरण के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जा सकेगा ख्याल

पर्यावरणीय एवं कृषि प्रभाव

- 57 प्रमुख नदियों में मिलने वाले 194 से अधिक नालों का चिह्नांकन एवं उनके शोधन के लिए योजना तैयार
- जैव विविधता संरक्षण हेतु वनस्पतियों और प्राणियों का किया गया सर्वेक्षण
- 145 नदियों के उद्गम क्षेत्रों को चिन्हित कर हरित विकास हेतु योजना तैयार
- अविरल निर्मल नर्मदा योजना में 5600 हेक्टेयर में पौधारोपण प्रारंभ
- वन्य जीवों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 2500 से अधिक तालाब, स्टॉप डैम का निर्माण
- पौधारोपण हेतु लगभग 6 करोड़ पौधों की नर्सरी विकसित

वॉटरशेड हेतु कार्य

- ₹1200 करोड़ लागत की 91 वॉटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत, 5.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगी सिंचाई सुविधा
- 9000 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं के ज़रिए किसानों को 1 वर्ष में दो से तीन फसलों का मिल रहा लाभ

इस अंक में

विवाद

8 | सरकार के निशाने पर संजय पाठक

सुशासन की राह पर चल रही डॉ. मोहन यादव की सरकार की नजर में हर वह व्यक्ति जो कायदे-कानूनों को दरकिनार कर काम करता है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसका ताजा...

डायरी

10-11 | अनुराग जैन को...

सितंबर का महीना मप्र में प्रशासनिक हलचल वाला रहेगा। इस महीने में मप्र को नया प्रशासनिक मुखिया यानि मुख्य सचिव मिलने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 अगस्त...

तैयारी

13 | 8 हजार गांवों में जल्द...

प्र सरकार जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 8 हजार गांवों में नल से जल पहुंचाने के लिए 2,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत, इन गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने खाका तैयार कर लिया है।

लालफीताशाही

15 | शराब ठेकेदार खा गए...

शराब ठेकेदारों ने मप्र सरकार को 756 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। तीन साल बीत चुके हैं, अभी तक सरकार ये रकम वसूल नहीं पाई है। ये खुलासा हुआ है, भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षा (कैग) की रिपोर्ट में। 31 मार्च 2022 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष की ये रिपोर्ट 31 जुलाई...

आवरण कथा

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तब भारत की तुलना एक गरीब देश से होती थी। लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विकास की जो नींव रखी थी, उस पर अन्य प्रधानमंत्रियों ने विकास की ऐसी इमारत खड़ी कर दी है, जिससे आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। आजादी के बाद से भारत में सरकारें बदलीं, प्रधानमंत्री बदले, लेकिन विकास का मिशन निरंतर जारी रहा। यही कारण है कि एक गरीब मुल्क से आज भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है।

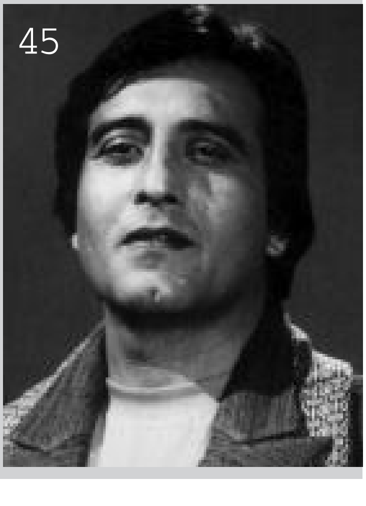

सियासत

30-31 | क्या जातीय युद्ध में...

दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा के सामने दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अब विपक्ष पहले से कहीं अधिक जागरूक हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा अपने ही बोझ से दब कर टूट जाएगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि विपक्ष अब हर छोटे-बड़े मुद्दे पर...

महाराष्ट्र

35 | धारावी: पुनर्विकास...

एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी अब पुनर्विकास के मुहाने पर खड़ी है। 600 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैली धारावी में एक लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। दावों के अनुसार देश के जाने-माने बिजनेस टायकून गौतम अडानी मुंबई में स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी...

बिहार

38 | किसका पलड़ा भारी

बिहार में चुनाव सिर पर हैं, मगर एनडीए पूरी तरह से अस्त-व्यस्त नजर आ रही है। कहने को मुख्यमंत्री का चेहरा फिलहाल नीतीश कुमार जरूर हैं, पर चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ने की तैयारी चल रही है। कमजोर नेतृत्व और अलग-अलग...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-22, पृष्ठ-48
16 से 31 अगस्त, 2025

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना अनूप यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

सत्ता की कूटनीति से विपक्ष संगठित

प्रख्यात शायर मुनव्वर राणा का एक शेर है...

एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है
तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना

उपरोक्त पंक्तियां विपक्षी पार्टियों के आक्रोश को दर्शाती हैं, जिन्होंने सत्ता की कूटनीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि 11 सालों के दौरान सत्तारूढ़ दल ने आम लोगों के आंसुओं की कद्र नहीं की। जिसका परिणाम यह हो गया है कि खंड-खंड होकर हर मोर्चे पर सत्तारूढ़ से मात खाने वाला विपक्ष अब पूरी तरह संगठित हो गया है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का जो अभियान चला उसे विपक्ष ने चुनाव जीतने के लिए सत्ता की कूटनीति बताया है और सत्तापक्ष की तथाकथित कूटनीति विपक्ष के लिए संजीवनी बन गई है। अब वोट चोरी के आरोपों ने देश की राजनीति में नई सरगर्मी पैदा कर दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र समेत कई इलाकों में एक लाख से अधिक फर्जी और डुप्लिकेट नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने का सनसनीखेज दावा किया। उनके मुताबिक यह सुनियोजित, संगठित और व्यवस्थित तरीके से रची गई साजिश है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करना और संविधान को कमजोर करना है। इसके बाद कांग्रेस ने पूरे देश में एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू कर दिया। बड़ी बात यह है कि इंडिया ब्लॉक उनके पीछे मजबूती से खड़ा दिख रहा है। जाहिर है कि यह मुद्दा अब देश की राजनीति में एक बड़े टकराव का आधार बन गया है। इस टकराव ने इंडिया को एक बार फिर से एकजुट होने का मौका दे दिया है। 2024 के आम चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी अक्सर अलग ही राह पर चलती नजर आ रही थीं। लेकिन इस बार उन्होंने भी राहुल के आरोपों को गंभीर मानते हुए उन्हें अपना समर्थन दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तृणमूल का यह बदला हुआ रुख राहुल गांधी की साख को विपक्षी खेमे में मजबूत तो कर ही सकता है, इसके साथ ही आने वाले समय में विपक्षी रणनीति में नई ऊर्जा का संचार भी कर सकता है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर विपक्षी एकता को औपचारिक रूप देने के लिए अपने आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें इंडिया के 25 दलों के 50 से अधिक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में साफ संदेश दिया गया कि यह मामला महज कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि देशव्यापी है। संदेश से निकला यह संकल्प भी साफ रहा कि मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता के सवाल को अब हलके में नहीं लिया जा सकता। 2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने संविधान की रक्षा को अपना केंद्रीय एजेंडा बनाया था। शुरुआत में यह मुद्दा सियासी मंचों से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन धीरे-धीरे गरीब, दलित और हाशिए पर खड़े वर्गों के बीच पैठ बनाने लगा। भाजपा को इसके चलते कुछ इलाकों में बैकफुट पर आना पड़ा, और कई जानकार मानते हैं कि पार्टी के अपेक्षाकृत कमजोर नतीजों में इस नैरेटिव का अहम योगदान रहा। अब राहुल और उनके सहयोगी दल वोट चोरी को भी इसी संविधान-रक्षा वाले नैरेटिव से जोड़कर पेश कर रहे हैं, ताकि यह न सिर्फ एक भावनात्मक मुद्दा बने, बल्कि इसे नैतिकता की कसौटी पर और कसा जा सके। विपक्ष का मानना है कि यह विवाद सिर्फ राहुल बनाम चुनाव आयोग का नहीं रहेगा। अब यह लोकतंत्र की पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की साख की सीधी परीक्षा बन सकता है। देश की राजनीति में निगाहें अब इस बात पर रहेंगी कि सच के पलड़े में भारी कौन पड़ता है। राहुल गांधी के लिए लड़ाई सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कानूनी, राजनीतिक और जनसमर्थन से जुड़े कई पहलू हैं।

- राजेन्द्र आगाल

इंदौर फिर नंबर-1

स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 में इंदौर एक बार फिर देशभर में स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे आगे रहा। सुपर स्वच्छ लीग सिटी में इंदौर को देशभर में पहला स्थान मिला है। यह अवॉर्ड 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में दिया गया। यह इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

● **प्रियांशी पाठक,** इंदौर (म.प्र.)

नए प्रदेश की मांग क्यों?

देश में भाषा विवाद के बीच नए प्रदेश की मांग देखने को मिल रही है। देश में एक बार फिर से नए राज्यों को बनाने की मांग उठ रही है। इनमें दो प्रदेशों की मांग ऐसी है जो मप्र से संबंधित हैं। पहला भील प्रदेश और दूसरा चंबल प्रदेश। सवाल यह है कि आखिर नए प्रदेश की मांग क्यों उठ रही है?

● **राहुल यादव,** सागर (म.प्र.)

नाराज नेताओं को करेंगे फिट

भाजपा सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव में हारने वाले भाजपा के पूर्व मंत्रियों का राजनीतिक पुनर्वास कर उन्हें मुख्यधारा में लाने की तैयारी कर ली है। इन नेताओं को जल्द ही निगम-मंडल आयोगों में पद देकर कैबिनेट मंत्री के दर्जे से नवाजा जाएगा। इससे नाराज नेताओं को मनाने की कवायद है।

● **प्रफुल वर्मा,** विदिशा (म.प्र.)

पक्ष-विपक्ष के हंगामे के बीच दब रहे जनता के मुद्दे

संसद की बैठक चलाने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों पर है, लेकिन सरकार पर कहीं ज्यादा। दूसरी तरफ विपक्ष को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि संसद में अपने मुद्दों के उठाने के अपने अधिकार को हाथ से न जाने दे। इससे तो सत्तापक्ष को ही लाभ होता है। संसद और विधान मंडलों में हंगामे का सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को होता है तो वह है जनता। विपक्ष के पास सदन की बैठक ही सबसे बड़ा मारक हथियार है। प्रश्न प्रहर और शून्य प्रहर में उठने वाले मुद्दे तमाम समस्याओं का निदान लेकर आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन यह कोई पहली बार नहीं हुआ। सत्तापक्ष और विपक्ष की भूमिकाएं बदलने के साथ उनका रुख भी बदलता रहा है।

● **निदा खान,** भोपाल (म.प्र.)

किसानों की सुने सरकार

मप्र के अधिकांश जिलों में खरीफ सीजन की बुवाई पूरी हो चुकी है और अब किसानों को खाद की जरूरत है। समय पर खाद नहीं मिलने से सबसे ज्यादा असर बुवाई पर पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि समय से खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हम कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं अब बोला जा रहा है कि जल्द ही खाद मिलेगी, लेकिन रोज-रोज चक्कर लगाने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। सरकार को किसानों की समस्या का हल निकालना होगा।

● **दिनेश सिंह,** राजगढ़ (म.प्र.)

चुनावी तैयारियों में जुटीं भाजपा-कांग्रेस

देश में चुनावी माहौल बनता जा रहा है। आने वाले चुनावों में दो मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने कार्यकर्ता या पदाधिकारियों के साथ आए दिन बैठक कर रही है और चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की अपील कर रही है। भाजपा की बैठकों में सरलता और सुचिता की लगातार हिदायत दी जा रही है। भाजपा की रणनीति है कि वे घर-घर जाकर आमजन का हाल पूछे। इससे आम जनता वहीं में भाजपा की पकड़ मजबूत होगी। वहीं कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, ओबीसी आरक्षण, महिला अपराध, किसान, युवाओं, एसआईआर को केंद्र में रखकर काम करेगी।

● **अभिषेक पुरोहित,** खंडवा (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

जगन मोहन के दावे में कितनी सचाई

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भले एनडीए का हिस्सा हैं लेकिन वे राहुल गांधी के निरंतर संपर्क में हैं। जगन मोहन रेड्डी की मानें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सेतु का काम कर रहे हैं। यानी रेड्डी के सहारे चंद्रबाबू और राहुल जुड़े हुए हैं और दोनों के बीच अक्सर बातचीत होती है। जगन मोहन का कहना है कि इस वजह से राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मामला नहीं उठा रहे हैं। उनके मुताबिक आंध्र प्रदेश में भी वोट चोरी के जरिए नायडू की पार्टी जीती है लेकिन राहुल यह मामला नहीं उठा रहे हैं। जगन के इस दावे के बाद सोशल मीडिया में कांग्रेस इकोसिस्टम के लोगों की बांछें खिली हुई हैं। उनको लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। वे मान रहे हैं और लिख, बोल रहे हैं कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश की पार्टी एनडीए छोड़ देगी और चंद्रबाबू नायडू भी छोड़ देंगे तो मोदी सरकार गिर जाएगी। समूचा इकोसिस्टम राहुल गांधी को असली चाणक्य साबित करने में लगा है। बताया जा रहा है कि राहुल ने कांस्टीट्यूशन क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूड़ी की मदद करके अमित शाह के उम्मीदवार संजीव बालियान को हरवा दिया और अब चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर दिल्ली में खेला कर सकते हैं।

योगी क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं?

भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या सचमुच सबकुछ ठीक नहीं है या यह सिर्फ एक साजिश थ्योरी है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं पसंद करने वाले लोग फैला रहे हैं? दो बातें जंगल की आग की तरह फैली हुई हैं। पहली बात तो यह है कि अगर 75 साल का होने पर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ा तो भाजपा के अंदर घमासान होगा और दूसरी बात यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाने की कोशिश हुई तो ऐसा भूकंप आएगा, जिससे दिल्ली की सत्ता हिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल का होने पर क्या करेंगे, इसका पता अगले महीने 17 सितंबर को चल जाएगा। अभी तक इस बात की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है कि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ या भाजपा के कुछ नेताओं के किसी दबाव से मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले हैं। इसलिए वह ज्यादा दिलचस्पी का मामला नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला है या हो सकता है और अगर हुआ तो भूकंप आएगा, यह चर्चा कई कारणों से दिलचस्प है। इस चर्चा में दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ गई है कि ठाकुर गोलबंदी अचानक बहुत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में ठाकुर विधायकों की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें 40 राजपूत एमएलए और एमएलसी शामिल हुए।

बिहार में चुनाव है तो छठ का ध्यान

बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और इस बार चुनाव लोक आस्था के महापर्व छठ के ठीक बाद हैं। इसलिए भाजपा और केंद्र सरकार को भी छठ का ध्यान आया है। एक तरफ भाजपा के नेताओं ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत के अभियान के तहत देशभर से बिहार के लोगों से मुलाकात की और उनको छठ के मौके पर उनके गांव पहुंचाने के बंदोबस्त का वादा किया तो दूसरी ओर अब केंद्र सरकार ने छठ महापर्व को संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में शामिल कराने का प्रयास शुरू किया है। इसकी पहल कर दी गई है। असल में छठ का सामूहिक आयोजन करने वाली कई संस्थाओं की ओर से सरकार से इसकी अपील की जा रही थी। ऐसी ही एक अपील छठी मैया फाउंडेशन के संदीप कुमार दुबे की ओर से केंद्र सरकार से की गई थी। उनकी अपील पर भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी को निर्देश दिया है कि वह इस पर विचार करके बताए कि यूनेस्को को यह प्रस्ताव भेजा जा सकता है या नहीं। भारत सरकार के अवर सचिव अंकुर वर्मा की ओर से संगीत नाटक अकादमी को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि छठ महापर्व को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने के लिए नामांकन की प्रक्रिया के बारे में सुझाव दे।

राहुल की नाराजगी

कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के मंत्री केएन राजन्ना की सरकार से विदाई एक बड़ा संकेत है। राज्य की सत्ता में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच साझेदारी को लेकर चल रहे विवाद में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ध्यान रहे राजन्ना घोषित रूप से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया खेमे के हैं। वे लगातार मुख्यमंत्री के समर्थन और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ बयान देते रहे हैं। उन्होंने खुलकर कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। ध्यान रहे मुख्यमंत्री नहीं बनने पर शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन राजन्ना बार-बार कहते रहे हैं कि जल्दी ही शिवकुमार प्रदेश अध्यक्ष पद से हटेंगे और सिद्धारमैया के करीबी सुरेश जरकिहोली अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन एक बयान खुद राजन्ना पर भारी पड़ गया। उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का समर्थन नहीं किया, उलटे कह दिया कि इसमें राज्य सरकार की भी लापरवाही है। यानी उन्होंने वोट की गड़बड़ी में अकेले चुनाव आयोग को जिम्मेदार नहीं बताया।

मायावती बदल रही हैं

सत्ता से लंबी दूरी और बहुजन समाज पार्टी की लगातार खराब होती स्थिति का नतीजा यह है कि पार्टी सुप्रीमो यानी बहनजी मायावती बदल रही हैं। यह खबर लखनऊ से है। खबर है कि मायावती ने इस बार नौ अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर पार्टी के अनेक नेताओं को राखी बांधी। बताया जा रहा है कि वे पार्टी कार्यालय में काफी देर तक मौजूद रहीं और वहां आने वाले हर नेता को उन्होंने राखी बांधी। हालांकि सभी नेताओं को इसकी तस्वीर डालने की मनाही थी। फिर भी पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने फोटो सोशल मीडिया में डाली। उन्होंने मायावती को बहन और प्रेरणास्रोत बताते हुए तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही यह बात सार्वजनिक हुई कि मायावती ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और उनको राखी बांधी है। आमतौर पर मायावती से पार्टी नेताओं की मेल मुलाकात दूर से होती है। यहां तक कि पत्रकारों की भी मुलाकात दूर से ही होती है।

चूहा कुतर रहा थान को...

प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गठित विभाग में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है। जानकारों का कहना है कि इस विभाग की तासीर ही कुछ ऐसी है कि इस विभाग में आने के बाद हर अफसर यहां की परिपार्टी में रंग जाता है। इसी का परिणाम है कि इस विभाग में होने वाली हर खरीदी संदेह के घेरे में रहती है। लेकिन विभाग में भर्राशाही इस कदर है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों के बावजूद कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। भ्रष्टाचारी चूहे की तरह धीरे-धीरे पूरे बजट को चट कर रहे हैं। जैसे चूहा कपड़ा के थान को कुतरता रहता है उसी तरह अफसर जरूरी और गैरजरूरी खरीददारी करवाकर विभाग को कुतर रहे हैं। गौरतलब है कि विभाग को कुपोषण दूर करने के लिए अरबों रुपए का बजट मिलता है। हर साल अरबों रुपए का बजट खर्च करने के बाद भी कुपोषण सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि कुपोषण के फंड से किसका पोषण हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि कुएं में मिली भांग की तरह इस विभाग में भी हर एक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यानी विभाग में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के नाम पर की जा रही खरीदी में भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जा रहा है उसमें सभी की मिलीभगत है। सूत्रों का कहना है कि विभागीय मंत्री और विभागाध्यक्ष की चुप्पी भी सवाल बनी हुई है कि आखिर सबकुछ जानते हुए भी वे कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं।

मंत्री के स्टाफ अफसर खोद रहे जिला

सुशासन की राह पर चल रही सरकार ने जिलों में विकास के लिए अपने मंत्रियों को प्रभारी बनाया है, ताकि सरकार की मंशानुसार वहां काम हो सके। लेकिन एक मंत्री की शह पर उनके स्टाफ के एक अफसर मंत्रीजी के प्रभार वाले जिले में अवैध खनन करने में जुटे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी तो अपने प्रभार वाले जिले में कम ही जाते हैं, ऐसे में उनके स्टाफ अफसर ने पूरा जिला संभाल रखा है। बताया जाता है कि स्टाफ अफसर ने मंत्रीजी की आड़ लेकर जिले के कलेक्टर और एसपी को भी साध लिया है और जिले में जमकर रेत का अवैध खनन कराया जा रहा है। आलम यह

है कि जिले के अन्य नेता इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सत्ता और संगठन के नाम पर चुप रहने को बोल दिया जाता है। मंत्रीजी के स्टाफ अफसर की काली कमाई कई नेताओं की आंख में चुभने लगी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि रेत के अवैध खनन का यह मामला जिले से निकलकर राजधानी की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में भी चर्चा का विषय बन गया है। यहां बता दें कि जिस जिले की बात यहां हो रही है, वह जिला आदिवासी बहुल है। और जिस स्टाफ अफसर की बात हो रही है, वे बुंदेलखंड से आने वाले मंत्रीजी के खासमखास हैं।

दिल जले तो क्या नहीं कर सकते... ?

प्रदेश में लव जिहाद, ड्रग्स जिहाद और लैंड जिहाद बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रदेश में लगभग हर दिन इनसे संबंधित मामले सामने आते हैं। लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाला मामला सरकार की नाक के नीचे वाले जिले में सामने आया है। किस तरह सत्तारूढ़ दल का संरक्षण प्राप्त कर कुछ लोग लव जिहाद, ड्रग्स जिहाद और लैंड जिहाद कर रहे थे। यह तो सरकार की दमदारी रही कि उसने सारे हितों को दरकिनार करते हुए आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि जिले के दो मंत्री इन आरोपियों के संरक्षक बने हुए थे। बताया जाता है कि आरोपियों ने दशकों से इन नेताओं को आर्थिक मदद की है। जिसके अहसान तले दबे इन नेताओं ने उन्हें संरक्षण दिया। सूत्र बताते हैं कि यह बात सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक को नागवार गुजर रही थी। ऐसे में मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने बड़ा खेल खेला और पूरे मामले की शिकायत पार्टी के लौहपुरुष के दिल्ली दरबार में पहुंचकर पूरी हकीकत बयां कर दी। दिल्ली दरबार से मिले निर्देशों के बाद आरोपियों का खेल तो लगभग खत्म कर दिया गया है, लेकिन विधायक जी का खेल मुकाम तक पहुंच पाएगा कि नहीं यह तो भविष्य में ही पता चलेगा। बता दें कि लगातार विधायक का चुनाव जीतने के बाद भी उक्त नेताजी को मंत्री बनने का मौका नहीं मिल पाया है। लेकिन अब उन्हें उम्मीद जगी है कि उनकी दाल गल सकती है।

एएसपी से परेशान पुलिस

प्रदेश में सुशासन पर भले ही जोर है, लेकिन सुशासन को बनाए रखने की जिम्मेदारी जिस पुलिस पर है, उसमें ही कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो उनके लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। ऐसे ही अफसरों में एक एएसपी का नाम सामने आया है। उक्त एएसपी महिला हैं। सूत्रों का कहना है कि राजधानी के एक क्षेत्र में उक्त महिला एएसपी सारे कायदे-कानूनों को ताक पर रखकर काली कमाई में इस कदर लगी हुई हैं कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। वैसे यह राजधानी की पहली पुलिस अधिकारी नहीं हैं। ऐसे अफसरों की भरमार है। गत दिनों एक टीआई से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने उक्त थानाक्षेत्र की विधायक और महिला मंत्री से सामूहिक रूप से शिकायत की तो मंत्री ने तत्काल उन्हें हटाने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन सूत्रों का कहना है कि माननीया के क्षेत्र के लोग जैसे ही उनके दरबार से निकले उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ न किया जाए। ऐसे में सरकार ने सुशासन का जो सपना संजोया है, उसे कैसे पूरा किया जाएगा, यह सवाल बना हुआ है।

सब पर भारी शराब माफिया

शराब और शराब माफिया के खिलाफ सरकार सख्त नजर आती है। लेकिन हकीकत में ऐसा शायद ही है। इसकी वजह यह है कि अभी हाल ही में एक पुलिस अधिकारी ने एक शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्या की, बेचारे की नौकरी पर बन आई है। दरअसल, प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार सातवें आसमान पर है। सरकार का निर्देश है कि शराब माफिया पर नकेल कसी आए और अवैध शराब के कारोबार को रोका जाए। सरकार के निर्देश का पालन करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने गत दिनों कठोर कदम क्या उठाया, मामला अदालत तक पहुंच गया। अदालत में पेश तथ्यों के आधार पर उक्त पुलिस अधिकारी को 3 साल की सजा दे दी गई। ऐसे में उक्त अधिकारी ने सरकार से गुहार लगाई। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी गुहार सुनी जाएगी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उनकी सजा कम होने की बजाय और बढ़ गई। ऐसे में सवाल उठता है कि कोई शासकीय अधिकारी सरकार के कायदे-कानून का किस तरह पालन कराए, जब दोषियों की जगह उसे ही सजा भुगतनी पड़े।

सुशासन की राह पर चल रही डॉ. मोहन यादव की सरकार की नजर में हर वह व्यक्ति जो कायदे-कानूनों को दरकिनार कर काम करता है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसका ताजा उदाहरण विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आया, जब एक सवाल के जवाब में खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कटनी जिले के विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी खदानों में अवैध उत्खनन के मामले में वसूली की जाएगी। गौरतलब है कि संजय पाठक कभी सरकार के खासमखास हुआ करते थे, लेकिन अपनी अवैध गतिविधियों के कारण अब सरकार के निशाने पर आ गए हैं। वैसे यहां बता दें कि संजय पाठक पुश्तैनी कांग्रेसी हैं। जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये कुछ कंडीशन पर भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा में शामिल होने के बाद पाठक को मंत्री बनाया गया, लेकिन अब वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि संजय पाठक को अब न तो संगठन और न ही सरकार में भाव मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अवैध खनन और जमीनों पर कब्जा। इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि सरकार ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर अवैध उत्खनन के मामले में 443 करोड़ रुपए का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेसी विधायकों के सवालों के जवाब में यह जानकारी लिखित रूप में दी। यह मामला कटनी जिले के विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी खदानों का है। आरोप है कि जबलपुर के सिहोरा में निर्मला मिनरल्स, आनंद माइनिंग और पेसिफिक एक्सपोर्ट नाम से संचालित उनकी तीन खदानों में स्वीकृत सीमा से अधिक अवैध उत्खनन किया गया।

मार्च 2025 में शिकायतकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित ने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 23 अप्रैल को एक जांच टीम गठित की गई। 6 जून को जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी गई, जिसमें तीनों कंपनियों पर कुल 443 करोड़ रुपए की वसूली का आंकलन किया गया। संजय पाठक और उनकी कंपनियों से जुड़े अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि, कंपनी की ओर से जारी एक पत्र में दावा किया गया कि वे 70 वर्षों से माइनिंग कारोबार में हैं और कोई अवैध उत्खनन नहीं किया गया। उनका आरोप है कि जांच दल ने बिना मौके पर जाए गलत रिपोर्ट तैयार की है। यह कार्रवाई भारतीय खनन ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। ब्यूरो के अधिकारियों ने सैटेलाइट डेटा और अन्य साक्ष्यों के जरिए अवैध उत्खनन की पुष्टि की। विधानसभा में कांग्रेस

सरकार के निशाने पर संजय पाठक

अफसरों ने अनुमान से रिपोर्ट बनाई

कटनी जिले के विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी तीन फर्मों से 443 करोड़ रुपए की वसूली करने को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह के सवाल पर जवाब दिया। इस मामले पर विधायक संजय पाठक ने कहा कि अफसरों ने अनुमान के आधार पर गलत प्रतिवेदन बनाया है। जब कंपनी के दस्तावेज देखे जाएंगे तो सब साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया है कि जबलपुर के सिहोरा में आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट द्वारा स्वीकृत मात्रा से अतिरिक्त खनन किया गया। इसके बावजूद शासन को 1,000 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं की गई। इसकी शिकायत आशुतोष मनु दीक्षित की ओर से ईओडब्ल्यू में 31 जनवरी 2025 को की गई थी। शिकायत के आधार पर मप्र खनिज साधन विभाग ने 23 अप्रैल को एक जांच दल गठित किया था। जांच दल ने 6 जून को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसमें तीनों खनन कंपनियों पर 443 करोड़ 4 लाख, 86 हजार 890 रुपए की वसूली निकाली है। इस राशि पर जीएसटी की वसूली अगल से तय की जाएगी। सरकार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

विधायक अभिजीत शाह और हेमंत कटारे ने शिकायत पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिखित में 443 करोड़ रुपए के जुर्माने की पुष्टि की।

संजय पाठक बड़े माइनिंग कारोबारी हैं। उनके पिता, स्वर्गीय सतेंद्र पाठक, दिग्विजय सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं। 2013 से पहले संजय पाठक कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन पार्टी की हार के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और दोबारा विधायक बने। उस समय चर्चा थी कि उन्होंने अपने माइनिंग कारोबार को बचाने के लिए भाजपा ज्वॉइन की थी। हाल ही में संजय पाठक की एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले दो साल से वे परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के 15 महीनों में भी उन्हें कई तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ी थीं। उनके इस बयान के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब वे भाजपा सरकार के भी निशाने पर हैं।

विधायक संजय पाठक से जुड़ी तीन खनन कंपनियों द्वारा स्वीकृति से अधिक खनन करने पर सरकार 443 करोड़ से अधिक की वसूली निकालने जा रही है। जीएसटी के बाद यह राशि और बढ़ सकती है। हालांकि आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन एवं निर्मला मिनरल्स ने इस मामले में अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनियों की ओर से कहा गया कि हम पिछले 70 वर्षों से खनिज का व्यापार कर रहे हैं। हमारी फर्म सीएल पाठक एंड संस को लगभग 115 वर्षों के माइनिंग के काम का अनुभव है। इतने सालों में फर्म पर रॉयल्टी या टैक्स चोरी की कोई शिकायत नहीं है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी खदान से कभी भी कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं हुआ और जितना भी मटेरियल खदानों से बिका, उस पर रॉयल्टी, सेल्स टैक्स व जीएसटी चुकाया गया है। पूर्व में इस मामले में एक जांच की गई थी, जिसमें जांच के बाद कोर्ट ने सभी आरोपों को तथ्यहीन पाते हुए विभागीय आदेश को निरस्त कर दिया था।

● अक्स ब्यूरो

अब होंगी राजनीतिक नियुक्तियां

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने 20 महीने के कार्यकाल में सुशासन और विकास की ऐसी मिसाल पेश की है कि वे देश के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। सत्ता, संगठन और संघ का जैसा समन्वय मप्र में देखने को मिल रहा है, वैसा अन्य किसी प्रदेश में नहीं है। इसको देखते हुए आलाकमान ने डॉ. मोहन यादव को फ्री हैंड कर दिया है कि वे अपनी पसंद से निगम-मंडलों में नेताओं को नियुक्त कर सकते हैं। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन के गठन के लिए भी हरी झंडी दे दी है।

दरअसल, गत दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिल्ली दौरे पर थे तो इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान आलाकमान ने उन्हें फ्री हैंड दिया है कि वे प्रदेश में अपने हिसाब से राजनीतिक जमावट कर सकते हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां इसी महीने की जा सकती हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि आलाकमान से मिले फ्री हैंड के बाद सत्ता-संगठन में तालमेल के लिए नई दिल्ली में मप्र के सांसदों की बैठक हुई। नई दिल्ली के मप्र भवन में संपन्न हुई इस बैठक की खास बात यह है कि इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद सहित लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद शामिल हुए। सूत्र बताते हैं कि बैठक में सभी ने एक सुर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की शासन व्यवस्था की प्रशंसा की और उनके नेतृत्व को सराहा।

सूत्र बताते है कि इस बैठक में क्षेत्रीय-सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की गई। इशारों ही इशारों में सबको साधने की कोशिश कर ली गई। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद वे गृहमंत्री अमित शाह के अलावा अन्य बड़े नेताओं से भी मिले। संगठन के नेताओं से भी उनकी चर्चा हुई। इसके बाद मप्र में भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद अब निगम-मंडल, बोर्ड और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता खुल गया है। ऐसे में जल्द ही कई पदों पर नई नियुक्तियों की घोषणा हो सकती है। दरअसल, पिछले दिनों ओबीसी आयोग के अध्यक्ष पद पर रामकृष्ण कुसमरिया की नियुक्ति हुई है। इसके बाद अब निगम-मंडल, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद अनुमोदित सूची में शामिल नामों की नियुक्तियों के आदेश जारी करेंगे। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्ति का खाका तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा है। इसमें पूर्व मंत्री, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और कुछ वर्तमान विधायकों को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य में निगम-मंडल, बोर्ड और आयोगों के लगभग तीन दर्जन से अधिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हैं। डॉ. मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले 45 निगम-मंडलों और बोर्डों में की गई पूर्ववर्ती नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। तब से यह पद रिक्त हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दिल्ली में मेल मुलाकात के बाद मप्र में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना बढ़ गई। इससे पहले मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद की दिल्ली यात्रा ने प्रदेश के निगम-मंडल, प्राधिकरण और आयोगों के दावेदारों की सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी में पदाधिकारी बनने की आस पाले नेताओं की भी बैचेनी बढ़ गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही निगम-मंडलों में नियुक्ति हो सकती है। प्रदेश में मोहन यादव सरकार को डेढ़ वर्ष से अधिक का समय होने जा रहा है, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। उधर, मंत्रिमंडल विस्तार का भी नेताओं को इंतजार है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जयंत मलैया, हरिशंकर खटीक, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को अपना नंबर आने की संभावना दिख रही है। इसमें क्षेत्रीय संतुलन साधने के हिसाब से कुछ पूर्व मंत्रियों को फिर मौका दिया जा सकता है।

● **नवीन रघुवंशी**

नई टीम में नए चेहरों को मिलेगा मौका

पार्टी की रणनीति है कि संगठन के कार्यों को पूर्णकालिक रूप से निभाने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाए, जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत है और जो संगठनात्मक कामकाज में सक्रिय हैं। इसी के तहत अब नए और कम चर्चित लेकिन प्रभावी चेहरों को प्रदेश टीम में स्थान मिल सकता है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि नई कार्यकारिणी में युवाओं, महिलाओं और सामाजिक दृष्टि से विविध प्रतिनिधित्व पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाजपा के सात मोर्चा संगठनों में से तीन की कमान वर्तमान में सांसदों के पास है और एक मोर्चा कैबिनेट मंत्री के जिम्मे है। सांसद बनने के बाद इन नेताओं की व्यस्तता बढ़ गई है, जिससे मोर्चों के कामकाज पर असर पड़ा है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष माया नारोलिया राज्यसभा सांसद बनने के बाद से सीमित सक्रियता में हैं। किसान मोर्चा के दर्शन चौधरी सांसद बन चुके हैं और ओबीसी मोर्चा के प्रमुख अब प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। खुद मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने मोर्चे की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध पार्टी से कर दिया है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पसंद माने जाते हैं। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि नई टीम में संघ की च्वाइस का भी ख्याल रखा जाएगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि प्रदेश भाजपा की नई टीम शीघ्र ही सामने आएगी और इस बार इस नई टीम में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता और जो नौजवान हैं, उनका संगम आपको देखने को मिलेगा।

अनुराग जैन को मिलेगा एक्सटेंशन?

सितंबर का महीना मप्र में प्रशासनिक हलचल वाला रहेगा। इस महीने में मप्र को नया प्रशासनिक मुखिया यानि मुख्य सचिव मिलने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके साथ ही इसी बैच के जेएन कंसोटिया भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या उन्हें सेवा विस्तार मिलेगा या किसी नए वरिष्ठ अधिकारी को शीर्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रशासनिक हलकों में इसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को पिछले वर्ष सितंबर में उस समय मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था, जब वे केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे। उनकी नियुक्ति को केंद्र की प्राथमिकता माना गया था। यही वजह है कि अब उनके संभावित सेवा विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्हें सेवावृद्धि मिलेगी या नहीं, इस पर फैसला जल्द होगा। यदि सरकार उन्हें रोकने का निर्णय करती है तो फिर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से सेवावृद्धि का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना होगा, जो अभी तक नहीं गया है।

दरअसल, हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को सेवानिवृत्ति के दिन ही एक साल का सेवा विस्तार दिया, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को तीन माह का विस्तार मिला। 3 माह का इसलिए कि उन्हें 4-5 वर्ष हो चुके हैं। हालांकि उप्र के मुख्य सचिव को सेवा विस्तार नहीं दिया गया। वहीं ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा को एक वर्ष का एक्सटेंशन मिला है।ऐसे में मप्र में मुख्य सचिव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यदि दूसरे विकल्प पर विचार किया जाता है तो फिर सबसे वरिष्ठ अधिकारी 1990 बैच के अपर मुख्य सचिव जल संसाधन राजेश कुमार राजौरा को अवसर दिया जा सकता है। इसके साथ ही वरिष्ठता क्रम में 1990 बैच की ही अलका उपाध्याय का नाम आता है। अलका उपाध्याय का कार्यकाल मई 2026 तक रहेगा। अगर 1990 बैच के अफसरों के नामों पर विचार नहीं होता है तो 1991 बैच के अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल भी कतार में है। उनकी छवि तेजतर्रार अधिकारियों में होती है। और ये 2018 में कांग्रेस की सरकार में भी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं। और भारत सरकार में भी इन्होंने लगभग 4 साल कांग्रेस के कार्यकाल में काम किया है। ये जनवरी 2027 में रिटायर होंगे। बता दें कि ये 1991 बैच के अनुक्रम में दूसरे नंबर के अधिकारी हैं। वहीं 1992 बैच के पंकज अग्रवाल की दावेदारी भी है। गौरतलब है कि पंकज अग्रवाल वर्तमान में केंद्र सरकार में ऊर्जा सचिव हैं। ये उन अफसरों में शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम से जानते हैं। यही नहीं ये नवंबर 2029 में रिटायर होंगे। तब तक आगामी विधानसभा, लोकसभा और सिंहस्थ भी संपन्न हो जाएगा। ऐसे में चुनावी जमावट को देखते हुए सरकार इनके नाम पर मुहर लगा सकती है। हालांकि पंकज अग्रवाल के लिए लंबा समय है। पूर्व में भी केएस शर्मा साढ़े तीन साल, राकेश साहनी 4 साल मुख्य सचिव रह चुके हैं। ऐसे में पंकज अग्रवाल जो इंदौर के रहने वाले हैं, उनकी दावेदारी मजबूत होने का कारण एक ये भी है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मप्र के अधिकारियों को प्राथमिकता से प्रदेश में नियुक्तियां देते हैं। ऐसा पूर्व में भी देखा गया है।

जेएन कंसोटिया भी होंगे सेवानिवृत्त

अनुराग जैन के साथ अगस्त में जेएन कंसोटिया भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कंसोटिया 12 अगस्त को 60 साल के हो गए हैं। जैन और कंसोटिया दोनों ही अधिकारियों ने 21 अगस्त 1989 को एक साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की थी और अब दोनों ही सेवा नियमों के अनुसार 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि सरकार जेएन कंसोटिया को रिटायरमेंट के बाद किसी बड़े पद से नवाज सकती है।

अनुराग जैन को सेवावृद्धि की वजह

मुख्य सचिव अनुराग जैन को सेवावृद्धि मिलने की संभावना की कई वजहे हैं। वे प्रधानमंत्री की गुडबुक में शामिल हैं। उन्होंने अपनी पदस्थापना के बाद जिस तरह प्रशासनिक लगाम कसी है, उससे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें खुश हैं। क्योंकि प्रदेश में उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जिसमें प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री ने इस मीट को गंभीरता से लिया था। क्योंकि अनुराग जैन ने दो दर्जन से अधिक सरकार की पॉलिसियां बना दी, जिससे आने वाले समय में राज्य को बहुत फायदा होने वाला है। वहीं उन्होंने अक्टूबर-नवंबर 2025 की मीटिंगों की तैयारियां भी कर ली हैं। साथ ही सिंहस्थ 2028 के लिए घाटों का निर्माण, नया रेलवे स्टेशन, अस्पताल और मूलभूत आवश्यकताओं को खूब गहराई से अध्ययन कर अमली जामा पहनाया है, ताकि प्रदेश में कुंभ की तरह भीड़ उमड़ने पर भी पब्लिक को तकलीफों का सामना न करना पड़े। हालांकि जैन की कसावट के कारण प्रशासनिक अमला दो धड़ों में बंट गया है। दरअसल, उन्होंने कर्त्तव्यनिष्ठ अफसरों पर अधिक भरोसा किया है। इसलिए कुछ अफसर सक्रिय अफसरों से अपने आपको अलग मान रहे हैं।

कई सीएस को मिल चुकी सेवावृद्धि

जब अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाया गया था, तब राज्य में नई सरकार बनी ही थी और उन्हें मुख्यमंत्री की पसंद के बजाय केंद्र से आए निर्देश के आधार पर चुना गया था। अब जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगभग 20 माह से पद पर हैं और प्रशासनिक ढांचे से पूरी तरह परिचित हो चुके हैं, ऐसे में वे अपनी प्राथमिकता के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। पिछले वर्षों में प्रदेश में कई मुख्य सचिवों को सेवा विस्तार मिल चुका है। इनमें आर परशुराम, बीपी सिंह, इकबाल सिंह बैंस और वीरा राणा शामिल हैं। वीरा राणा की सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन ही केंद्र से निर्देश आने के बाद अनुराग जैन की नियुक्ति की गई थी।

सूफिया और तन्वी जाएंगी दिल्ली

मप्र कैडर की दो महिला आईएएस अधिकारी जल्द ही प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाएंगी। इनमें एक हैं 2009 बैच की सूफिया फारूकी वली और दूसरी हैं 2010 बैच की तन्वी सुंदरियाल। जल्द ही मप्र सरकार इन्हें केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए अनुमति दे सकती है।

पोस्ट आईजी की, काम कर रहे डीआईजी का

राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से चार पुलिस अधीक्षकों को पदोन्नत कर डीआईजी बनाया और चार डीआईजी को आईजी के पद पर पदोन्नत किया। डीआईजी के पद पर पदोन्नत चारों अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर 7 माह बाद भी सरकार निर्णय नहीं ले पाई है। अधिकारियों का पदनाम तो बदल गया, पर काम वही कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। संगठित अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस पर हमले भी हो रहे हैं, इसके बाद भी सरकार 7 माह में पदस्थापना नहीं दे पाई है।

जिन्हें डीआईजी बनाया गया था, उनमें एसएसपी रेडियो विजय कुमार खत्री, एसपी धार मनोज कुमार सिंह, पुलिस मुख्यालय में एआईजी राकेश सिंह और विनीत जैन शामिल हैं। इसके बाद राजेश चंदेल और शचींद्र चौहान को पदोन्नत कर डीआईजी बनाया है। इनमें चंदेल को रीवा डीआईजी बना दिया गया है, पर चौहान को अभी उच्च पद पर पदास्थापना की प्रतीक्षा है। वह अभी 32वीं वाहिनी उज्जैन में सेनानी हैं। इसी तरह सचिन अतुलकर, कृष्णावेनी, कुमार सौरभ और जगत सिंह राजपूत को डीआइजी से आईजी के पद पदोन्नत किया गया था। इनमें जगत सिंह राजपूत को छोड़ सभी को नई जगह पदस्थापना मिल गई है। राजपूत पुलिस मुख्यालय में योजना शाखा में डीआईजी थे। उनका भी सिर्फ पदनाम बदला काम नहीं। वह अगस्त में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनमें कृष्णावेनी को छोड़ दें सचिन अतुलकर और कुमार सौरभ को जून में नई पदस्थापना मिली। दतिया एयरपोर्ट के उद्घाटन में आईजी सुशांत सक्सेना और एसपी वीरेंद्र मिश्रा के बीच कहासुनी के बाद इन दोनों अधिकारियों के अतिरिक्त कुमार सौरभ को हटाकर पुलिस मुख्यालय में आईजी और अतुलकर को सक्सेना की जगह चंबल रेंज का आईजी बनाया गया।

उधर, प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची कब आएगी, यह चर्चा में जोरों पर है। गौरतलब है कि पिछले 6 महीने से अधिक समय से प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के थोक तबादले होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हर बार कहा जा रहा है कि सूची बनकर तैयार है, लेकिन सूची कहां गुम हो गई, किसी को नहीं पता।

फरवरी 2026 में खत्म होगा रेरा अध्यक्ष का कार्यकाल

मप्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण यानि रेरा के अध्यक्ष अजीत प्रकाश श्रीवास्तव का कार्यकाल फरवरी 2026 में समाप्त होगा। ऐसे में

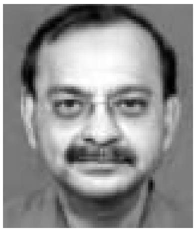

सरकार अगले रेरा अध्यक्ष के लिए अभी से खोज में जुटी हुई है। गौरतलब है कि रेरा के गठन के बाद एपी श्रीवास्तव उसके दूसरे अध्यक्ष हैं। पहला अध्यक्ष प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अंटोनी डिसा को बनाया गया था। यानि अब जो भी रेरा अध्यक्ष बनेगा, वह तीसरा होगा। गौरतलब है कि वर्तमान रेरा के चेयरमैन व पूर्व आईएएस अधिकारी एपी श्रीवास्तव का अभी तक का कार्यकाल विवादों में रहा है। शासन के पास उनके खिलाफ कई शिकायतें पहुंची हैं। इनमें नियम विरुद्ध काम करने, प्रोजेक्ट लटकाने और खुद जिस प्रोजेक्ट (आकृति गार्डन) में डुप्लेक्स बनाया, उसके प्रमोटर्स के 12 प्रोजेक्ट को रद्द करने का भी मामला शामिल है। इससे सरकार की छवि भी खराब हुई है।

नियामक आयोग 7 माह से खाली

मप्र विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन का पद पिछले 7 माह से खाली पड़ा है। आयोग के पूर्व चेयरमैन एसपीएस परिहार का कार्यकाल 2 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया था। उसी समय नए चेयरमैन पद पर नियुक्ति के लिए ऊर्जा विभाग ने समिति का गठन किया था। इस समिति में रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के साथ मुख्य सचिव और अध्यक्ष, विद्युत प्राधिकरण को शामिल किया गया है, जो पैनल का चयन करेंगे और इसके बाद नए चेयरमैन के नाम पर सरकार फैसला करेगी। इस पद के लिए पिछले महीनों में दावेदारों से आवेदन बुलाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और रिटायर्ड आईएएस अफसरों ने भी इसके लिए आवेदन किया है। लेकिन 7 माह बाद भी अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया है।

प्रज्ञा के भाई बनेंगे बिहार के डीजीपी

1991 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और डीजी होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के भाई प्रत्यय अमृत बिहार के डीजीपी बनेंगे। प्रत्यय अमृत भी 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

● राजेन्द्र आगाल

सिया मामले में सरकार ने दिया जवाब

स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (सिया) विवाद मामले में सरकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। कहा जा रहा है कि 2-3 हफ्ते में इसे लिस्टेड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार से जो जवाब मांगा गया था, उसे राज्य मूल्यांकन समिति के अफसरों ने बड़ी बारीकी से तैयार किया है और उसे सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है। गौरतलब है कि सिया के चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान की मनमानी के कारण विवाद इस कदर बढ़ गया है कि इससे सरकार की साख पर बन आई है। उधर, सिया चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान ने चुप्पी साध ली है। दरअसल, सिया के पास पर्यावरणीय अनुमति के लिए आवेदन पहुंचते हैं। प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी और एप्को डायरेक्टर उमा माहेश्वरी ने पर्यावरणीय अनुमति के लिए आए 700 आवेदनों में 450 को अनुमति देने की प्रक्रिया में शामिल किया। इनमें से 237 आवेदनों को पर्यावरणीय मंजूरियां गैर कानूनी तरीके से पिक एंड चूज पैटर्न पर जारी कर दी थीं। जिनमें करीब 200 अनुमतियां खदानों से संबंधित थीं। जो कि अपेक्स कमेटी होती है, राज्य मूल्यांकन समिति में टेक्नीकल एक्सपर्ट होते हैं। पर्यावरण अनुमति के इस झगड़े के बाद कमेटी की 5 बैठकें हो चुकी हैं।

आरक्षण-परिसीमन के लिए बनेगा आयोग!

आयोग ऐसे करेगा वार्डों का परिसीमन

आयोग प्रारूप अधिसूचना जारी करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलेक्टर) के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं से जानकारी प्राप्त करने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना जारी करेगा। वहीं आयोग प्रारूप अधिसूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के बाद जनता को आपत्तियां और सुझाव देने के लिए आमंत्रित करेगा। आयोग प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा। यदि आवश्यक हो तो संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई के लिए बुलाएगा या दस्तावेजों की जांच करेगा। आपत्तियों और सुझावों के निराकरण के बाद आयोग निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अंतिम आदेश जारी करेगा। आदेश का प्रकाशन, अंतिम आदेश को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और यह कानून की तरह लागू होगा। एक्ट के ड्राफ्ट के मुताबिक आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में 18 महीने पहले परिसीमन करवाएगा। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल जून 2027 में खत्म होगा। इस हिसाब से देखें तो आयोग को परिसीमन का काम ग्रामीण इलाकों में मार्च 2026 से शुरू करना होगा। इसके बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण और फिर पदों का आरक्षण होगा। नगरीय निकायों के लिए वार्डों की सीमा चुनाव से 2 महीने पहले पूरी किए जाने का बंधन होगा। वहीं इस बार नई जनगणना भी होने वाली है। यदि जनगणना के आंकड़े 2027 तक आ गए तो पदों का आरक्षण नए सिरे से किया जाएगा। यदि जनगणना नहीं हुई तो आरक्षण पुराने चक्रानुक्रम के मुताबिक ही होगा।

मप्र में 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में दो-दो हाथ करना पड़ेगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। मप्र में 2027 में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार से राज्य परिसीमन आयोग बनाने की सिफारिश की है। सरकार इस प्रस्ताव को मानती है तो नगर निगम के मेयर, नगर पालिका-परिषद के अध्यक्ष, पंचायत में पंच-सरपंच, जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और वार्डों के परिसीमन का जिम्मा आयोग का रहेगा। गौरतलब है कि 29 जुलाई को विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि अगले दो साल के भीतर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं।

अभी नगरीय निकायों के लिए ये काम नगरीय प्रशासन विभाग और पंचायतों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग करता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका ड्राफ्ट बनाकर सरकार को भेज दिया है। केंद्रीय परिसीमन आयोग को जो अधिकार मिले हैं, ठीक उसी तरह राज्य परिसीमन आयोग के अधिकार भी प्रस्तावित किए हैं। इसमें नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पुनर्गठन (री-स्ट्रक्चरिंग), परिसीमन (डिलिमिटेशन) और परिमार्जन (मॉडिफिकेशन) का जिक्र किया है। खास बात ये है कि आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। आयोग बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में नगरीय निकायों के लिए वार्डों का परिसीमन और पदों का आरक्षण नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग का जिम्मा है। जिला कलेक्टर के जरिए वार्डों का परिसीमन कराया जाता है। वहीं पंचायतों के लिए ये जिम्मा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है। मौजूदा व्यवस्था को लेकर सरकार पर पक्षपात के आरोप लगते हैं।

मप्र में साल 2022 में हुए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 2019 में होने थे। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिले के कलेक्टरों को परिसीमन के आदेश दिए थे। इसे लेकर भाजपा कोर्ट चली गई। भाजपा नेताओं का कहना था कि परिसीमन की अधिसूचना राज्यपाल की तरफ से जारी की जाती है, न कि सरकार की तरफ से। ये मामला कोर्ट में चला इसके बाद जब नगर पालिका और वार्डों का परिसीमन हुआ तो इस पर आपत्तियां लगा दी गईं। 2020 में कांग्रेस सरकार गिर गई, फिर भाजपा की सरकार आई तो निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का विवाद उठा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाने का आदेश दिया। तत्कालीन शिवराज सरकार ने रिव्यू पिटिशन दायर की। इसके बाद मप्र में 50 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय और पंचायत चुनाव हुए। इसी तरह साल 2014 में भोपाल के उपनगर कोलार नगर पालिका को नगर निगम में शामिल करने पर भी विवाद की स्थिति बनी थी। नगर पालिका को नगर निगम में शामिल किए जाने को लेकर कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इस विवाद के सुलझने के बाद ही सितंबर 2014 में कोलार को नगर निगम में शामिल किया गया था। इसके बाद 2019 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कोलार को फिर नगरपालिका बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस मुद्दे पर फिर सियासत हुई। हालांकि, बाद में सरकार ने ही इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया, मगर इस पूरी कवायद में चुनाव देरी से हुए।

एक्ट के प्रस्तावित ड्राफ्ट के मुताबिक मप्र राज्य परिसीमन आयोग केंद्रीय आयोग की तरह काम करेगा। केंद्रीय आयोग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करता है, उसी तरह राज्य का आयोग नगरीय निकायों और वार्डों की सीमा का निर्धारण करेगा। इसके साथ ही महापौर, अध्यक्ष और वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया भी आयोग की जिम्मेदारी होगी। प्रस्ताव के मुताबिक, राज्य परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य सचिव रैंक के किसी अफसर को बनाया जा सकेगा। इसके साथ सचिव स्तर से रिटायर तीन अफसर आयोग के सदस्य रहेंगे। वहीं नगरीय विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव भी सदस्य रहेंगे। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का रहेगा। सेवा शर्तें वही रहेंगी जो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की हैं। ड्राफ्ट में कहा गया है कि परिसीमन व आरक्षण से संबंधित आयोग के किसी भी फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। केंद्रीय आयोग के फैसले को भी कोर्ट में चुनौती नहीं देने का प्रावधान है।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

8 हजार गांवों में जल्द पहुंचेगा नल से जल

मप्र सरकार जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 8 हजार गांवों में नल से जल पहुंचाने के लिए 2,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत, इन गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, इन गावों के 7.5 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने के प्रस्ताव को जल्द की कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगते ही योजना से वंचित गांवों में काम शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि मप्र में जल जीवन मिशन योजना में शामिल 51 हजार से ज्यादा गांव शामिल हैं। जिनमें कुल घरों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख है। अब तक 78 लाख घरों में नल से जल की सप्लाई हो रही है। वहीं 34 लाख घरों में नल से जल की सप्लाई करना बाकी है।

जल जीवन मिशन के तहत सरकार प्रदेश के सभी 51 हजार से ज्यादा गांवों के हर एक घर में नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके तहत 8 हजार गांवों में पानी पहुंचाना शेष रह गया है।

गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के तहत, केंद्र सरकार 5,000 गांवों में नल कनेक्शन के लिए फंड देने से इनकार कर चुकी है, जिसके लिए 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसलिए, मप्र सरकार ने इन गांवों के लिए खुद ही 2,800 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। यह राशि 8 हजार गांवों के 7.5 लाख घरों में नल कनेक्शन स्थापित करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। यह योजना आत्मनिर्भर मप्र की परिकल्पना को साकार करने में भी मदद करेगी। मप्र में जल जीवन मिशन सवालों के घेरे में रहा है। विधानसभा सत्र में भी सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक मिशन में अनियमितता के मुद्दे उठाते रहे हैं। विधायकों की सबसे ज्यादा शिकायतें मिशन में व्याप्त भ्रष्टाचार, पाइप लाइन बिछाने के बाद सड़कों का रेस्टोरेशन नहीं किए जाने और ठेकेदारों द्वारा काम पूरा नहीं किए जाने को लेकर रही हैं।

प्रदेश में जल जीवन मिशन में छूटे करीब 8 हजार गांवों (मजरे-टोलों) के 7.5 लाख घरों में नलों से पानी की सप्लाई का रास्ता साफ हो गया है। इन गांवों में नलों से पानी पहुंचाने पर खर्च होने वाली पूरी राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इस पर करीब 2,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आएगा। दरअसल, जल जीवन मिशन में प्रदेश के एक-एक गांव के प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन प्रदेश में करीब 8 हजार मजरे-टोलों के 7.50 लाख घर जल जीवन मिशन में शामिल होने से छूट गए। विभाग ने जुलाई, 2024 में इन मजरे-टोलों में नल से पानी सप्लाई किए जाने को लेकर 2,800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा था।

केंद्र से 50 प्रतिशत राशि देने का अनुरोध किया गया था। योजना में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत राशि वहन की जाती है। प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद केंद्र सरकार ने राशि देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पीएचई के अफसरों ने इस मामले से मुख्य सचिव अनुराग जैन को अवगत कराया। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और इसे आगे बढ़ाने की सहमति दे दी। वित्त विभाग ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन का काम तेजी से चल रहा है। यहां जल जीवन मिशन में वर्तमान में एकल नल जल योजनाओं की संख्या 27 हजार 990 है। इनका 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। दिसंबर, 2025 तक एकल नल जल योजनाओं का काम पूरा करने का लक्ष्य तय है। प्रदेश में समूह नल जल योजनाओं की संख्या 147 है। इनमें 23 हजार से ज्यादा गांव शामिल हैं। मार्च, 2027 तक इनका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन में प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के करीब 1 करोड़ 12 लाख घरों तक एकल और समूह नल जल योजनाओं के जरिए नलों से जल पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में बुरहानपुर और निवाड़ी हर घर जल प्रमाणित जिले घोषित हो चुके हैं। इन दोनों जिलों के हर घर में नल से पानी की सप्लाई की जा रही है।

● **जितेंद्र तिवारी**

15 करोड़ से ज्यादा परिवारों को लाभ

बता दें कि देश के प्रत्येक गांव के हर घर में नल से पानी की सप्लाई के लिए केंद्र सरकार ने 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च किया था। इसकी डेडलाइन मार्च, 2024 रखी गई थी। यानी इस तारीख तक देश के ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में नल से पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जानी थी, लेकिन सरकार का यह मिशन पूरा नहीं हो सका। इस कारण जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार का दावा है कि देश में वर्ष 2019 से लेकर अब तक 15 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस जल जीवन मिशन का लाभ दिया गया है। पीएचई विभाग ने 9 हजार 205 एकल नलजल योजनाएं निर्मित कर उन्हें 6 हजार 963 ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया है। इन नल जल योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए एक एसओपी भी बनाई गई है। अब इन एकल नल जल योजनाओं में सोलर पैनल सोलर पम्प लगवाए जाने के निर्देश पंचायत विभाग ने दिए हैं और इसके लिए पंचायतों को प्रदाय राज्य वित्त आयोग की राशि उपयोग में लाने के लिए कहा गया है।

जनहितैषी मुद्दों को धार नहीं दे पाई कांग्रेस

मप्र विधानसभा का मानसून सत्र भले ही दो दिन पहले सिमट गया, लेकिन इस दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पार्टी न सदन में और न ही सदन के बाहर जनहितैषी मुद्दों को धार दे पाई। मानसून सत्र जितने दिन चला, उतने दिन कांग्रेस के विधायक रूप बदल-बदलकर विधानसभा आते रहे। इस दौरान कांग्रेस विधायक बड़े-बड़े मुद्दे लेकर विधानसभा तो पहुंचे, लेकिन मुद्दों से अधिक विधायकों की रूपरेखा चर्चा में रही। कांग्रेस विधायक कभी भैंस, कभी गिरगिट, कभी इंजेक्शन की मालाएं और कभी यूरिया की बोरियों के साथ तो कभी पुलिस की वर्दी में पहुंचे। जो मात्र प्रहसन बनकर रह गया।

विधानसभा के मानसून सत्र में सत्तापक्ष को घेरने कांग्रेस ने कमोबेश हर दिन नए-नए स्टंट किए। विधानसभा के इस सत्र में कमोबेश हर दिन कांग्रेस विधायक किसी नए अवतार में पहुंचे। हर दिन मीडिया के कैमरों के सामने नया स्टंट हुआ। विधानसभा में मानसून सत्र में बैठकों की शुरुआत के साथ हुए इन तमाशों को लेकर सत्तापक्ष का आरोप है कि कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका के साथ न्याय ही नहीं किया। जनता से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाने के बजाय पार्टी मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए बीन बजाती रही।

विधानसभा, सरकार और विपक्ष के लिए अपनी बात रखने का सबसे उपयुक्त मंच होता है। 10 दिवसीय सत्र होने के कारण विपक्ष के पास भरपूर अवसर था कि वह वजनदारी से सदन में मुद्दे उठाता और सरकार को मजबूर करता कि वह जवाब दे लेकिन इसके स्थान पर प्रदर्शन में उलझा रहा। सैन्य अधिकारी सोफिया कुरैशी के अपमान का विषय उठाकर जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह को तो घेरा, लेकिन परिवहन घोटाले के सौरभ शर्मा को भूल गया। विधानसभा सत्र के पहले कांग्रेस के विधायकों का धार के मांडू में नव संकल्प शिविर हुआ था। दो दिन सबने प्रदेश के मुद्दों पर खूब मंथन किया। इससे उम्मीद बंधी थी कि मानसून सत्र में विधायक दल का प्रदर्शन जबरदस्त रहेगा। मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा जाएगा लेकिन दल इसमें चूक गया। सदन के बाद प्रतिदिन प्रदर्शन करके मीडिया में सुर्खियां तो बटोरीं पर ऐसा कोई विषय सदन में खड़ा नहीं कर पाए, जिससे सरकार बैकफुट पर आ गई हो। एक बार यह अवसर अवश्य आया जब जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह को सदन में जवाब देने से रोक दिया। सेना के अपमान का मुद्दा उठाकर जमकर हंगामा किया। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे आदिवासी और कांग्रेस द्वारा सेना के अपमान का मुद्दा बनाकर प्रभाव कम कर दिया। आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे का मामला हो या फिर किसानों को खाद की किल्लत, कानून व्यवस्था हो या फिर अन्य विषय, कांग्रेस इन्हें तर्कपूर्ण ढंग से अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। कुछ मामलों में आसंदी के समक्ष नारेबाजी और बहिर्गमन तो किया पर परिवहन घोटाले को तो छुआ तक नहीं। जबकि पिछले सत्र में सौरभ शर्मा के बहाने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह सत्र केवल इस मायने में कांग्रेस के लिए सफल माना जा सकता है कि एकजुटता का जो संदेश देना चाहते थे, वह नजर आया।

उधर, सरकार इस मंच का भरपूर उपयोग कर विपक्ष की धार कुंद करने में सफल रही। लंबे समय बाद विधेयक चर्चा के बाद पारित हुए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्षों की जन्म जयंती मनाने की शुरुआत भी हुई। सत्तापक्ष के सदस्य अनुशासन में रहे। किसी ने भी अपनी ही सरकार को घेरने का काम नहीं किया। दरअसल, इसके पहले ऐसा कोई सत्र नहीं बीतता था, जब वे अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा ना करते हों। इसका लाभ कांग्रेस उठाती थी और ऐसे सदस्य के सुर में सुर मिलाकर भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास करती थी। जब कभी ऐसा अवसर भी आया तो मंत्रियों ने स्थिति को संभाला, उन्होंने अड़ने के स्थान पर बीच का रास्ता निकाला। मुख्यमंत्री ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। एक-एक करके 14 विधेयक पारित कराए। विधानसभा अध्यक्ष अनुभव के आधार पर सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के बीच संतुलन बनाने में सफल रहे। उन्होंने जहां सत्तापक्ष को प्रश्नों के सीधे उत्तर देने के लिए सचेत किया तो विपक्ष से भी मर्यादित आचरण करने की अपेक्षा की। ध्यानाकर्षण के माध्यम से विपक्ष को अपनी बात उठाने का अवसर दिया और नियम में ढील देकर लंबी चर्चा भी कराई।

● **अरविंद नारद**

न सदन, न सड़क पर दिख रहा कांग्रेस का दम

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को फिर से मजबूती से खड़ा करने की कवायद की जा रही है। लेकिन मप्र में इसका असर नहीं दिख रहा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद नेतृत्व में बदलाव किया गया। युवा हाथों में पार्टी की कमान सौंपी गई। उसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंकने की कवायद शुरू की, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने की सारी कवायद बेअसर साबित हो रही हैं। न सदन और न ही सड़क पर कांग्रेस का दम दिख रहा है। करीब डेढ़ साल पहले कांग्रेस ने जिस तरह संगठन में बदलाव किया था उससे लगा था कि कांग्रेस को मजबूत विपक्ष बनाने की कवायद सफल होगी, लेकिन कांग्रेस पहले से भी कमजोर दिखाई पड़ रही है। जनहित, अपराध, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर वह न सड़क पर मजबूती से उतर पा रही है, न विधानसभा में सरकार को घेरने में कामयाब दिखाई दी। बीते माह भोपाल आए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नरेंदर-सरेंडर का विवादित बयान दिया था, लेकिन उनके लौटते ही कांग्रेस पुराने ढर्रे पर आ गई। भाजपा के अंदरूनी समीकरण में स्पष्ट है कि डॉ. मोहन यादव विधायक दल से लेकर कैबिनेट तक पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जैसे मजबूत होने का प्रयास कर रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है।

शराब ठेकेदार खा गए 756 करोड़

756 करोड़ में होता भरपूर विकास

शराब ठेकेदारों ने सरकार के जो 756 करोड़ रुपए हजम कर लिए हैं, उससे प्रदेश में विकास की बयार आ जाती। इससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1500 किमी सड़क बन सकती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, 1 किमी सड़क बनाने की राष्ट्रीय औसत लागत करीब 55 से 65 लाख रुपए है। मप्र में ये लागत 50 से 55 लाख के करीब है। वहीं, इतने पैसों में शहर में 750 किमी सीमेंट और डामर की सड़क बन सकती है। 1 किमी लंबी सड़क बनाने में औसतन 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वहीं 756 करोड़ में मप्र में 7-8 नए जिला अस्पताल सभी आधुनिक उपकरण समेत तैयार हो सकते हैं। एक अस्पताल को बनाने की लागत करीब 100 करोड़ रुपए आती है। साथ ही 10 लाख रुपए की लागत से एक जनऔषधि केंद्र स्थापित होता है। ऐसे में इतने पैसों में 7500 जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जा सकती है। 756 करोड़ रुपए में 750 नए स्कूल बन सकते हैं या पुराने स्कूलों को सुधारा जा सकता है। एक स्कूल बिल्डिंग बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वहीं, 15 हजार स्कूलों में 15 हजार स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जा सकते हैं। एक स्मार्ट क्लासरूम बनाने में 5 लाख रुपए की लागत आती है। इतने पैसों में 5 लाख से ज्यादा गरीबों के पक्के मकान बन सकते हैं।

शराब ठेकेदारों ने मप्र सरकार को 756 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। तीन साल बीत चुके हैं, अभी तक सरकार ये रकम वसूल नहीं पाई है। ये खुलासा हुआ है, भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षा (कैग) की रिपोर्ट में। 31 मार्च 2022 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष की ये रिपोर्ट 31 जुलाई को विधानसभा में पेश की गई है। कैग ने फरवरी 2022 से अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान 52 में से 26 जिला आबकारी और आबकारी आयुक्त कार्यालय की जांच के दौरान ये रिपोर्ट तैयार की है। इसमें 2,569 केस में 756 करोड़ की हानि होने की तरफ इशारा किया गया है। इतने पैसे में सरकार 5 लाख गरीबों के पीएम आवास (ग्रामीण) बना सकती थी। वहीं, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 1500 किमी सड़कें बन सकती थीं।

कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि साल 2020-21 की शराब नीति को 1 अप्रैल से लागू किया गया, लेकिन चार महीने बाद अगस्त में इस नीति को कैंसिल कर दिया। इससे सरकार को 471.38 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। जो अभी तक नहीं मिला है। दरअसल, सरकार ने 16 जिलों में मौजूदा खुदरा लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे और 20 समूह लाइसेंस दिए थे। कैग ने पाया कि इस अवधि के दौरान 20 में से 11 लाइसेंसधारियों ने शराब नीति रद्द करने और उनकी सुरक्षा जमा राशि को वापस पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोविड महामारी के प्रतिबंधों के कारण शराब दुकानों का संचालन करने और लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में असमर्थता का हवाला दिया। लाइसेंस रद्द करने के बाद इनकी 241.50 करोड़ की राशि की वसूली 31 मार्च 2023 तक लंबित रही। आबकारी विभाग ने मई 2023 में अपने जवाब में कहा कि कोविड प्रतिबंधों के कारण फुटकर शराब दुकानें लगातार चालू नहीं रहीं। कई ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए और विभाग ने इन दुकानों का संचालन किया था। कैग ने विभाग के इस जवाब को नहीं माना क्योंकि जिन 18 जिलों में समूह लाइसेंस के बजाय फुटकर लाइसेंस की व्यवस्था लागू थी, वहां शराब ठेकेदारों ने पूरी राशि जमा की थी।

कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि विभाग के पास बोली लगाने की प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने का कोई प्रावधान नहीं था। सुरक्षा राशि जमा करने में विफलता के कारण कलेक्टर धार ने बदनावर और गंधवानी समूह के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। हालांकि, समूह से कोई वसूली नहीं की जा सकती है क्योंकि जिले के लाइसेंसधारी के नाम पर कोई चल-अचल संपत्ति नहीं थी। इसके कारण शासन को 9 करोड़ 58 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।

सरकार ने 2020-21 में प्रदेश के 52 जिलों में शराब बेचने के 329 लाइसेंस जारी किए थे। इससे 10 हजार 729 करोड़ रुपए का राजस्व मिलना था। 38 ठेकेदारों ने शराब दुकानों का संचालन करने से इनकार कर दिया था। जिनसे सरकार के खाते में 1 हजार 605 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा होनी थी। आबकारी विभाग ने इन दुकानों के नए सिरे से ठेके दिए, लेकिन 38 ठेकेदारों से 269 करोड़ रुपए वसूल करने थे, सरकार वो मार्च 2024 तक वसूल नहीं कर पाई। इनमें से 11 ठेकेदारों से ही 232 करोड़ रुपए वसूल होने थे जबकि 17 ठेकेदारों से 37 करोड़ रुपए की वसूली होनी थी। इनका मामला कोर्ट में लंबित था। वहीं रीवा जिले की सभी 71 दुकानों का ठेका एक समूह बिलासपुर के गोपाल एसोसिएट्स को दिया गया था। जिसमें 10 पार्टनर थे। एसोसिएट्स ने सुरक्षा निधि की राशि (51.38 करोड़) और अन्य दस्तावेज जमा नहीं किए। इस वजह से ठेका कैंसिल कर दिया गया। गोपाल एसोसिएट्स का एक पार्टनर निकुंज शिवहरे (मैसर्स वाइन ट्रेडर्स ग्वालियर) था। मेसर्स वाइन ट्रेडर्स ने मुरैना में ठेका लिया था। इसके एवज में 3.63 करोड़ की बैंक गारंटी जमा की थी। रीवा कलेक्टर ने शिवहरे से यह राशि जब्त करने के लिए मुरैना कलेक्टर को पत्र लिखा, लेकिन मुरैना जिला आबकारी अधिकारी ने यह राशि जब्त करने के बजाय ठेकेदार की देय राशि में समायोजित कर दी। तीन जिले- बैतूल, सिंगरौली और रीवा में जिला आबकारी अधिकारियों ने 6 खुदरा दुकानों से विदेशी और देशी शराब जब्त की। पंचनामा के अनुसार, दुकानों में शराब का कुल स्टॉक 1 लाख 05 हजार 268 था। जांच अधिकारियों ने अपने स्टॉक रजिस्टरों में केवल 14 हजार 42 बोतलें दर्ज कीं यानी 91 हजार 226 बोतलों को रिकॉर्ड में नहीं लिया। रिकॉर्ड में न आने वाली बोतलों की कीमत 1 करोड़ 69 लाख रुपए है।

● धर्मेंद्र कथूरिया

मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट रखी गई। इस रिपोर्ट में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह विभागों के अफसरों ने सरकार को अरबों रुपए की चपत लगाई है। यह पहली बार नहीं है, बल्कि हर बार जब भी कैग की रिपोर्ट पेश की जाती है, विभागीय अधिकारियों की अनियमितता सामने आती है, लेकिन विडंबना यह है कि मामला कागजों में ही दबकर रह जाता है।

अफसरों ने लगाई अरबों की चपत...

फाइल फोटो

कैग रिपोर्ट के मुताबिक खनन, वन और आबकारी विभागों में करीब 1000 करोड़ रुपए राजस्व नुकसान हुआ। 2021-22 में 11 जिलों के 45 माइनिंग लीजधारियों ने मंजूरी से अधिक खनन किया। शासन को इससे 630.30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आबकारी विभाग में करीब 10 करोड़ का नुकसान वित्तीय स्थिति का सही आंकलन न करने और जब्त शराब स्टॉक में गड़बड़ी से हुआ। वन विभाग में नियम विरूद्ध कार्यों से 65 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो पाई।

कैग रिपोर्ट में 31 मार्च 2024 को खत्म वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रबंधन पर सवाल उठाए गए हैं। सरकार ने 3.72 लाख करोड़ का बजट पारित किया, लेकिन खर्च सिर्फ 3.04 लाख करोड़ हुआ। इस तरह 67,926 करोड़ रुपए बिना खर्च हुए लैप्स हो गए। इसके बावजूद सरकार ने दो सप्लीमेंट्री बजट के जरिए 57,963 करोड़ रुपए और मांगे, जबकि जरूरत केवल 28,885 करोड़ की थी। यानी 29,029 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। 1,575 करोड़ रुपए का खर्च गलत तरीके से पूंजीगत खर्च में दिखाया गया। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 2021-22 में ठेकेदारों को 42.19 करोड़ रुपए का भुगतान बिना टैक्स कटौती के किया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और ठेकेदारों को अनैतिक लाभ मिला। 10.75 करोड़ रुपए बिना मंजूरी के खर्च हुए और ग्राम पंचायतें 34 करोड़ रुपए के खर्च का कोई प्रमाण नहीं दे सकीं, पर कार्रवाई नहीं हुई।

कैग की रिपोर्ट ने सरकार के किसान कल्याण के दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, किसानों के सहकारी विकास के लिए तय 5.31 करोड़ रुपए में से 90 प्रतिशत यानी 4.79 करोड़ रुपए अफसरों ने लग्जरी गाड़ियां खरीदने में खर्च कर दिए। ये खुलासा गत दिनों विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट बताती है कि राज्य और जिला स्तर पर खाद के अग्रिम भंडारण की समीक्षा का जिम्मा अफसरों को सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। इससे भंडारण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। भोपाल की अमरावत कला समिति में उर्वरक के स्टॉक में गड़बड़ी से सरकार को 14 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 2017 से 2022 के बीच किसानों को जिस खाद की जरूरत थी, वह नहीं, बल्कि जो उपलब्ध थी वही दे दी गई। पोषक तत्वों पर विचार नहीं किया गया। रिपोर्ट बताती है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत सैंपलिंग का पालन नहीं हुआ। 18 प्रयोगशालाओं की जरूरत थी, जबकि सिर्फ 6 प्रयोगशालाएं हैं। निरीक्षकों और स्टाफ की कमी से जांच समय पर नहीं हो सकी। मार्कफेड ने आपूर्तिकर्ताओं से 2019-22 के दौरान बिक्री दर में परिवर्तन किया, जिससे उसे 83.96 करोड़ रुपए में से 5.06 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 8 दिसंबर 2023 तक 15 जिलों के केंद्रीय सहकारी बैंकों से उर्वरक की लागत राशि 37.37 करोड़ रुपए बकाया थी। कैग ने हिदायत दी है कि सरकार को ब्याज कम करने के लिए ऋण अदायगी के लिए बकाया राशि वसूलना चाहिए। मप्र सरकार ने खाद की आवश्यकता का आंकलन करते समय सब्जियों और उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र को शामिल नहीं किया। गलत आंकलन और लक्ष्य के अनुरूप प्रस्ताव न आने के कारण मार्कफेड सहकारी क्षेत्र के लिए कॉम्प्लेक्स खाद की खरीदी नहीं कर सका। खरीफ 2019 से खरीफ 2022 के दौरान 1,19,350 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 4116 मीट्रिक टन खाद की खरीदी हो सकी।

कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि मप्र में

बिना सत्यापन अपात्र उद्योगों को जारी की सब्सिडी

रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी मानदंडों के उल्लंघन के कारण सब्सिडी का अधिक भुगतान हुआ है। डीटीआईसी से संबंधित 16 मामलों में औद्योगिक इकाइयों ने पी एंड एम की खरीद के लिए सब्सिडी का दावा करते समय, पी एंड एम लागत में जीएसटी घटक को गलत तरीके से शामिल किया। इनमें बुरहानपुर का एक, छिंदवाड़ा के तीन, देवास एक, ग्वालियर एक इंदौर दो, मंडीदीप एक और उज्जैन के सात इस तरह 16 प्रकरणों में डीटीआईसी सब्सिडी के दावों की सत्यता की जांच करने में विफल रहे और पी एंड एम खरीद लागत में जीएसटी को शामिल करने की अनुमति दी। इससे 1.54 करोड़ की पूंजी सब्सिडी की अधिक रिलीज भुगतान हुआ। इन प्रकरणों में शासन ने बताया कि जीएसटी राशि की पात्रता इकाई द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न के आधार पर तय की जाएगी। इस उत्तर को कैग ने स्वीकार्य नहीं किया क्योंकि इकाइयों द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी का विवरण पहले से ही डीटीआईसी के पास उपलब्ध था।

पर्यावरण मंजूरी की निर्धारित सीमा से अधिक अवैध खनन किए गए। संबंधित जिला खनन अधिकारियों ने अवैध रूप से निकाले गए खनिजों की कीमत के बाजार मूल्य का 10 गुना या रायल्टी का 20 गुना, जो भी अधिक हो वसूलने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप 712.77 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ। कैग की वर्ष 2022 की रिपोर्ट में खनिज विभाग में हुई गड़बड़ी सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि छिंदवाड़ा, सागर, सीहोर जिला खनन कार्यालयों में 10 खनन पट्टाधारकों के पास स्वीकृत खनन योजनाएं नहीं थीं, लेकिन वे अधिनियमों-नियमों और सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए खनन कर रहे थे। वहीं आबकारी विभाग के शराब दुकानों के लाइसेंस के आवंटन के दौरान आवेदक की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने का कोई प्रविधान नहीं था। इससे शासन को 9.58 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन बैंक गारंटियों को स्वीकार कर लिया गया जो अधिकृत लाइसेंसियों के नाम पर नहीं थीं, बैंक गारंटियों का सत्यापन भी नहीं किया। देशी शराब के भंडारगारों और बाटलिंग इकाइयों में न्यूनतम स्टॉक न रखने पर आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया। 2020-21 में सरेंडर किए गए लाइसेंसों की वसूली नहीं की गई। ऐसे 2,569 प्रकरणों में कुल 756.14 करोड़ रुपए राजस्व नुकसान हुआ।

प्रदेश में किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए खाद की आपूर्ति राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से की जाती है लेकिन न तो आवश्यकता का ठीक से आंकलन किया जाता है और न ही कोई वितरण व्यवस्था बनाई जाती है। यहां तक की अग्रिम खरीदी के लिए छूट का प्रस्ताव करने के बाद भी किसानों से अधिक दर पर विक्रय किया गया। किसानों से 10.50 करोड़ रुपए अधिक वसूले गए। दूसरी ओर अधिक दर पर खाद खरीदकर कम दर पर बेचा गया। इससे संघ को 4.38 करोड़ रुपए की हानि हुई। यह बात विधानसभा में प्रस्तुत कैग के प्रतिवेदन में सामने आई। कैग ने पाया कि खाद की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए भारत सरकार के जो पैमाने हैं, उसका पालन नहीं किया गया। पिछले वर्ष की खपत के आधार पर अनुमान लगाकर खरीफ सीजन के लिए 20 से 24 प्रतिशत और रबी के लिए 11 से 35 प्रतिशत के बीच वृद्धि की। सब्जियों और उद्यानिकी फसलों को इसमें शामिल ही नहीं किया। सर्वे में 250 किसानों से पता चला कि 56 प्रतिशत किसानों ने खाद का उपयोग किया। खाद का आंकलन कृषि विभाग ने 1 लाख 19 हजार टन का किया था लेकिन 4 हजार 116 टन ही खरीदा गया। 2019 में आपूर्तिकर्ताओं ने खरीफ अग्रिम अवधि के लिए डीएपी पर 1,100 और एमओपी पर 700 रुपए प्रति टन छूट का प्रस्ताव दिया। फरवरी 2019 में उर्वरक समन्वय समिति ने नुकसान की प्रतिपूर्ति के दावे के विरूद्ध छूट की राशि को समायोजित करने का निर्णय लिया लेकिन विक्रय दर में छूट पर विचार नहीं किया गया। इसके कारण किसानों के ऊपर 10.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

कैग की रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया है कि कई विभाग पूरा बजट भी खर्च नहीं कर पाए हैं। कैग ने अनुशंसा की है कि बजट अनुमानों को यथार्थवादी होना चाहिए। बचत और आधिक्य व्यय को कम करने कुशल नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए। कैग ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले विभिन्न योजनाओं में अनुपूरक राशि की आवश्यकता का आंकलन करना चाहिए। विधानसभा में प्रस्तुत राज्य वित्त को लेकर रिपोर्ट में सरकार के बजट को लेकर कई आपत्तियां उठाई गई। इसमें बताया गया कि वर्ष 2023-24 के 3 लाख 27 हजार करोड़ रुपए से अधिक के बजट में लगभग 68 हजार करोड़ रुपए का उपयोग ही नहीं हुआ। 58 हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक प्रविधान में से 29,098 करोड़ रुपए का अधिक प्रविधान किया गया। 1,575 करोड़ रुपए के राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय में दर्ज कर उसे अतिरिक्त व्यय बताया गया। रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया कि वर्ष 2023-24 में महिलाओं को सशक्त बनाने लाड़ली बहना योजना का क्रियान्वयन किया गया। इसके लिए बजट में 14,743 करोड़ रुपए का प्रविधान किया लेकिन यह पहल राजकोषीय व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। एनसीसी का सुदृढ़ीकरण, कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम, भवन निर्माण व इलेक्ट्रानिक-मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना में बजट नियंत्रण अधिकारी ने जानकारी ही एकत्र नहीं की। इस कारण 2,051 करोड़ व्यय नहीं हुए। 13,669 करोड़ का एकमुश्त प्रविधान तो किया पर 9,338 करोड़ रुपए अप्रयुक्त वहीं कृषि, जनजातीय कार्य, खेल, अजा कल्याण व राजस्व में 8,093 करोड़ का उपयोग नहीं हुआ।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

शराब कंपनियों और डिस्टिलरियों को 358 करोड़ लौटाए

मप्र के आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के अनुसार, मई 2019 से दिसंबर 2020 के बीच शराब निर्माता कंपनियों को बिना वैध दस्तावेजों के 358 करोड़ रुपए लौटाए गए। यह राशि एक्स-डिस्टिलरी प्राइस के नाम पर दी गई थी, लेकिन भुगतान प्रक्रिया में अनिवार्य औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं। सीएजी ने इस पूरे मामले में सघन जांच की सिफारिश करते हुए, संबंधित लाइसेंसधारकों और बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में प्रारंभिक स्तर पर ही जवाबदेही तय नहीं की गई, जिससे इतनी बड़ी राशि का गलत भुगतान संभव हो पाया। एक्स-डिस्टिलरी प्राइस वह रकम होती है जो सरकार शराब निर्माता कंपनियों को उनके उत्पाद गोदाम तक पहुंचाने के एवज में चुकाती है। शराब के ठेकेदार गोदामों से उत्पाद उठाते हैं और शुल्क अदा करते हैं। इसके बाद कंपनियां सरकार से एक्स-डिस्टिलरी प्राइस की वापसी की मांग करती हैं, जिसके लिए दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

बीओटी मॉडल की सड़कों से हो रही कमाई

मप्र में बोओटी (निर्माण परिचालन हस्तांतरण) मॉडल पर बनी सड़कें निवेशकों को मालामाल कर रही हैं। लागत से कई गुना अधिक वसूली के बाद भी निवेशकों को 25 से 30 साल तक टोल वसूली की छूट रहेगी। बीओटी मॉडल पर बनाई गई कुछ सड़कों से 550 फीसदी तक की वसूली हो चुकी है। फिर भी ये टोल 2033 से लेकर 2038 तक चलते रहेंगे। कुछ सड़कों से 2042 तक टोल वसूली होती रहेगी। भोपाल-देवास 141 किमी के चार लेन मार्ग पर ही 2009-10 से 30 जून 2025 तक 345 करोड़ की लागत के विरुद्ध 1889 करोड़ की टोल वसूली हो चुकी है। जो लागत का 500 फीसदी है। तीन प्रमुख फोरलेन मार्ग देवास-भोपाल, लेबड़-जावरा तथा जावरा-नयागांव की 1360 करोड़ की लागत के एवज में 30 जून 2025 तक 6522 करोड़ रुपए का टोल वसूला जा चुका है। यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने विधानसभा सत्र के दौरान विधायक प्रताप ग्रेवाल और पंकज उपाध्याय के सवालों के जवाब में दी थी।

लोक निर्माण मंत्री के अनुसार, लेबड़-जावरा तथा जावरा-नयागांव सड़क मार्ग पर टोल रोड पर लागत से कई गुना अधिक टोल वसूली होने पर टोल बंद करने के लिए पूर्व विधायक पारस सकलेचा की सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लंबित है। विधायकों ने अपने सवाल में पूछा कि न्यायालय में शासन याचिका का विरोध कर जनता के हित के स्थान पर कंसेशनर (निवेशक) के हित का संरक्षण क्यों कर रहा है? जिस पर मंत्री ने अनुबंध के नियमों का पालन कर न्यायालय में शासन का पक्ष रखा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक देवास-भोपाल रोड पर टोल से वर्ष 2021-22 में कलेक्शन 151 करोड़ हुआ जो कि 2024-25 में बढ़कर 253 करोड़ हो गया। इसमें 22 फीसदी तक वृद्धि हुई। इस अवधि में वाहन की संख्या वर्ष 2021-22 में 35,740,77 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 52,16,208 हो गई। 3 साल में वाहन की संख्या में 50 फीसदी तथा कलेक्शन में 70 फीसदी की वृद्धि हुई। वर्ष 2010-11 में वाहन की संख्या 26,83,488 तथा कलेक्शन 55 करोड़ था। 2010-11 की तुलना में 2024-25 में कलेक्शन 5 गुना हो गया।

इसी तरह जावरा-नयागांव टोल रोड पर वर्ष 2021-22 में कलेक्शन 172 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 252 करोड़ हो गया तथा जावरा-लेबड़ का कलेक्शन वर्ष 2021-22 में 147 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 234 करोड़ हो गया है। जून 2025 में देवास-भोपाल रोड पर 22.5 करोड़, जावरा-नयागांव मार्ग पर 23.33 करोड़ तथा लेबड़-जावरा पर 23.81 करोड़ टोल वसूली हुई। टोल रोड पर वाहन, कार, जीप की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। जून 2021 में भोपाल-देवास रोड पर 1,67,741 की तुलना में जून 2025 में 3,29,716 कार-जीप, बस 10,033 से 22,043, ट्रक 20,849 से 33,471 तथा मल्टी एक्सल ट्रक 36,757 से 54,768 हो गए। इसी तरह लेबड़-जावरा मार्ग पर भी गुजरने वाले वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जून 2021 में कार-जीप 95,170 से जून 2025 में बढ़कर 1,68,296, ट्रक 21,903 से 49,047 तथा मल्टी एक्सल ट्रक 59,852 से 92,257 हो गए हैं। जावरा-नयागांव सड़क मार्ग पर कार-जीप 1,64,150 से बढ़कर 3,28,447 ट्रक 21,811 से 36,895 तथा मल्टी एक्सल ट्रक 70,931 से बढ़कर 96,358 हो गए।

पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने बताया कि वर्ष 2022 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया था। उस समय भोपाल-देवास मार्ग पर टोल वसूली 330 प्रतिशत, लेबड़-जावरा मार्ग पर 200 प्रतिशत तथा जावरा-नयागांव मार्ग पर 425 प्रतिशत हो रही थी। आज यह वसूली क्रमशः चार गुना से 6 गुना बढ़ गई है। इन तथ्यों के आधार पर याचिका लगाई गई थी। न्यायालय में शासन ने हमारी याचिका का विरोध किया। बीओटी (निर्माण परिचालन हस्तांतरित) मॉडल के तहत एक निजी कंपनी सड़क का निर्माण करती है। फिर संचालन के जरिए लागत निकालती है। फिर सरकार को हस्तांतरित करती है। यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल है, जिसमें निजी कंपनी परियोजना के वित्तपोषण, निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी लेती है। कुछ समय बाद, सड़क का स्वामित्व और संचालन सरकार को सौंप दिया जाता है। इस मॉडल में सरकार को पैसा नहीं लगाना होता है।

● **लोकेश शर्मा**

सड़क निर्माण में 414 करोड़ का घोटाला

जनवरी में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने मप्र में ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए बिटुमिन खरीद में 414.94 करोड़ रुपए की संदिग्ध धोखाधड़ी की तरफ इशारा किया है। राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में बड़ी अनियमितताएं होने का आरोप लगाया था। 2021-22 से पीएमजीएसवाई गतिविधियों को कवर करने वाले एक ऑडिट पर सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि मप्र के 49 जिलों में 75 पीआईयू में से 71 में पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण में शामिल ठेकेदारों ने बिटुमिन खरीद के लिए कथित तौर पर फर्जी और डुप्लिकेट चालान जमा किए। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया, हमने 75 में से 71 पीआईयू और 51 में से 49 जिलों में पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण के लिए बिटुमेन की खरीद में 414.94 करोड़ रुपए की संदिग्ध धोखाधड़ी का पता लगाया है। ठेकेदारों ने सरकारी रिफाइनरियों के फर्जी चालान पेश किए।

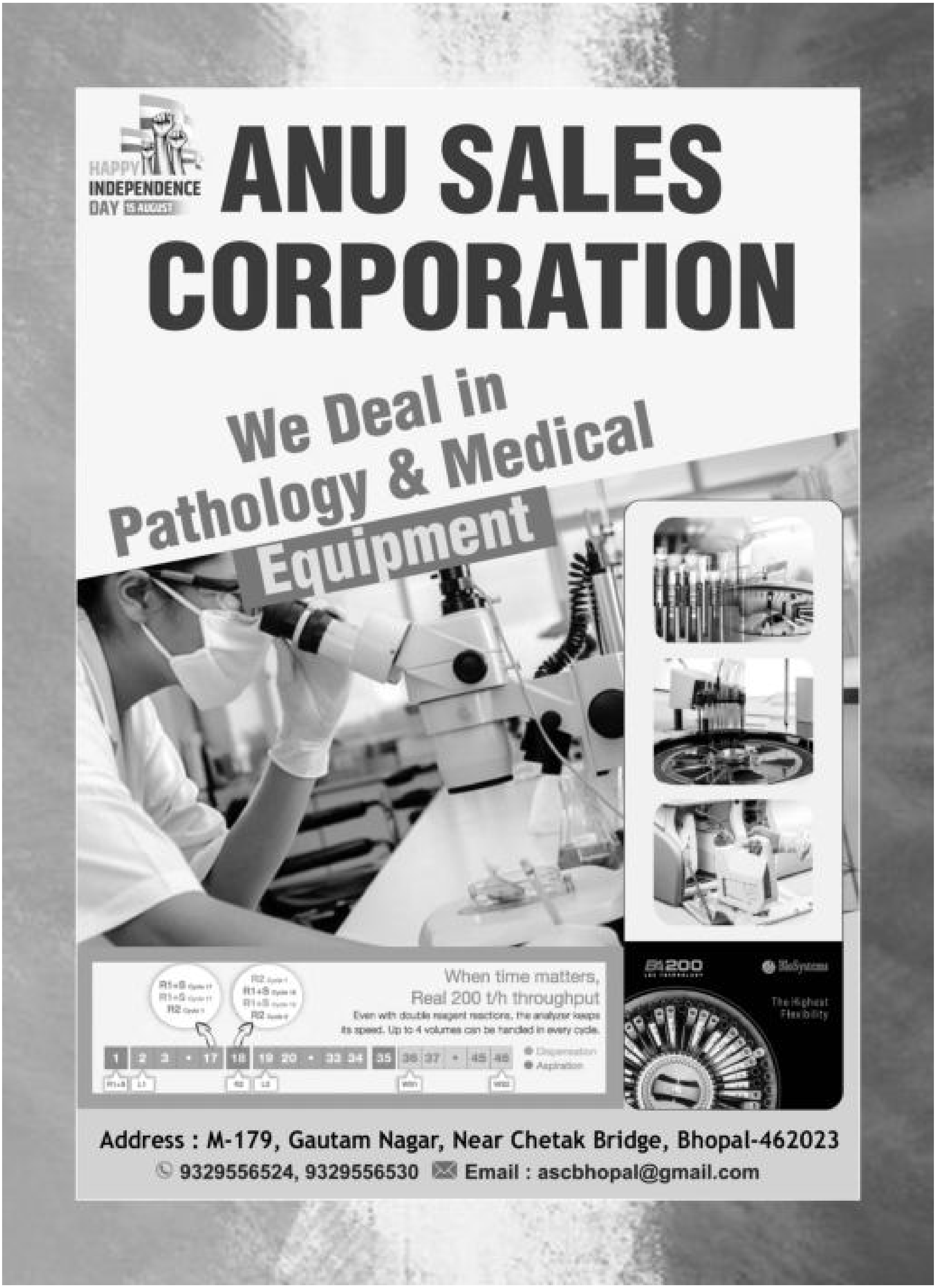
HAPPY INDEPENDENCE DAY 15 AUGUST
ANU SALES CORPORATION
We Deal in Pathology & Medical Equipment
When time matters, Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

मौसमी आपदाओं का कहर...

साल-दर-साल देश में मानसून के दौरान बाढ़, तूफान, बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शायद ही कोई ऐसा साल हो जब देश ने जलवायु से जुड़ी त्रासदी का सामना न किया हो। 2025 में भी उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने एक झटके में पूरे गांव को उजाड़ दिया। ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के सराज में भी देखने को मिला, जहां 30 जून 2025 की रात हुई भारी बारिश के बाद आई बाढ़, भूस्खलन ने कई जिंदगियों को निगल लिया। हिमालय नीति अभियान (एचएनए) द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक इस आपदा में सराज घाटी के करीब दो दर्जन गांव बाढ़-भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। ऐसा ही कुछ 2024 में केरल के वायनाड में देखने को मिला था, जब मानसून ने भारी तबाही मचाई थी। इन आपदाओं के बारे में 6 अगस्त 2025 को गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि पिछले सात महीनों में बारिश, तूफान, सूखा जैसी जलवायु से जुड़ी आपदाओं ने देश में 1,626 लोगों की जान ली है।

आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि कई राज्यों में मौसम से जुड़ी आपदाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या चौंकाने वाली रही है। आंकड़ों के मुताबिक इन आपदाओं में जहां जनवरी 2025 से जुलाई 2025 के बीच आंध्रप्रदेश में 343 लोगों की जान गई है। वहीं मप्र में यह गिनती 243 रिकॉर्ड की गई। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में 195 लोग जलवायु से मौसम-पानी से जुड़ी आपदाओं में जान गंवा चुके हैं। इसी तरह कर्नाटक (102) और बिहार (101) में भी मरने वालों का आंकड़ा 100 से अधिक है। वहीं केरल में अब तक 97 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

उत्तराखंड जिसने हाल ही में भारी तबाही का सामना किया है, वहां भी पिछले सात महीनों में 71 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक, केरल में 97, महाराष्ट्र में 90, राजस्थान में 79, उत्तराखंड में 71, गुजरात में 70, जम्मू-कश्मीर में 37, जबकि असम में 32 और उप्र में 23 लोगों की जान गई है। देखा जाए तो देशभर में चरम मौसमी घटनाओं में हुए 60 फीसदी से ज्यादा मौतें आंध्र प्रदेश, मप्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में रिकॉर्ड की गई हैं। ऐसा नहीं है कि इन आपदाओं में सिर्फ इंसानों ने अपनी जान गंवाई है। इसका किसानों और कृषि क्षेत्र पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले सात महीनों में इन आपदाओं में 52,367 मवेशी भी मारे गए हैं। इसके साथ ही करीब 1,57,818 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है। यदि सिर्फ उत्तराखंड की बात करें तो पिछले सात महीनों में आई जलवायु आपदओं मे 9.47 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 67 मवेशी भी मारे गए हैं।

देश में फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ है, जहां 91,429 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह असम में यह आंकड़ा 30474.89, कर्नाटक में 20245, मेघालय में 6372.30 और पंजाब 3569.11 रिकॉर्ड किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 23,992 पशुधन मारे गए हैं। वहीं असम में 14,269, जम्मू-कश्मीर में 11,067, मप्र में 1,625 और गुजरात में 698 मवेशी मारे गए हैं। इन सभी राज्यों में बड़ी संख्या में मवेशी मारे गए हैं। यह स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि इससे किसानों पर गहरा असर पड़ा है। हालांकि मंत्रालय ने इस बात की भी पुष्टि की है कि यह आंकड़े अस्थाई हैं। लेकिन देखा जाए तो यह आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते हैं कि जलवायु से जुड़ी आपदाओं के प्रति भारत में स्थिति लगातार नाजुक होती जा रही है। मंत्रालय ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट कहा कि वह आपदाओं से जुड़े आंकड़े खुद इकट्ठे नहीं करता, बल्कि उसके लिए राज्यों पर निर्भर रहता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने जानकारी दी है कि जमीनी स्तर पर राहत सामग्री के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। वहीं केंद्र, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। इस सवाल के जवाब में कि क्या लोगों को वज्रपात और तूफान की सही चेतावनी मिल रही है, सरकार ने बताया कि, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली जैसे खतरों की निगरानी, पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए एक अत्याधुनिक प्रणाली बनाई है। यह प्रणाली सैटेलाइट, रडार, जमीनी उपकरणों और आकाशीय बिजली को पकड़ने वाले नेटवर्क के जरिए जिला और शहरी स्तर पर सटीक जानकारी देती है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

धराली तबाही का रहस्य...

धराली की आपदा ने हमें एक बार फिर चेतावनी दी है कि हिमालय जैसे संवेदनशील इलाकों में जलवायु परिवर्तन और मानवीय गलतियां मिलकर तबाही मचा रही हैं। बादल फटने का पैटर्न बदल रहा है। ऊंचे इलाकों में होने वाली ऐसी घटनाएं अब नीचे बसे गांवों को प्रभावित कर रही हैं। धराली की 54 करोड़ साल पुरानी ढीली मिट्टी और खड़ी ढलानें इसे और जोखिम में डालती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शायद 3,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर बादल फटा हो, जहां मौसम स्टेशन नहीं हैं। ऐसी ऊंचाई पर होने वाली बारिश नीचे की ओर बहकर भूस्खलन या मलबे का सैलाब ला सकती है, जैसा धराली में हुआ। हिमालय में बादल फटने की घटनाएं आमतौर पर 1,000 से 2,500 मीटर की ऊंचाई के बीच होती हैं, लेकिन 3,000 मीटर से ऊपर ये कम देखी जाती हैं। इसका कारण है हिमालय की खास मौसमी परिस्थितियां और ओरोग्राफिक प्रभाव। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें पहाड़ों की वजह से हवा और बारिश का पैटर्न बनता है। जब नम और गर्म हवा हिमालय की खड़ी ढलानों से टकराती है, तो वह तेजी से ऊपर उठती है। ऊपर जाकर हवा ठंडी होती है। उसमें मौजूद नमी जमा होकर भारी बारिश का रूप ले लेती है। यही बादल फटने की घटनाओं का कारण बनता है। लेकिन 3,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर हवा ठंडी और शुष्क हो जाती है। नमी की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए वहां भारी बारिश या बादल फटने की संभावना कम होती है। इसीलिए ऐसी घटनाएं ऊंचे इलाकों में दुर्लभ हैं।

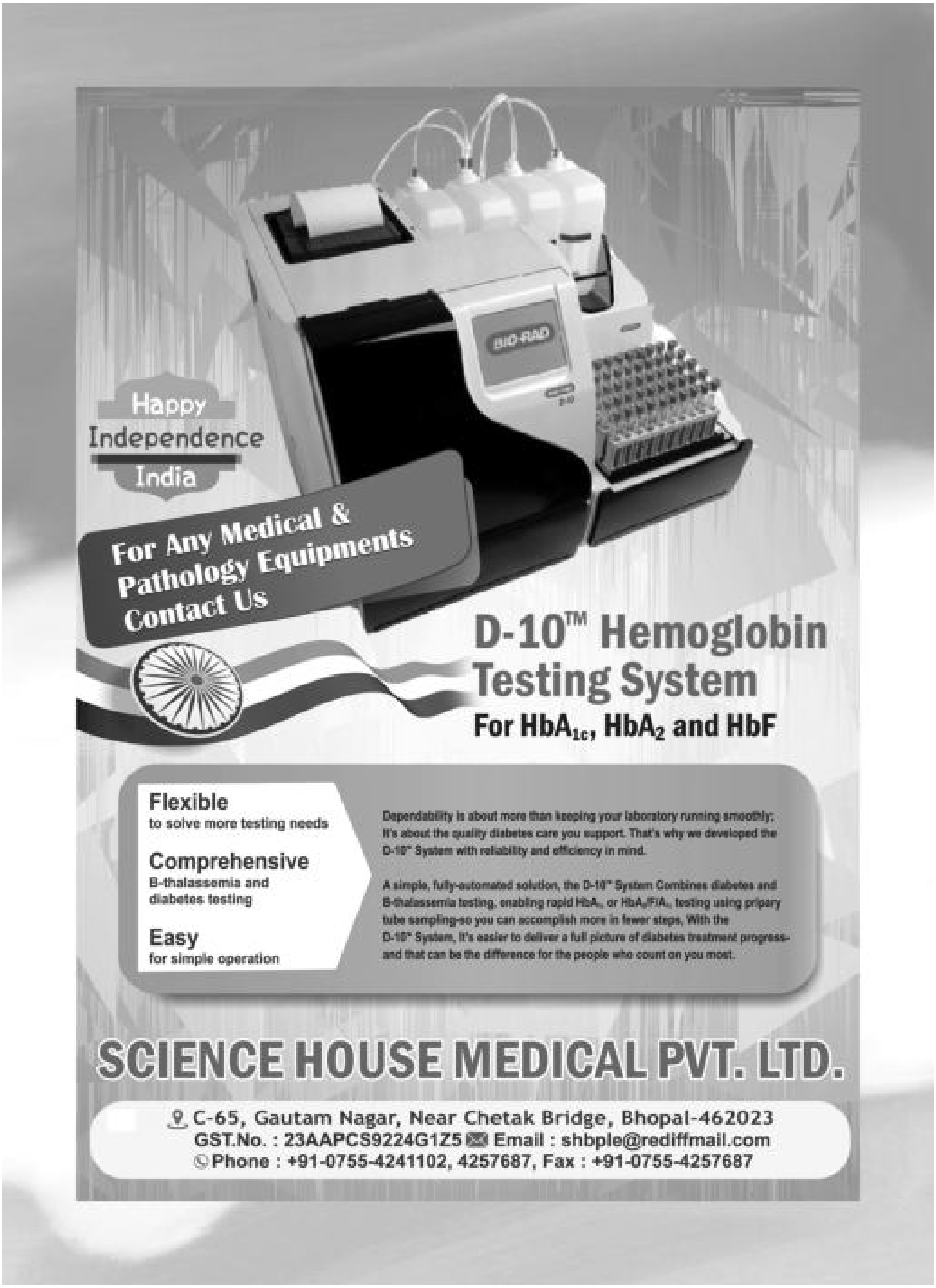
Happy
Independence
India
For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us
D-10™ Hemoglobin
Testing System
For HbA1c, HbA2 and HbF
Flexible
to solve more testing needs
Comprehensive
B-thalassemia and
diabetes testing
Easy
for simple operation
Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.
A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA1c or HbA2/F/A1c testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.
SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.
C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

उत्साह व उमंग के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस

मप्र में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि जो जैसा है, उसे वैसा ही जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों को दीपावली के बाद 1500 रुपए देने के अपनी घोषणा को भी दोहराया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में करारा जवाब दिया है। इस अभियान ने पूरी दुनिया के सामने भारत की शक्ति और सामर्थ्य को प्रमाणित किया। देश की एकता और अखंडता पर बुरी नजर डालने वालों को स्पष्ट संदेश है कि वे जिस भाषा में समझते हैं, हम उसी भाषा में जवाब देंगे। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए जो कहना होगा, हम कहेंगे। देश के वीर सपूतों को शत-शत नमन।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मार्ग केवल स्वदेशी को अपनाकर ही प्रशस्त होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1.52 लाख रुपए हो गई है, जो पहले 1.39 लाख थी। राज्य सरकार 1 लाख पदों पर भर्ती कर रही है और अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हवाई संपर्क के लिए बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है और सिंचाई क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश के 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को 10 हजार से 50 हजार रुपए तक की ऋण सहायता दी गई है।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क (धार) से कपड़ा उद्योग को खेती से लेकर निर्यात तक नई दिशा मिलेगी। मप्र देश का सबसे बड़ा प्रमाणित जैविक खेती क्षेत्र है और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 14 लाख किसानों को 1,383 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि जन विश्वास अधिनियम लागू करने के बाद प्रदेश ने जन विश्वास विधेयक अधिसूचित किया है। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में भी मप्र देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं में प्रति गौ राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत डेढ़ साल में किसानों को कुल 46,700 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को स्थायी बिजली कनेक्शन 5 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लक्ष्य है कि 3 वर्षों में 32 लाख सोलर पंप देकर किसानों को बिजली बिलों से मुक्त किया जाए।

● प्रवीण सक्सेना

अतुल्य मध्यप्रदेश बना पर्यटकों की पहली पसंद

पर्यटन की दृष्टि से मध्यप्रदेश एक समृद्ध और विविधतापूर्ण राज्य है। इसकी सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरें, प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीव संपदा का आकर्षण अतुलनीय मध्यप्रदेश के रूप में पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है। प्रदेश ने वर्ष 2024 में पर्यटन के क्षेत्र में कीर्तिमान रचा है। मध्यप्रदेश में रिकॉर्ड 13 करोड़ 41 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ। यह उपलब्धि वर्ष 2023 की तुलना में 19.6 प्रतिशत, 2019 से लगभग 50.6 प्रतिशत और 2020 की तुलना में 526 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है।

पर्यटन की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत का एक समृद्ध और विविधतापूर्ण राज्य है। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा, ऐतिहासिक धरोहरें और वन्यजीव विविधता, पर्यटकों को एक सम्पूर्ण अनुभव प्रदान करती हैं। वर्ष 2024 में 13 करोड़ 41 लाख पर्यटकों का आगमन इस बात का प्रमाण है कि मध्यप्रदेश देश ही नहीं, वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर भी मजबूती से उभर रहा है। यह उपलब्धि शासन की दूरदर्शी नीतियों, आधारभूत ढांचे के विकास और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी का प्रतिफल है।

विदेशी पर्यटकों का आगमन

वर्ष 2024 में 1.67 लाख विदेशी पर्यटकों ने भी मध्यप्रदेश की सैर की। खजुराहो में 33 हजार 131, ग्वालियर में 10 हजार 823 और ओरछा में 13 हजार 960 विदेशी पर्यटक पहुंचे। शहरी पर्यटन में भी विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसमें इंदौर में 9,964 और भोपाल में 1,522 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। बांधवगढ़ में 29 हजार 192, कान्हा में 19 हजार 148, पन्ना में 12 हजार 762 और पेंच में 11 हजार 272 विदेशी पर्यटक आए, जो मध्यप्रदेश की वैश्विक अपील को दर्शाता है।

धार्मिक पर्यटन

प्रदेश के धार्मिक स्थलों ने वर्ष 2024 में 10.7 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित किया, जो वर्ष 2023 की तुलना में 21.9 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश के शीर्ष 10 पर्यटन स्थलों में से 6 धार्मिक स्थल शामिल हैं। उज्जैन 7.32 करोड़ पर्यटकों के साथ इस सूची में सबसे आगे रहा, जो वर्ष 2023 के 5.28 करोड़ की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक है। चित्रकूट में भी 1 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जो वर्ष 2023 के 90 लाख की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है। मैहर में 1.33 करोड़, अमरकंटक में 40 लाख, सलकनपुर में 26 लाख और ओंकारेश्वर में 24 लाख पर्यटक पहुंचे। महाकाल लोक, ओंकारेश्वर महालोक, श्रीराम वनगमन पथ, देवी लोक, राजा राम लोक, हनुमान जैसी परियोजनाओं ने धार्मिक पर्यटन को आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।

विरासत पर्यटन

मध्यप्रदेश की समृद्ध विरासत ने 2024 में 80 लाख से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया, जो 2023 के 64 लाख की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ग्वालियर में पर्यटकों की संख्या में 3 गुना वृद्धि देखी गई, जहां 9 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे, जो 2023 की तुलना में 3.69 लाख की उल्लेखनीय वृद्धि है। खजुराहो (4.89 लाख), भोजपुर (35.91 लाख) और महेश्वर (13.53 लाख) में भी पर्यटकों ने इन समृद्ध विरासतों का आनंद लिया। यूनेस्को ने हाल ही में भोजपुर को अपनी टेंटेटिव सूची में शामिल किया है और ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता दी है। मध्यप्रदेश में अब 3 स्थायी और 15 टेंटेटिव सूची में कुल 18 यूनेस्को धरोहरें हैं। स्थायी सूची में खजुराहो के मंदिर समूह, भीमबेटका की गुफाएं और सांची स्तूप शामिल हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख, चौसठ योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, बुंदेला शासकों के महल और किले, ग्वालियर किला, बुरहानपुर का खूनी भंडारा, चंबल घाटी के शैल कला स्थल, भोजपुर का भोजेश्वर महादेव मंदिर, मंडला स्थित राम नगर के गोंड स्मारक, धमनार का ऐतिहासिक समूह, मांडू के स्मारकों का समूह, ओरछा का ऐतिहासिक समूह, नर्मदा घाटी में भेड़ाघाट-लमेटाघाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और चंदेरी टेंटेटिव लिस्ट में हैं।

वन्यजीव पर्यटन

टाइगर, लेपर्ड और घड़ियाल स्टेट के रूप में पहचाने जाने वाला मध्यप्रदेश टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, चीता स्टेट और वल्चर स्टेट के रूप में जाना जाता है, जिसमें देश का सबसे अधिक वन क्षेत्र है। राज्य में 12 राष्ट्रीय उद्यान, 25 वन्यजीव अभयारण्य और 9 टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा (2.48 लाख), पेंच (1.92 लाख), बांधवगढ़ (1.94 लाख), पन्ना (3.85 लाख) और मढ़ई (4.34 लाख) जैसे प्रमुख वन्यजीव स्थलों पर पर्यटकों का आगमन हुआ। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीतों की पुनर्स्थापना परियोजना ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है।

– फीचर

ग्रामीण पर्यटन : संस्कृति और आतिथ्य का जीवंत अनुभव

मध्यप्रदेश में ग्रामीण पर्यटन ने स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 63 पर्यटन ग्राम विकसित किए गए हैं। प्रदेश में 470 से अधिक होमस्टे का निर्माण किया गया है, जिनमें अब तक 24 हजार से अधिक अतिथि स्थानीय संस्कृति और खानपान का अनुभव ले चुके हैं। पचमढ़ी, कान्हा और अमरकंटक जैसे क्षेत्रों के आसपास के गांवों में होम स्टे सुविधाएं पर्यटकों के लिए अद्भुत अनुभव बन गई हैं। चंदेरी में भारत के पहले हैंडलूम गांव प्राणपुर ने स्थानीय शिल्पकारों को वैश्विक पहचान दिलाई है। आदिवासी समुदायों की कला जैसे गोंड, भील पेंटिंग और माड़ना आर्ट पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे शहर अपनी आधुनिकता, स्वच्छता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2024 में इंदौर में 1.02 करोड़, भोपाल में 22 लाख और जबलपुर में 23 लाख पर्यटक पहुंचे। इंदौर ने 7वीं बार स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में पहला स्थान हासिल किया है, जो इसे एक स्वच्छ और स्मार्ट पर्यटन गंतव्य बनाता है। मध्यप्रदेश ने वर्ष 2024 में पर्यटन के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश और दुनिया के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाई है। धार्मिक आस्था से लेकर ऐतिहासिक विरासत, वन्यजीव रोमांच से लेकर प्राकृतिक सौंदर्य, ग्रामीण आत्मीयता से लेकर शहरी आधुनिकता और फिल्मसिटी आकर्षण तक अतुलनीय मध्यप्रदेश ने हर पर्यटक को एक नया अनुभव दिया है। प्रदेश में 13.41 करोड़ पर्यटकों का आगमन इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में पर्यटन न केवल तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि सतत् विकास और समावेशिता के नए प्रतिमान भी स्थापित कर रहा है।

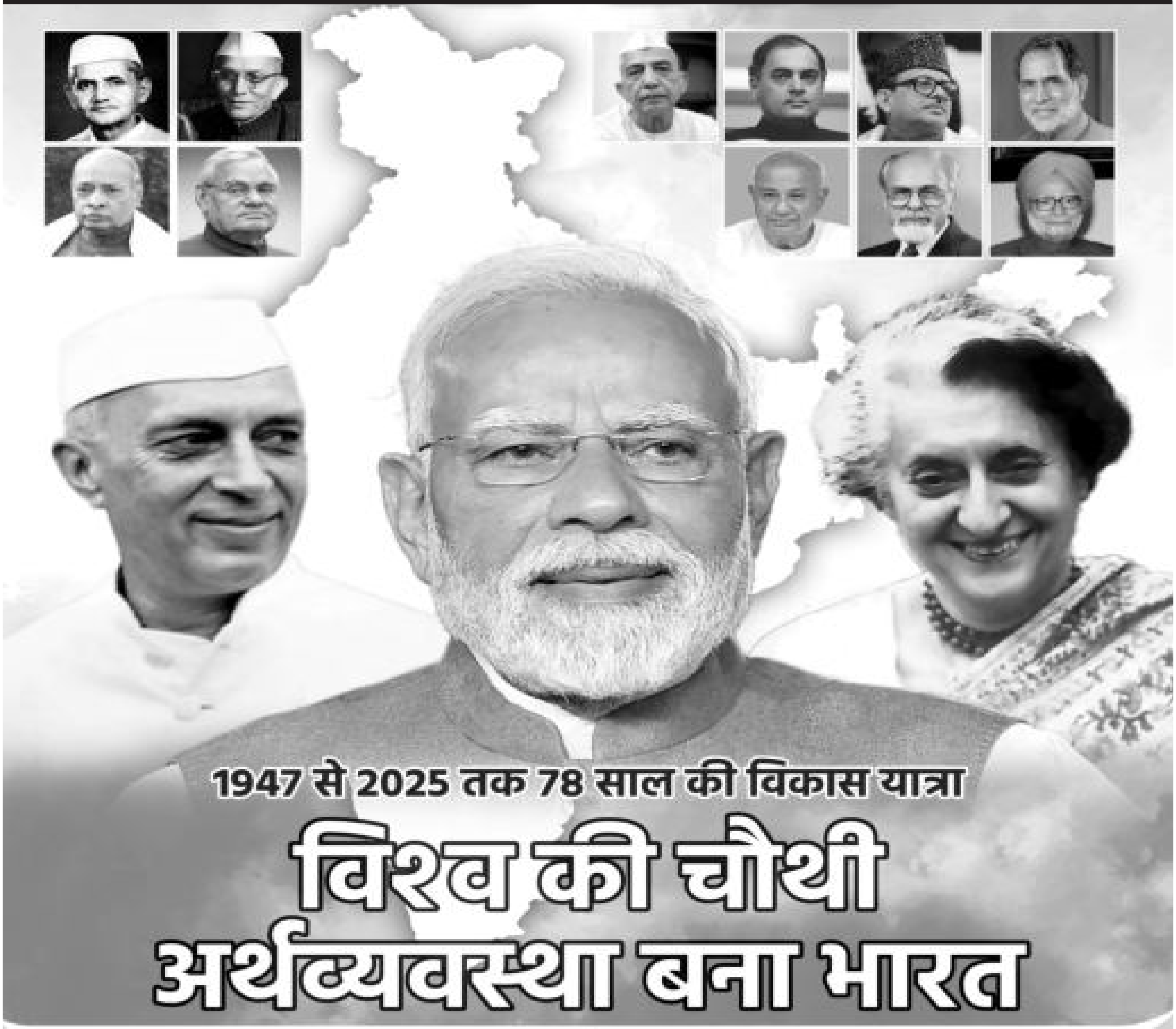

एक गरीब मुल्क से आज हिंदुस्तान बन गया है वैश्विक आर्थिक शक्ति

पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक 14 प्रधानमंत्रियों का अमूल्य योगदान

15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तब भारत की तुलना एक गरीब देश से होती थी। लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विकास की जो नींव रखी थी, उस पर अन्य प्रधानमंत्रियों ने विकास की ऐसी इमारत खड़ी कर दी है, जिससे आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। आजादी के बाद से भारत में सरकारें बदलीं, प्रधानमंत्री बदले, लेकिन विकास का मिशन निरंतर जारी रहा। यही कारण है कि एक गरीब मुल्क से आज भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है।

● राजेंद्र आगाल

आज भारत को आजाद हुए 78 साल पूरे हो गए हैं। और देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह देश के लिए अत्यंत सुखद अवसर है कि देश आज हर मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। आज देश की 140 करोड़ की जनता इसको लेकर दृढ़ संकल्पित है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। जब हम आजाद हुए थे तब देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी। 1951 में देश की पहली जनगणना हुई। उस वक्त हमारी आबादी 36 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा थी। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी, तब आबादी बढ़कर 121 करोड़ के पार पहुंच गई। हालांकि, आधार बनाने वाली संस्था यूआईडीएआई ने जुलाई 2025 तक देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान लगाया है। यानि आज हम आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत होने के साथ ही विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गए हैं।

15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तब टेक्नोलॉजी के नाम पर हमारे पास बहुत कम चीजें थीं। न इंटरनेट था, न मोबाइल, न टीवी, न सैटेलाइट और ना ही कम्प्यूटर। लेकिन आज 2025 में जब हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तब भारत एक टेक्नोलॉजी पॉवरहाउस बन चुका है। एक ऐसा देश जो अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाता है, स्पेस में सैटेलाइट भेजता है, और दुनिया को भी नई राह दिखा रहा है। 78 साल में आम आदमी की कमाई भी बढ़ी है। 1950-51 में देश में एक आदमी की सालाना कमाई 265 रुपए थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम काफी कम है। आज 265 रुपए में महीनेभर का मोबाइल डेटा प्लान भी नहीं आता, लेकिन उस वक्त एक आदमी की सालभर की कमाई इतनी ही थी। आजादी के बाद से अब तक देश में प्रति व्यक्ति सालाना कमाई सैकड़ों गुना बढ़ गई है। अनुमान के मुताबिक, आजादी के वक्त देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो उस वक्त की आबादी का 80 प्रतिशत होता है। हमारे देश में 1956 के बाद से गरीबी की संख्या का हिसाब-किताब रखा जाने लगा है। बीएस मिन्हास आयोग ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें अनुमान लगाया था कि 1956-57 में देश के 21.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। गरीबी रेखा के सबसे ताजा आंकड़े 2011-12 के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक, देश की 26.9 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। यानी, उस समय तक देश की 22 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती थी। गरीब कौन होगा? इसकी परिभाषा भी सरकार ने तय कर रखी है। इसके मुताबिक, अगर शहर में रहने वाला व्यक्ति हर महीने 1000 रुपए से ज्यादा कमा रहा है और गांव में रहने वाले व्यक्ति की हर महीने की कमाई 816 रुपए से ज्यादा है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा।

ऐसे बढ़ी हमारी अर्थव्यवस्था

किसी भी देश की आर्थिक सेहत कैसी है? इसको जानने का पैमाना है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए थे, तब दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत से ज्यादा थी। लेकिन जब वो छोड़कर गए तो ये हिस्सेदारी घटकर 3 प्रतिशत पर आ गई। आजादी के बाद से अब तक हमारी जीडीपी 50 गुना से ज्यादा बढ़ी है। 1950-51 में हमारी जीडीपी 4.96 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2024-25 में 167 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका कारण ये था कि हमारे देश में हर घर में सोना हुआ करता था। आज भी दुनियाभर में सबसे ज्यादा सोना भारतीय घरों में ही है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार पहुंच गई है, लेकिन जब हम आजाद हुए थे, तब 10 ग्राम सोने की कीमत 90 रुपए भी नहीं

विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत

भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आर्थिक विकास की दौड़ में तेज रफ्तार से दौड़ रहा भारत कुछ ही सालों में दुनिया की मौजूदा तीसरी बड़ी इकोनॉमी जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। ये आंकलन देश की प्रमुख संस्था नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने दी है। दुनिया की प्रमुख आर्थिक संस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कहा है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 4.19 लाख करोड़ डॉलर (4.19 ट्रिलियन डॉलर) की हो गई है। इससे भारत जापान से आगे निकल गया है। सवाल उठता है कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि उस देश की आर्थिक ताकत और उत्पादन क्षमता दुनिया के बाकी देशों की तुलना में तीसरे स्थान पर है। इसे मुख्य रूप से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के आधार पर मापा जाता है। नीति आयोग और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बयान का भारत के संदर्भ में यह मतलब है कि वर्ष के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। गौरतलब है कुछ महीने पहले भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, और अब वह जापान को पीछे छोड़कर विश्व की शीर्ष 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि भारत की आर्थिक वृद्धि, नीतिगत सुधारों, और वैश्विक निवेश के लिए आकर्षण को दर्शाती है। इसका मतलब है कि भारत वैश्विक मंच पर आर्थिक प्रभाव, निवेश, और भू-राजनीतिक साख के मामले में मजबूत स्थिति में है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि एक निवेश के लक्ष्य के रूप में भारत पर दांव लगाया जा सकता है। भारत के पास अपने कर्जों को भुगतान करने की मजबूत क्षमता है और इस देश में आर्थिक विकास के मजबूत फंडामेंटल्स मौजूद हैं। यह आंकड़ा बताता है कि भारत में उत्पादन, व्यापार और सेवाओं की मात्रा बहुत अधिक है। इस मामले में केवल चुनिंदा देश (जैसे अमेरिका, चीन और जर्मनी) ही भारत से आगे हैं।

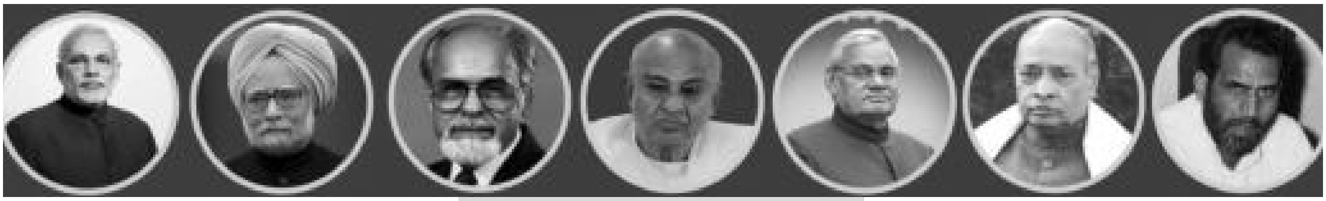

थी। यानी, अगर आज के हिसाब से तुलना करें तो आजादी के वक्त हम जितने में 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे, आज उतने में एक लीटर पेट्रोल भी नहीं आता। सोने के बाद अब पेट्रोल की कीमतों की बात। आज देश में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। लेकिन आजादी के वक्त एक लीटर पेट्रोल की कीमत महज 27 पैसे थी। साल 2000 तक एक लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 29 रुपए के आसपास पहुंच गई। सरकारी आंकड़ों की मानें तो 31 मार्च 1948 तक देश में 1.40 लाख के आसपास प्राइमरी और 12,693 मिडिल और हाईस्कूल थे। लेकिन आज देश में करीब 15 लाख स्कूल हैं। इसी तरह उस वक्त महज 414 कॉलेज हुआ करते थे और आज इनकी संख्या 49 हजार से ऊपर चली गई है। उस वक्त बजट भी मात्र 74 करोड़ रुपए हुआ करता था और केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं।

स्पेस में भारत की धमक

भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च हुआ। यह स्पेस साइंस की दुनिया में का पहला कदम था। आज, 2025 तक भारत सैकड़ों सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। इसरो के मिशन चंद्रयान-1 से लेकर चंद्रयान-3 (2023) ने दुनियाभर में भारत को अलग पहचान दी। अब गगनयान (2027 में लॉन्च हो सकता है) जैसे कई स्पेस मिशन पर काम चल रहा है। भारत सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन (1986) के तहत स्कूलों में कम्प्यूटर लाने की शुरुआत की। तब कम्प्यूटर क्लास एक नया कॉन्सेप्ट था। 2025 में भारत दुनिया के सबसे बड़े आईटी टैलेंट हब्स में शामिल है। नास्कोम रिपोर्ट 2024 के अनुसार, 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, 250 अरब डॉलर का आईटी एक्सपोर्ट है। 15 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) के जरिए इंटरनेट सर्विस शुरू हुई। इसकी शुरुआती स्पीड सिर्फ 9.6 केबीपीएस थी। टीआरएआई की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, आज 2025 में देश में 96.91 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर है। 2004 में डिजिटल आइडेंटिटी के लिए विचार शुरू हुआ और 2009 में आधार लॉन्च हुआ। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, अप्रैल 2025 तक भारत की कुल आबादी 146.39 करोड़ है, जबकि 142.39 करोड़ लोगों को आधार कार्ड मिल चुका है। इससे एलपीजी सब्सिडी, बैंकिंग, ई-केवायसी, स्कूलों में एडमिशन जैसी सर्विसेज आसान हुईं।

अभी बहुत कुछ करना बाकी...

एक और दृष्टिकोण यह है कि हमें उपलब्धि का जश्न मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत अभी भी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में 136वें स्थान पर है, और यहां तक कि क्रय शक्ति समता में हम दुनिया के 190 देशों की सूची में 119वें स्थान पर हैं। लेकिन ये संख्याएं जितना छुपाती हैं, उससे कम बताती हैं। जैसे कि हम भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाले देशों में रहने वाली वैश्विक जनसंख्या पर एक नजर डालें, जो 3.54 बिलियन है, जो विश्व की जनसंख्या का मुश्किल से 43 प्रतिशत है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से हमसे ऊपर के देशों की संख्या गिनना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमसे ऊपर के देश अधिकतर उच्च आय और मध्यम आय वाले देश हैं, और उनकी संख्या बड़ी है, यद्यपि उन देशों में रहने वाली जनसंख्या काफी कम है। जनसंख्या की दृष्टि से 18 बड़े देश हैं, जिनका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भारत से अधिक है, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 3.4 अरब है, और शेष 100 देशों की कुल जनसंख्या लगभग 14 करोड़ (0.14 अरब) है। डॉलर के बाजार मूल्य के साथ-साथ पीपीपी के संदर्भ दोनों में प्रति व्यक्ति आय की उच्च वृद्धि दर की बदौलत भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसकी रैंकिंग में बेहतरी हो रही है।

मोबाइल से पेमेंट की शुरुआत

11 अप्रैल 2016 को एनपीसीआई ने यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) लॉन्च किया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने अगस्त 2025 में ही एक आंकड़ा जारी किया, जिसमें बताया गया अब देश में हर दिन 70 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। 2 अगस्त, 2025 को पहली बार एक ही दिन में 70.7 करोड़ से ज्यादा के लेनदेन हुए। भारत के अलावा अब सिंगापुर, फ्रांस और यूएई जैसे देशों में भी यूपीआई एक्टिव है।

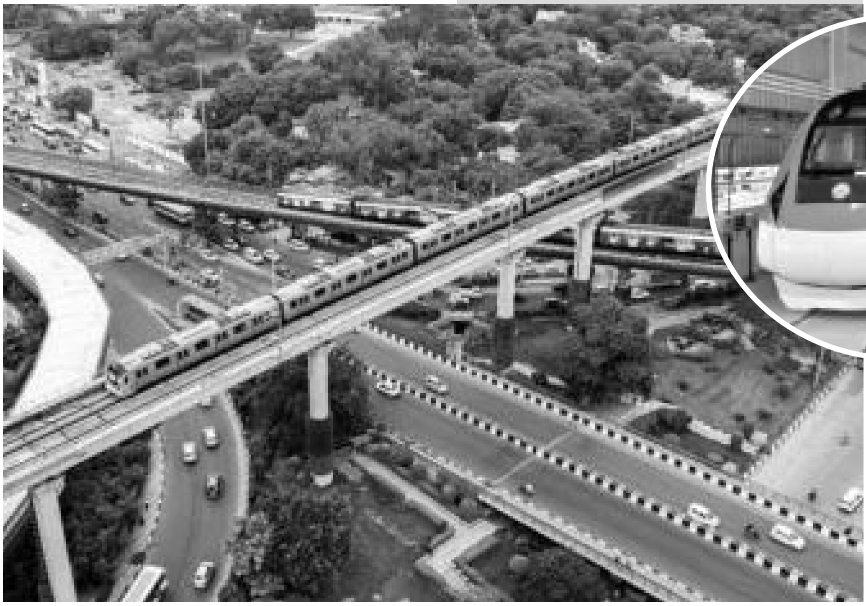

डिजिटल इलाज: कोविड के दौरान आरोग्य सेतु एप, कोविन पोर्टल, टेलीमेडिसिन ने हेल्थटेक में जबरदस्त बदलाव लाए। 2021-22 के बीच 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डिजिटल तरीके से हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, 2025 में भारत का टेलीमेडिसिन मार्केट 5.5 बिलियन डॉलर के पार पहुंच सकता है।

भारत का अपना चिप और इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन शुरू

दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया नाम की एक पहल को हरी झंडी दी थी। इसका मकसद भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने वाली इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। इसके लिए सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का फंड रखा, ताकि जो कंपनियां इस सेक्टर में निवेश करें, उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। इसमें चिप डिजाइन, डिस्प्ले यूनिट और पूरे टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। 2023 में माइक्रोन, टाटा और वेदांता ने भारत में चिप प्लांट लगाना शुरू किया। उद्योग से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2024 में करीब 38 अरब डॉलर का रहा। माना जा रहा है कि 2025 से 2026 के बीच यह आकार बढ़कर 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अगर ग्रोथ इसी रफ्तार से जारी रही, तो 2030 तक यह मार्केट 100 से 110 अरब डॉलर के बीच हो सकता है। 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5जी सर्विस लॉन्च हुई। मार्च 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार, 99.6 प्रतिशत जिलों तक 5जी पहुंच चुका है और कुल 25 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर इस नेटवर्क का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा देश में 6जी स्टैंडर्ड्स पर काम चल रहा है, यह 2030 तक शुरू हो सकता है।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप

2021 में भारत ने 50,000 स्टार्टअप्स का आंकड़ा पार किया। डीपीआईआईटी की डेटा के अनुसार, 2025 में अभी तक 1.59 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनमें से 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं, जिनकी वैल्यू 1 अरब डॉलर से ज्यादा है, जो एआई, स्पेसटेक, एग्रीटेक और एडटेक में लीड कर रहे हैं। कई रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन और डीपटेक पर भी काम कर रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत सरकार ने 2020 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया था और 2024 तक 10,000 से ज्यादा भारतीयों का जीनोम सीक्वेंस कर लिया गया है। इससे कैंसर, डायबिटीज और जेनेटिक बीमारियों का इलाज पहले से ज्यादा सटीक हो रहा है।

दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है भारत

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति वाला राष्ट्र है। सूची में अमेरिका का दबदबा बरकरार है। इसके बाद रूस और चीन दूसरे और तीसरे नंबर पर है। भारत की जल, थल और वायु सेना, एक से बढ़कर एक घातक हथियार, लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइल, लेजर सिस्टम समेत दर्जनों वार टूल भारत को एक ताकतवर देश बनाते हैं। जल, थल और वायु तीनों क्षेत्रों में भारत की ताकत बेमिसाल है। अमेरिका के फाइटर प्लेन और मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी उन्नत है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर रूस है। उसके पास 3,570,000 सैन्यकर्मी, 4,292 एयरक्राफ्ट और 5,750 टैंक हैं। जबकि चीन को तीसरे नंबर पर रखा गया है। भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है।

थल सेना- भारतीय सेना में 14.55 लाख एक्टिव सैनिक हैं। इनमें 11.55 लाख रिजर्व सैनिक हैं। 25 लाख से ज्यादा अर्धसैनिक बल के जवान हैं। इनके पास टी-90 भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, होवित्जर तोपें हैं।

वायु सेना- भारतीय वायु सेना की गिनती दुनिया के ताकतवर एयरफोर्स में होती है। भारतीय एयरफोर्स के पास 2229 विमान हैं, जिसमें 600 लड़ाकू विमान, 899 हेलीकॉप्टर, 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। भारत के प्रमुख लड़ाकू विमानों में राफेल, एसयू-30 एमकेआई, मिराज, मिग-29, तेजस है। मिसाइल प्रणाली की बात करें तो रुद्रम, अस्त्र, निर्भय, ब्रह्मोस, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हैं।

नौसेना- भारत की नौसेना भी काफी ताकतवर है। नौसेना के पास 1,42,251 नौ सैनिक हैं। परमाणु पनडुब्बियां हैं। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत हैं। इसके अलावा भारत के पास 150 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। 50 से अधिक जहाज निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा टोही और पनडुब्बी रोधी विमान, जैसे पी-8आई, एमएच-60आर हेलीकॉप्टर भी हैं।

2047 में विकसित भारत

भारत सरकार ने साल 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी को ध्यान में रखकर तमाम नीतियां भी बनाई जा रही हैं। लेकिन 2047 तक भारत को विकसित बनाने की राह आसान नहीं होने वाली। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत जैसे सौ अन्य विकासशील देशों ने पिछले दो-तीन दशकों में जो प्रगति की है उसकी रफ्तार लगातार आगे बनाकर रखना मुश्किल होगा। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। विश्व बैंक का मानना है कि राह इसलिए कठिन है क्योंकि भारत जैसे दूसरे 100 विकासशील देशों के लिए भी पिछले दो-तीन दशकों में जो प्रगति की है उसकी रफ्तार लगातार आगे बनाकर रखना मुश्किल होगा। पिछले 50 वर्षों के दौरान दुनिया के हर देश की विकास यात्रा का आंकलन करने के बाद विश्व बैंक की नई वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 कहती है कि वैश्विक माहौल इस तरह का बना है कि विकासशील देशों के मध्य आय वर्ग वाले जाल में ही फंसकर रह सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि कई देश लगातार विकास करते हुए एक ऐसी बिंदु पर पहुंचे हैं जहां उनकी प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के 10 फीसदी के करीब हो गई है। यह स्तर फिलहाल 8,000 डॉलर के करीब है। विश्व बैंक इसे मध्य आय वर्ग की श्रेणी में रखता है। विश्व बैंक के मुताबिक, 1136 डॉलर से 13,885 डॉलर प्रति व्यक्ति आय को मध्यम आय वर्ग वाले देशों में रखा जाता है। वर्ष 1990 के बाद से अभी तक सिर्फ 34 देश ऐसे हैं, जो मध्यम आय वर्ग वाले श्रेणी से ऊपर उठकर उच्च आय वर्ग वाले श्रेणी में शामिल हुए हैं। लेकिन इन 34 देशों में से अधिकांश को यह सफलता इसलिए मिली है कि उन्होंने या तो यूरोपीय संघ में शामिल होना स्वीकार किया है या फिर उन्होंने कच्चे तेल के भंडार से कमाई की है। इन देशों में अब कई तरह की समस्याएं हैं जैसे इनकी जनसंख्या में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी है,

विकसित देश अपनी आर्थिक नीतियां बदल रहे हैं व संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से ऊर्जा के उपभोग का तरीका बदल रहा है वह भी इन देशों पर बहुत ज्यादा दबाव बनाए हुए है। पहले, विकासशील देशों के लिए विकसित देश बनना आज के मुकाबले ज्यादा आसान था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर देश को 2047 तक विकासशील से विकसित बनाने का लक्ष्य सामने रखा था। विकसित राष्ट्र बनने के सपने को साकार करने के लिए भारत बुलंद इरादों के साथ जुटा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने, विकास की रफ्तार तेज करने के लिए उठाए गए कदमों के नतीजे दिखने लगे हैं। दुनिया में कई क्षेत्रों में भारत की धमक बढ़ी है। आखिर विकसित भारत की विकास यात्रा में हम कहां पर पहुंचे हैं। देश की अर्थव्यवस्था के वे क्या फैक्टर हैं, जो हमें मंजिल तक समय से पहुंचाएंगे। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पानगड़िया का कहना है कि विकसित भारत बनने के लिए हमारी प्रति व्यक्ति आय करीब 12 हजार 800 या 12 हजार 900 अमेरिकी डॉलर के आसपास होनी चाहिए। अगर हम 2022-2023 की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा लेकर चलते हैं, तो ये 2500 डॉलर था। इसे करीब 13 हजार और उससे ज्यादा तक पहुंचाने के लिए हमें करीब 7.6 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रेट की जरूरत है। उन्होंने बताया, अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट को रियल डॉलर में देखें, तो ये 7.9 प्रतिशत रही है।

बेशक भारतीय रुपए में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी कम है, लेकिन जब रुपए को डॉलर में मापा जाता है, तो रुपए की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पिछले 20 साल में ये जो ग्रोथ हुई है, जब इसे रुपए में मापते हैं, तो उसकी वैल्यू कम होने के बावजूद बढ़ी है। क्योंकि रुपए की वैल्यू डॉलर में बढ़ गई है। पानगड़िया बताते हैं, भारत अगले 20-25 साल के बारे में सोच रहा है। 2047 तक देश को अगर डेवलप कंट्री बनाना है, तो हमें जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना होगा। 2047 तक आबादी में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है। 2047 तक देश की जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा 0.5 प्रतिशत या 0.6 प्रतिशत बढ़ेगी। ऐसे में अगर 7.6 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय ग्रोथ चाहिए, तो जनसंख्या वृद्धि को जोड़ते हुए हमें करीब 8.2 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ लाना होगा। 7.9 प्रतिशत का जीडीपी ग्रोथ तो हमने पिछले 20 साल में हासिल किया है।

उन्होंने कहा, देश में जो रिफॉर्म हो चुके हैं, चाहे वे जीएसटी का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या एआई फ्रंट का हो, ये बहुत अहम हैं। आने वाले सालों में सरकार जो-जो रिफॉर्म्स करेगी, इन सबको मिलाकर देखा जाए, तो 2047 में विकसित भारत बनने का लक्ष्य हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले 20 साल में हमने 7.9 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल कर ली है, तो इसे आगे लेकर जाकर हम 8.2 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ तक ले जा सकते हैं।

मैन्युफैक्चरिंग पर देना होगा जोर

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो वस्तुओं का उत्पादन करता है। इससे रोजगार पैदा होता है और आखिरकार देश का निर्यात बढ़ता है। किसी भी देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था की बुनियाद होती है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में 13-14 प्रतिशत योगदान देता है। भारत सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। मेक इन इंडिया पहल से इस सेक्टर को पुश मिला है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल वोकल फॉर लोकल से कई देशी कंपनियों ने भारत में निर्माण शुरू किया है। एप्पल जैसी विदेशी कंपनियां भारत में निर्माण करने के लिए आ रही हैं। भारत ने चिप मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में हाल में पहल शुरू की है और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। इन प्रयासों के बावजूद भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सीमित भूमिका निभाता है। बुनियादी ढांचे, पूजी और कुशल श्रम की कमी इस दिशा में भारत की मुख्य चुनौतियां हैं। वहीं आंकड़ों के अनुसार, जापान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में 20 प्रतिशत से अधिक योगदान देता है। जापान ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और रोबोटिक्स में वैश्विक नेतृत्व करता है।

रोजगार के नए मौके तलाशने होंगे

वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह का कहना है कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत बड़ी चुनौती है। इसके ऊपर एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर रिफॉर्म निर्भर करता है। अगर हम इन चीजों को फोकस में रखते हुए रिफॉर्म करते हैं, तो ये सभी एक को-ऑर्डिनेशन में आ सकती हैं। एनके सिंह कहते हैं कि भारत के सामने विकसित देश के लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते में ग्लोबल मामले इतनी गहराई से असर डालेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होतीं, लेकिन बाकी चीजों पर हम काम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में शेयर बढ़ाना इसमें शामिल है। उन्होंने कहा, अमेरिका की बात करें, तो बाइडेन से पहले की सरकार यानी ट्रंप के काल में अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वॉर हुआ। इसके बाद रूस-यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इसकी वजह से रूस पर काफी इंबार्गो (प्रतिबंध) लगे। फिर भी वर्ल्ड इकोनॉमी में ट्रेड ग्रोथ जारी रहा। कोविड के पहले एक्सपोर्ट मार्केट पीक पर था। इसका बिजनेस 25 ट्रिलियन डॉलर का था। इसमें माल निर्यात 19 ट्रिलियन डॉलर और सेवा निर्यात 6 ट्रिलियन डॉलर था। एनके सिंह का कहना है कि कोविड के बाद इन ग्लोबल मामलों के रहते हुए भी माल निर्यात बढ़कर 25 ट्रिलियन हो गया। सेवा निर्यात भी बढ़कर 7 ट्रिलियन हो गया।

विदेशों में गूंजा मप्र का विजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मप्र विकास की नई मिसाल गढ़ रहा है। प्रदेश सरकार की इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियों का परिणाम यह हुआ है कि मप्र विदेशी निवेशकों की पसंद बन गया है। करीब डेढ़ साल के अंदर जिस तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है उससे मप्र विकास का ग्लोबल हब बन रहा है।

मप्र के संतुलित औद्योगिक विकास और रोजगार संवर्धन के लिए संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर महानगरों में निवेश के लिए हुए रोड-शो से देशभर से सकारात्मक परिणाम मिले हैं। आईटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, भारी उद्योग, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग सहित सभी प्रकार के उद्योग धंधों के माध्यम से राज्य के लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में बेहतर आर्थिक वातावरण बने, लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलें, युवाओं को अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप स्थानीय स्तर पर काम मिले, उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

निवेशकों के लिये उद्योग मित्र नीतियां

औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश प्रोत्साहन और कस्टमाइज्ड पैकेज जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। नये निवेशकों को उद्योग मित्र नीतियों के साथ सरल और सुगम निवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। कई जिलों में शुरू भी हो चुके हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये इन सेंटर में जिला कलेक्टर्स को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

भारत और स्पेन सांस्कृतिक सहयोग को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी दी कि भारत सरकार ने 2026 को भारत-स्पेन दोहरे वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस पहल के तहत दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, पर्यटन और कृत्रिम मेधा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में मध्यप्रदेश से सांस्कृतिक टीमें स्पेन भेजी जाएंगी और स्पेन के प्रतिनिधिमंडलों को भी प्रदेश में आमंत्रित किया जाएगा। स्पेन के पारंपरिक फ्लेमेंको नृत्य की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इसकी शैली भारतीय लोक परंपराओं से काफी मेल खाती है। उन्होंने कहा, वहां के लोगों का यह भी मानना है कि यह नृत्य शैली भारत से आई होगी।

मप्र बन रहा है नया ग्लोबल ग्रोथ इंजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी स्पेन यात्रा के दौरान बार्सिलोना में आयोजित इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मप्र को भविष्य का ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताया। उन्होंने निवेशकों को मप्र आने का आमंत्रण देते हुए राज्य की उद्योग-अनुकूल नीतियों, सरल प्रक्रियाओं और स्थिर नेतृत्व का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मप्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 18 डेडिकेटेड सेक्टर-वार नीतियां लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि हम निवेशकों की जरूरत को समझते हैं और उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करना हमारी नीति है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2026 को भारत-स्पेन सांस्कृतिक सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें कला, साहित्य और फिल्म से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मप्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और स्पेन की कंपनी सबमर टेक्नोलॉजीज के बीच डिजिटल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बार्सिलोना की नवाचार परंपरा की सराहना की और कहा कि जैसे बार्सिलोना संस्कृति और विकास का मॉडल बना है, उसी तरह मप्र भी विरासत से आगे बढ़कर वैश्विक विकास केंद्र बनने की राह पर है। उन्होंने इंडिटेक्स जैसी कंपनियों से मिलकर मप्र के कॉटन की गुणवत्ता की चर्चा की और कहा कि मप्र ग्रीन एनर्जी उत्पादन में तेजी से अग्रणी बन रहा है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारे राज्य में 32 लाख से ज्यादा सोलर पंप किसानों को वितरित कर ग्रीन एनर्जी में अग्रणी राज्य बनना चाहते हैं।

निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है मप्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश न सिर्फ औद्योगिक हब बन रहा है बल्कि हर क्षेत्र में उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग अनुकूल नीतियों और मजबूत अधोसंरचना से मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई और स्पेन के एक सप्ताह के विदेश दौरे को बेहद सफल बताया है। विदेश से लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने प्रदेश के लिए निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नए रास्ते खोले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस यात्रा से मध्यप्रदेश को वैश्विक मंच पर एक निवेश-अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हुआ।

\- फीचर

मप्र में आएगी टेक क्रांति

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्पेन के बार्सिलोना में छा गए। उनका अंदाज और उनकी बातों ने वहां की टेक आधारित कंपनी सबमर टेक्नोलॉजीज प्रबंधन को इतना प्रभावित किया कि उसने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुछ घंटे चले हुए दौरे के बाद ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया। यह एमओयू मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और सबमर के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ाना, मप्र में निवेश और साझेदारी के अवसरों की खोज करना है। इसमें टिकाऊ डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी, इमर्शन कूलिंग सॉल्यूशन, ग्रीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जॉइंट डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 17 जुलाई की रात ही सबमर का दौरा किया था। उनकी विजिट के दौरान सरकार और कंपनी प्रबंधन के बीच अहम चर्चा भी हुई थी। इस चर्चा के बाद ही कंपनी प्रबंधन ने कह दिया था कि मप्र सरकार और हम एक साथ सतत् टिकाऊ तकनीकी विकास पर काम कर सकते हैं।

> भारत अब धीरे-धीरे जनकल्याण सेवाओं का दायरा भी फैला रहा है। नागरिकता रजिस्टर बन जाने से एक तो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग और घुसपैठिए न तो योजनाओं का अनुचित लाभ उठा पाएंगे और न ही जनादेश को भी प्रभावित कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों के निरंतर और वार्षिक अद्यतनीकरण की व्यवस्था भी शुरू करनी होगी।

मतदाता सूचियों में घुसपैठ...

जनतंत्र में जनता चुनावों के जरिये जनादेश देती है। इसलिए चुनाव जनतंत्र की आधारशिला है और चुनावों की विश्वसनीयता यह सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है कि मतदान में वही लोग भाग लें जो उसकी अहर्ता रखते हों। मतदाताओं की अहर्ता लगभग हर लोकतांत्रिक देश में मतदाताओं की आयु, नागरिकता और जिस क्षेत्र का चुनाव हो रहा हो, वहां निवास के प्रमाण के आधार पर तय की जाती है और मतदाता सूचियां बनाई जाती हैं। पुनरीक्षण से इन्हें निरंतर अद्यतन रखने के मामले में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी को विश्व में आदर्श माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम भारत के चुनाव आयोग की तरह केंद्रीय एजेंसियां करती हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में इसका दायित्व स्थानीय प्रशासन के पास है जो केंद्र सरकारों के निर्देशों के आधार पर उसे निभाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इटली में मतदान के लिए पंजीकरण कराना और मतदान करना अनिवार्य भी है।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की बात करें तो निर्वाचन आयोग के अनुसार पिछले साल तक मतदाता सूची में कुल 96.88 करोड़ लोगों के नाम थे। जबकि देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की जनसंख्या केवल 91 करोड़ के आसपास थी। आंकड़ों की इस विसंगति के तीन प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, पिछले 15 वर्षों से जनगणना न होने के कारण जनसंख्या का अनुमान सही न होना। दूसरा, मतदाता सूचियों में ऐसे लोगों के नाम शामिल होना जिनका निधन हो चुका है। तीसरा, अयोग्य, फर्जी और घुसपैठियों का शामिल होना। उन्हीं के निवारण के लिए चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम शुरू किया है, जिसके समय को लेकर आईएनडीआईए के दल मुखर विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों का एक तर्क यह है कि नागरिकता का सत्यापन

झूठे आरोपों पर कार्रवाई करे चुनाव आयोग

यह ठीक है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के नितांत झूठे और भारतीय लोकतंत्र की छीछालेदर करने वाले आरोपों का कड़ा प्रतिवाद करने के साथ यह कहकर उन्हें बेनकाब भी किया कि वे किस तरह अपने आरोपों का जवाब सुनने उसके समक्ष उपस्थित नहीं हुए। चुनाव आयोग ने बार-बार उन्हें बुलाया लेकिन लगता है कि वे खुद को इस संवैधानिक संस्था से भी ऊपर समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव आयोग पर जैसे शरारत भरे और इस संवैधानिक संस्था को बदनाम करने एवं देश को गुमराह करने वाले आरोप लगाए, वे उनकी हताशा को ही दर्शाते हैं। वे अपनी नाकामी का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं और वह भी भद्दे तरीके से। चूंकि उनके ऐसे पुराने आरोप ठहर नहीं रहे इसलिए वे कुंठित हो रहे हैं। वे हताशा में हद पार कर रहे हैं। उन्हें यह भी भान नहीं कि वे नेता सदन हैं और उस कांग्रेस के नेता हैं, जिसने देश पर लंबे समय तक शासन भी किया और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के कुछ कदम भी उठाए। क्या कांग्रेस के लिए यह शर्म की बात नहीं कि जिस ईवीएम का उपयोग उसके शासनकाल में शुरू हुआ, उसके पीछे उसके ही बड़े नेता पड़े हैं। हाल के वर्षों में ईवीएम के कथित दुरुपयोग के जो भी आरोप लगे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्जी पाया। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगाए गए आरोप भी फर्जी ही पाए गए।

करना गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग का नहीं। हालांकि नागरिकता के सत्यापन के बिना मतदान करने की अर्हता तय नहीं हो सकती और उसे तय किए बिना सही मतदाता सूची नहीं बन सकती।

मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम चुनाव एजेंसियों का ही है, इसलिए नागरिकता का प्रमाण मांगे बिना वे पारदर्शी मतदाता सूची कैसे तैयार कर पाएंगी? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से लेकर जापान तक हर देश की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य है। घुसपैठियों की समस्या बढ़ने के कारण नागरिकता सत्यापन के नियम पूरे विश्व में कड़े होते जा रहे हैं। घुसपैठियों द्वारा मतदान के जरिये जनादेश को प्रभावित करना चुनाव प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप जैसा ही है। इसलिए बिहार में मतदाता सूची की पुनरीक्षा को चुनौती देने वालों के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का कूद पड़ना और यह कहना कि यदि बड़े पैमाने पर लोगों को इस सूची से बाहर किया गया, तो वह हस्तक्षेप करेगा, हैरत की बात है। शीर्ष अदालत को तो उलटे निर्वाचन आयोग से यह पूछना चाहिए कि उसने बिहार में 2003 से और बंगाल में 2002 से आज तक मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण क्यों नहीं किया? जिन फर्जी मतदाताओं और घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकालने के लिए निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षा का काम शुरू किया है, उन्हें वोटबैंक बनाकर अब वही दल सबसे कड़ा विरोध कर रहे हैं जो इस समस्या को लेकर कभी सबसे मुखर रहे। मसलन, लालू प्रसाद यादव ने सितंबर 1992 में केंद्र सरकार से कहा था कि वह बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने के कारगर उपाय करें। उन्होंने ऐसा कानून बनाने की मांग भी रखी थी जो घुसपैठियों को अचल संपत्ति खरीदने से रोके। सीमावर्ती जिलों में भारतीयों को पहचान पत्र देने की सलाह भी दी थी ताकि घुसपैठियों की पहचान हो सके। इसी तरह 2005 में बंगाल की मतदाता सूचियों में घुसपैठियों की समस्या रेखांकित करने के लिए ममता बनर्जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को बांग्लादेश और बंगाल के उन दो चुनाव क्षेत्रों की मतदाता सूचियां भेंट की थीं, जिनमें अनेक नाम समान थे।

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी ने मतदाता सूचियों को अद्यतन रखने के लिए निर्वाचन आयोगों को पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म-मृत्यु पंजीकरण और जनकल्याण जैसी नागरिकों के आंकड़े रखने वाली एजेंसियों से जोड़ रखा है। इसलिए वहां की चुनाव एजेंसियों को अपनी मतदाता सूचियां अद्यतन रखने में कठिनाई नहीं होती। जर्मनी ने अपना पता बदलने पर स्थानीय प्रशासन के दफ्तर में जाकर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर रखा है, जिसकी वजह से मतदाता सूची भी अपने आप अद्यतन होती रहती है। ब्रिटेन और फ्रांस में स्थानीय सरकारें डाक और इलेक्ट्रॉनिक संपर्क के माध्यम से हर साल मतदाता सूची को अद्यतन करती हैं। लोग जब चाहें ऑनलाइन जाकर भी नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हर चुनाव से पहले भी इन्हें अद्यतन किया जाता है। स्वीडन, फिनलैंड और नीदरलैंड्स जैसे छोटे यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर भी हैं, जिससे फर्जी नाम और घुसपैठिए मतदाता सूचियों में जगह नहीं पा सकते। नागरिकता रजिस्टर रखने इसलिए भी जरूरी हैं, ताकि घुसपैठिए मुफ्त स्कूली शिक्षा और इलाज, वृद्धावस्था पेंशन और सीमित समय के लिए बेरोजगारी भत्ते आदि का लाभ न उठा सकें। यहां तक कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार जैसे भारत के पड़ोसी देशों ने भी नागरिकता रजिस्टर या पहचान पत्र बना रखे हैं ताकि शरणार्थियों और घुसपैठियों का हिसाब रखा जा सके। क्या ऐसे असफल देशों से घिरे भारत को भी अपनी चुनाव प्रक्रिया को घुसपैठ के प्रभाव से बचाने के लिए नागरिकता रजिस्टर बनाने पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? भारत अब धीरे-धीरे जनकल्याण सेवाओं का दायरा भी फैला रहा है। नागरिकता रजिस्टर बन जाने से एक तो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग और घुसपैठिए न तो योजनाओं का अनुचित लाभ उठा पाएंगे और न ही जनादेश को भी प्रभावित कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों के निरंतर और वार्षिक अद्यतनीकरण की व्यवस्था भी शुरू करनी होगी।

विपक्षी दलों का रवैया चुनाव आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट का अनादर करने और संसद के भीतर-बाहर इस मुद्दे को तूल देकर चर्चा में बने रहने वाला है। क्या देश की औसत जनता इतनी नासमझ है कि उनकी सस्ती राजनीति और चालबाजी को न समझ पा रही हो? चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर जिस तरह यह कहा कि अब तक इस सूची के प्रारूप पर किसी भी दल से कोई आपत्ति नहीं मिली, उससे यही साफ होता है कि विपक्षी दल जानबूझकर इस संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के साथ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लज्जा की बात यह है कि यह काम देश पर लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस भी कर रही है।

● **विपिन कंधारी**

क्या जातीय युद्ध में टूटेगी भाजपा

दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा के सामने दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अब विपक्ष पहले से कहीं अधिक जागरूक हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा अपने ही बोझ से दब कर टूट जाएगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि विपक्ष अब हर छोटे-बड़े मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। ताजा मामला जातीय जनगणना को लेकर है। विपक्ष भाजपा को सबल जातियों का संरक्षक बता रही है और अन्य जातियों को एकजुट कर रही है।

भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। भाजपा का दावा है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। 18 से 20 करोड़ के बीच भाजपा के सदस्यों की संख्या है। केंद्र में 2014 के बाद से लगातार एनडीए की अगुवाई करते हुए भाजपा नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। देश के 20 राज्यों में भी भाजपा सत्ता में है। उनमें से 14 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और 6 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सत्ता में हैं। एक समय में यही हालत कांग्रेस की थी। कुछ समय के बाद अपने ही बोझ से दबकर कांग्रेस डूब गई।

भाजपा ने सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह से अलग-अलग विचारधाराओं के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा उससे पार्टी के अंदर ही अंदर काफी रोष फैला हुआ है। इसके अलावा भाजपा अगड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करती रही है। अब सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा को जिस तरह से एससी और ओबीसी जातियों की जी-हुजूरी करनी पड़ रही है, उससे अगड़ी जातियों के नेता और कार्यकर्ता कसमसा रहे हैं। जातियों के बीच संतुलन बनाए रखना पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। अब यह परेशानी खुलकर सामने आ रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में पहली बार इतनी देरी हो रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव के समय खत्म हो गया था। 2024 से अब तक एक साल बीतने के बाद भी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं करवा पाई। बात केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने तक सीमित नहीं रही है। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बनाने तक में उसको जातीय समीकरण बैठाना पड़ता है। पहले यह काम संगठन स्तर पर हो जाता था। अब जैसे ही एक नाम सामने आता है दूसरा खेमा विरोध करने लगता है। जिसकी वजह से किसी पदाधिकारी का चुनाव करना मुश्किल हो जाता है। अलग-अलग प्रदेशों में अध्यक्ष के चुनाव में इस तरह का विरोध खूब देखने को मिल रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा जब तक सत्ता में है, मीडिया पर उस का पूरा कंट्रोल है, पैसा कुछ के ही हाथ में है। ऐसे में विरोध के स्वर मुखर नहीं हो रहे हैं लेकिन जैसे ही वह कोई कदम लेने को होती है, पार्टी के भीतर और बाहर विरोध से सुर उभरने लगते हैं। यह किसी एक प्रदेश की कहानी नहीं है। विरोध के सुर कई प्रदेशों में खदबदा रहे हैं। जिस तरह से हांडी के एक चावल को देखने से पता चल जाता है कि पूरी हांडी के चावल पके हैं या नहीं उसी तरह से विरोध का एक स्वर बता देता है कि पार्टी में क्या चल रहा है?

तेलंगाना का ताजा उदाहरण सामने है। वहां भाजपा को बड़ा झटका तब लगा जब उसके फायर ब्रांड नेता और विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। टी राजा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर एन रामचंद्र राव का नाम सामने आने के बाद नाराज हो गए थे। टी राजा सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि बहुत से लोगों की चुप्पी को सहमति नहीं समझ जाना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए बोल रहा हूं जो हमारे साथ आस्था के साथ खड़े थे और जो आज निराशा महसूस कर रहे हैं। तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है और नेताओं के पास अवसर हैं कि वे कांग्रेस में जा मिले। टी राजा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को भेजे पत्र में लिखा कि भले ही मैं पार्टी से अलग हो रहा हूं, लेकिन मैं हिंदुत्व की विचारधारा और हमारे धर्म और गोशामहल के लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा और हिंदू समुदाय के साथ और भी अधिक मजबूती से खड़ा रहूंगा। यह एक कठिन निर्णय है, लेकिन एक जरूरी निर्णय है। टी राजा सिंह भाजपा के लिए मजबूत नेता थे। उनकी तरह ही अलग-अलग राज्यों में यह बेचैनी अंदर ही अंदर बढ़ रही है। हिंदुत्व की ढाल ही अब भारतीय जनता पार्टी के पास बची है, पर उससे वोट नहीं मिलते। यह जून 2024 के लोकसभा चुनाव और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में साफ हो गया था।

सजग हो गया विपक्ष

2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और विपक्ष के बीच मिले वोटों में बहुत अंतर नहीं था। जो भाजपा पहले अजेय समझी जा रही थी, उसके बारे में यह सच सामने आ गया कि उसको हराया भी जा सकता है। अब विपक्ष चुनाव-दर-चुनाव ज्यादा समझदार और आक्रामक हो रहा है, जिससे उसके नेताओं में आत्मविश्वास आ गया है। वह एकजुट हो रहा है। चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष सचेत हो चुका है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विस्तार से लिखा। उससे सबक लेते हुए अब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सकें। अब विपक्षी दल अपने वोटों को बिखरने से रोकने के लिए एकजुट हो रहे हैं। बिहार में राजद और कांग्रेस सहित गैर भाजपाई खेमा इस प्रयास में है कि वोट बिखरने न पाएं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एकसाथ आ खड़े हुए हैं। वहीं उप्र में कांग्रेस-सपा साथ है।

भाजपा को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उनको लंबे समय तक पद पर बनाए रखना पड़ा। भाजपा इस बात का बखान बड़े जोरशोर से करती है कि उसकी पार्टी में एक नेता एक पद का सिद्धांत ही काम करता है। इसी वजह से जब 2019 में अमित शाह को मोदी मंत्रिमंडल में गृहमंत्री बनाया गया तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। जिसके बाद जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आखिर 2019 और 2024 के बीच क्या बदल गया जो जेपी नड्डा को उन के पद से हटाने में मुश्किल आ गई। जेपी नड्डा को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इसके बाद भी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी बने रहे। सवाल उठता है कि जो सिद्धांत अमित शाह के मामले में काम कर रहा था उसने जेपी नड्डा के समय काम क्यों नहीं किया। असल में 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिस तरह से वोट मिले जितनी भाजपा की सीटें आईं उनके कारण ही भाजपा को फैसला करने में कठिनाई आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 2014 के लोकसभा से अधिक सीटें मिली थीं। ऐसे में भाजपा ताकतवर थी। उसने एक झटके में अमित शाह को गृहमंत्री बना दिया और जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया।

2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटकर 240 रह गईं। वह अपने बूते सरकार बनाने में सफल नहीं हुई। उसको दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ा। चुनावी हार का कारण यह था कि हिंदुत्व के बावजूद एससी और ओबीसी का समर्थन उसको नहीं मिला। उप्र में उसको केवल 33 सीटें ही मिल सकीं जबकि उसकी विरोधी समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिलीं। यानी भाजपा की ताकत घटी। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया पर उनकी जगह पर अपनी मनपसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाने में दिक्कत पेश आ रही है। ऐसे में लगातार एक पद एक नेता सिद्धांत को दरकिनार कर के जेपी नड्डा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। लोकसभा में भाजपा की सीटें घटने का प्रभाव भले ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाया पर पार्टी के भीतर मोदी-शाह के फैसलों को प्रभावित किया। अगर 2019 के चुनाव जैसी सफलता भाजपा को 2024 के चुनाव में भी मिली होती तो जेपी नड्डा को हटाकर दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में दिक्कत नहीं आती। भाजपा के कमजोर होने से मोदी-शाह के फैसलों पर आरएसएस अपनी धौंस जमाने लगा है। वह अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है। मोदी-शाह अपनी पसंद को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में बीच का रास्ता यह निकाला गया कि एक नाम पर दोनों सहमत हो जाएं। अब भाजपा पर आरएसएस की पकड़ मजबूत होती जा रही है। अब भाजपा को संतुलन बनाकर काम करना पड़ रहा है। भाजपा में सब से बड़ी गुटबाजी उप्र में चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को इसी प्रदेश में हुआ जबकि भाजपा को यह लग रहा था कि अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण के बाद उप्र में उसकी स्थिति मजबूत होगी। लोकसभा चुनाव में राममंदिर के नाम पर भाजपा को वोट नहीं मिले। यही भाजपा और आरएसएस की चिंता का कारण है।

चुनाव में धर्म का असर खत्म होते ही मसला जाति पर टिक जाता है। जाति के मसले पर भाजपा को नुकसान हो जाता है। ऐसे में जातीय गुटबाजी उभार मारने लगती है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने हार का ठीकरा प्रदेश सरकार पर फोड़ दिया। उनके निशाने पर शुरू से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हैं। भाजपा धर्म के वोट पर प्रभाव के कारण ही योगी आदित्यनाथ को आगे किए है। सवाल उठ रहा है कि जब धर्म का मुद्दा वोट नहीं दिला पा रहा, क्या तब भी भाजपा योगी आदित्यनाथ पर ही दांव लगाने का खतरा मोल लेगी? तेलंगाना में फायर ब्रांड नेता और विधायक टी राजा सिंह को दरकिनार किया गया, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि उप्र में भी धर्म की जगह जातीय समीकरणों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

● इन्द्र कुमार

कॉर्पोरेट कोयले के खिलाफ जंग

छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य, जिसे लोग मध्य भारत के फेफड़े कहते हैं, जैव-विविधता और सांस्कृतिक धरोहर का खजाना है। लेकिन अब ये इलाका गंभीर खतरे में है। 7 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ वन विभाग ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को दी गई केंटे एक्सटेंशन कोयला खदान के लिए 1,742.6 हेक्टेयर घने जंगल की जमीन को हस्तांतरित करने की सिफारिश की। इस प्रोजेक्ट में अडानी एंटरप्राइजेज खनन का काम कर रही है। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया, जिसके बाद आदिवासी समुदायों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने इसका जमकर विरोध शुरू कर दिया।

26 जून 2025 को सरगुजा डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के निरीक्षण के आधार पर ये सिफारिश की गई। लेकिन इस पर ग्राम सभाओं के अधिकारों को कुचलने, पर्यावरण नियमों की अनदेखी और लाखों आदिवासियों की आजीविका को कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए दांव पर लगाने का आरोप लग रहा है। अब ये प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। हसदेव का ये संघर्ष विकास, आदिवासी अधिकारों और भारत की पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के बीच टकराव की बड़ी मिसाल बन गया है।

हसदेव के जंगलों को कोयला खनन के लिए खाली करने का वन विभाग का फैसला पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 का खुला उल्लंघन है। ये कानून भारत के पांचवीं अनुसूची वाले इलाकों में आदिवासियों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार देता है। इसमें विकास परियोजनाओं को मंजूरी देना या रोकना, जंगलों का प्रबंधन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना शामिल है। वन अधिकार अधिनियम 2006 भी आदिवासियों को जंगलों को संभालने और उन्हें नुकसानदायक परियोजनाओं से बचाने का हक देता है। लेकिन हसदेव में केंटे एक्सटेंशन कोयला ब्लॉक के लिए वन विभाग की सिफारिश पर इन कानूनों को रौंदने का आरोप है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने पास की परसा कोयला खदान की मंजूरी में गड़बड़ियों का खुलासा किया था, जिसमें ग्रामसभा की सहमति में जालसाजी और आदिवासी नेताओं पर दबाव बनाने की बात सामने आई थी। केंटे एक्सटेंशन के मामले में भी यही शिकायतें हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वन विभाग ने सलही, हरिहरपुर और फतेहपुर जैसे गांवों में ग्राम सभाओं से जरूरी सलाह-मशविरा तक नहीं किया।

वन विभाग का दावा है कि ये कदम वर्किंग प्लान कोड 2023 के तहत वैज्ञानिक वन प्रबंधन के लिए जरूरी है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये पेसा और एफआरए कानूनों को नजरअंदाज करने का बहाना है। ये कानून आदिवासियों को उनके जंगलों की रक्षा का अधिकार देते हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने वन विभाग की इस कार्रवाई की निंदा की है। उनका कहना है, ये सिफारिश पेसा और एफआरए का उल्लंघन करती है। ये उन आदिवासी समुदायों की आवाज दबाती है, जो पीढ़ियों से हसदेव के रखवाले रहे हैं।

वन विभाग का ये कदम एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर ये जंगल किसके लिए हैं? कॉर्पोरेट्स के लिए या उन आदिवासियों के लिए, जिनका पूरा जीवन हसदेव पर टिका है? केंटे एक्सटेंशन कोयला ब्लॉक हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र का हिस्सा है, जो 1,879.6 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें 5.179 बिलियन टन कोयले का भंडार है। इस प्रोजेक्ट में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ अडानी एंटरप्राइजेज काम कर रही है। ये 1,742 हेक्टेयर घने जंगल को निशाना बना रहा है, जो चोरनाई नदी के जलग्रहण क्षेत्र में है और जल सुरक्षा व जैव-विविधता के लिए बेहद जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा की राज्य सरकार पर पर्यावरणीय वादों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक पेड़ मां के नाम अभियान तब हास्यास्पद लगता है, जब वो कॉर्पोरेट हितों के लिए 6 लाख पेड़ काटने की योजना बनाती है। बघेल का कहना है कि हसदेव में पहले से चल रही परसा ईस्ट और केंटे बेसन खदान में 350 मिलियन टन कोयला है, जो राजस्थान की बिजली जरूरतों को 20 साल तक पूरा कर सकता है। ऐसे में केंटे एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की जरूरत ही नहीं है। इससे साफ है कि ये फैसला कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए लिया जा रहा है, न कि जनता की जरूरत के लिए।

हसदेव का पर्यावरणीय महत्व भी कम नहीं है। ये जंगल 640 पौधों की प्रजातियों, 128 औषधीय पौधों, 92 पक्षी प्रजातियों और हाथी, भालू, तेंदुआ जैसे लुप्तप्राय जानवरों का ठिकाना है। वन्यजीव संस्थान ने चेतावनी दी है कि हसदेव में खनन से मानव-हाथी टकराव बढ़ेगा और वन्यजीवों के लिए जरूरी गलियारे टूट जाएंगे। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने बताया कि हसदेव नदी और हसदेव बांगो बांध के जरिए ये जंगल 3 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई में अहम भूमिका निभाता है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

धारावीः पुनर्विकास या विनाश

एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी अब पुनर्विकास के मुहाने पर खड़ी है। 600 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैली धारावी में एक लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। दावों के अनुसार देश के जाने-माने बिजनेस टायकून गौतम अडानी मुंबई में स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी की किस्मत बदलने वाले हैं। अडानी ग्रुप की रियल एस्टेट इकाई अडानी रियल्टी ने 11 अरब डॉलर के निवेश के साथ धारावी को बदलने का प्लान बनाया है। इससे 641 एकड़ में बसे इस इलाके में रहने वाले करीबन दस लाख लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन धारावी के लोग इसको मानने को तैयार नहीं हैं।

पूर्व विधायक और धारावी बचाओ आंदोलन (डीबीए) के नेता बाबूराव माने कहते हैं कि यह योजना धारावी की सूरत बदल सकती है, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? बाबूराव माने और उनके जैसे कई लोग जिनके लिए मुंबई का यह घना इलाका, जिसे ये लोग अपना घर कहते हैं, के लिए धारावी पुनर्विकास योजना सिर्फ रियल एस्टेट का बदलाव नहीं है, यह बड़ा परिवर्तन है, जो धारावी की अनोखी आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहचान को मिटा सकता है। उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? पर्यावरण। वे आगे कहते हैं कि हम, धारावी बचाओ आंदोलन के लोग, अपनी रणनीति तय करने के लिए जल्दी ही बैठक करेंगे। इस योजना में कई खामियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें पर्यावरण और बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले असर को बहुत कम महत्व दिया गया है।

धारावी की सबसे बड़ी चिंताओं में एक है, यहां का चमड़ा उद्योग। इस उद्योग को अक्सर गलत समझा जाता है। धारावी की बड़ी पहचान और टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं में से एक यह उद्योग है। यहां भारत की सबसे अधिक टेनरी (चमड़े के कारखाने) हैं। धारावी में बने चमड़े के सामान दुनियाभर में भेजे जाते हैं। यह सिर्फ कारोबार ही नहीं, बल्कि कई परिवारों की पीढ़ियों से चली आ रही आजीविका का सहारा भी है। बाबूराव माने कहते हैं कि यह केवल रोजगार की बात नहीं है। इस उद्योग से आपस में कई चीजें जुड़ी हुई हैं। यह मजबूत आर्थिक तंत्र का हिस्सा है। उन्हें यहां से हटाकर कहीं और ले जाया जाएगा, तो ये उस तरह नहीं चल पाएंगे, जैसे यहां चलते हैं। करीब 700 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाला यह कारोबार सैकड़ों प्रोसेसिंग यूनिट पर आधारित है, जहां भेड़, बकरी, भैंस और गाय की खाल पर काम होता है। इसके अलावा धारावी में हजारों छोटे उद्योग चलते हैं, जैसे प्लास्टिक की रीसाइक्लिंग, कपड़े का उत्पादन और पुरानी धातुओं को उपयोग लायक बनाना। इन उद्योगों के लिए केवल जगह नहीं, बल्कि पास में मजदूरों के घर, ढुलाई की सुविधा और पर्यावरण से जुड़ी खास व्यवस्था की जरूरत होती है। जैसे कचरा साफ करने की इकाइयां और हवा के आने जाने की सही व्यवस्था।

धारावी पुनर्विकास परियोजना को महाराष्ट्र सरकार और अडानी समूह की संयुक्त भागीदारी वाली कंपनी नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड चला रही है। यह बहुत बड़ी कंपनी है। धारावी के लगभग 620 एकड़ क्षेत्र में से 269 एकड़ को विकास के लिए योग्य माना गया है। इसमें 116.6 एकड़ लोगों के पुनर्वास और 118.4 एकड़ व्यापारिक और खुदरा उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है। केवल 99 एकड़ को खुली जगह के रूप में रखने का प्रस्ताव है। सरकारी आंकड़ों में धारावी की जनसंख्या बहुत कम दिखाई गई है। 2011 की जनगणना में यहां करीब 3 लाख लोग बताए गए थे, जबकि असल में अब यहां 7 से 10 लाख लोग रहते हैं। धारावी के पुनर्विकास की योजना के तहत, कई लोगों को धारावी से बाहर बसाने का प्रस्ताव है। उन्हें मुंबई के अलग-अलग इलाकों में शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे माहिम में रेलवे की 47.5 एकड़ जमीन है, कुर्ला में मदर डेयरी की 21.5 एकड़, मुलुंड का 58.1 एकड़ का सॉल्ट पैन, मलाड का अक्सा इलाका जो 140 एकड़ में फैला है और देवनार डंपिंग ग्राउंड की 124 एकड़ जमीन इसके लिए उपयोग में ली जा सकती है। लेकिन ये सभी जगहें या तो पर्यावरण के लिए खतरे से भरी हैं या फिर कानूनी उलझनों में फंसी हुई हैं।

धारावी बचाओ आंदोलन से जुड़े राजू कोरड़े इसे पर्यावरणीय अन्याय कहते हैं। उनका कहना है कि सरकार सक्रिय कचरा स्थल पर उद्योग बसाना चाहती है। यह केवल खतरनाक ही नहीं, बल्कि अवैध भी है। धारावी से चमड़ा और अन्य छोटे उद्योगों को देवनार ले जाने से ये कारोबार बंद भी हो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 2023 में देवनार के पास चमड़ा उद्योग पार्क की घोषणा की थी जिसमें 100 से अधिक शोरूम और सुविधाएं शामिल थीं। लेकिन स्थानीय लोग उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं।

● बिन्दु माथुर

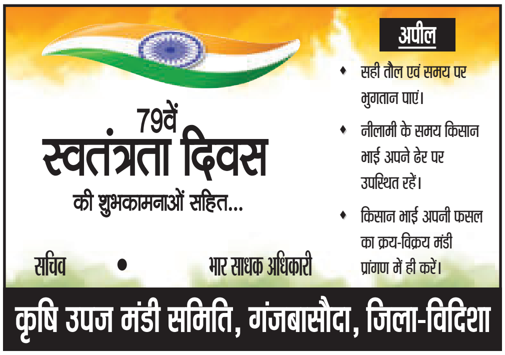

राजस्थान कांग्रेस का मिशन-2028

राजस्थान में भजनलाल सरकार के गठन को डेढ़ साल से अधिक हो चुके हैं। भाजपा सरकार नीतियों को धरातल पर उतारने में जुटी हुई है। वहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने साल 2028 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। संगठन की मजबूती से लेकर पार्टी में एकजुटता तक, हर मोर्चे पर पार्टी के भीतर कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। मिशन-2028 के तहत हाल ही में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के दिल्ली आवास पर बैठक भी हुई। इसमें कई फैसले लिए गए। सबसे अहम फैसला संगठन का जमीन पर सक्रिय और मजबूत करने से जुड़ा है। पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया है कि लंबे वक्त से निष्क्रिय चल रहे पदाधिकारियों की छुट्टी की जाएगी।

पिछली सरकार में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मतभेद की चर्चाओं ने खूब सुर्खियां बटोरीं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत का श्रेय पायलट को दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी गहलोत को, जिसके बाद मानेसर एपिसोड के चलते कांग्रेस सरकार पर संकट भी आ गया। लेकिन अब इन दोनों के बीच मतभेद कम होते नजर आ रहे हैं।

कांग्रेस संगठन स्तर पर पार्टी को सक्रिय करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जमीनी पहुंच पर काम हो रहा है। बैठकों का फोकस भी संगठन सशक्तिकरण है। साथ ही ब्लॉक से जिला स्तर तक के पदाधिकारियों के कार्य मूल्यांकन और आगामी रणनीति निर्माण पर है। बताया जा रहा है कि 4 चरणों में अलग-अलग समूहों के साथ चर्चा होगी। वहीं, जमीनी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए फॉर्मूले पर भी काम हो रहा है। आगामी समय में नए समन्वयक मंडल के गठन और जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना पर भी काम शुरू हो जाएगा। ताकि संगठन को धरातल पर मजबूत किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पार्टी आलाकमान स्पष्ट संकेत दे चुका है कि अब पार्टी के भीतर ढीले रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वहीं भाजपा की तर्ज पर अब कांग्रेस ने भी राजस्थान के सभी जिलों में अपने कार्यालय बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी ने अपने खुद के दफ्तरों के निर्माण पर खास ध्यान नहीं दिया। अधिकतर जिलों में कांग्रेस के दफ्तर किराए के भवनों में या अस्थाई व्यवस्थाओं पर चल रहे हैं, जिससे संगठनात्मक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने अब इस कमी को दूर करने का फैसला लिया है। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी के लिए स्थायी भवनों का निर्माण कराया जाएगा। पार्टी ने इस कार्य के लिए एक विशेष कमेटी गठित कर दी है, जो जमीन चयन से लेकर अलॉटमेंट और निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया संभालेगी। निर्माण की लागत पार्टी नेताओं के सहयोग और क्राउडफंडिंग से जुटाई जाएगी। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान में कोई भी व्यक्ति छोटी से छोटी राशि देकर योगदान कर सकता है।

फिलहाल राजस्थान में केवल छह जिलों में कांग्रेस कार्यालय के अपने भवन है। जिसमें सीकर, चित्तौड़गढ़, अलवर, जालोर, उदयपुर और बांसवाड़ा में कांग्रेस के अपने भवन हैं। बाकी जिलों में दफ्तर किराए के भवनों में चल रहे हैं और जयपुर सहित कई जिलों के किराए के लाखों रुपए बकाया हैं। पार्टी का मानना है कि अपने भवन होने से संगठनात्मक गतिविधियों में मजबूती आएगी और कार्यकर्ताओं को स्थायी मंच मिलेगा। नवनियुक्त प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा ने बताया कि भीलवाड़ा, राजसमंद और श्रीगंगानगर में जमीन अलॉटमेंट हो चुका है और जल्द ही यहां निर्माण कार्य शुरू होगा। अन्य जिलों में जमीन चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, जिसके बाद अलॉटमेंट कराया जाएगा। बोहरा ने कहा कि जनहित के सहयोग से, यानी क्राउडफंडिंग के जरिए, हम हमारे दफ्तरों का निर्माण करेंगे। कोई अगर पांच रुपए भी देना चाहेगा तो हम उसका योगदान स्वीकार करेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने जयपुर के मानसरोवर में नए मुख्यालय के निर्माण को भी प्राथमिकता पर रखा है। पार्टी का दावा है कि अगले दो वर्षों में मुख्यालय का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। संगठन का मानना है कि स्थायी भवन न केवल पार्टी की छवि मजबूत करेंगे, बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता के बीच बेहतर समन्वय का केंद्र भी बनेंगे।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

राजनीति में चल रही एबीसीडी की जंग

उप्र की राजनीति में इस समय एबीसीडी की जंग सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा हाल ही में दिए गए बयान के बाद सियासत और भी गरमा गई है। अखिलेश ने जब सत्ताधारी भाजपा सरकार को एबीसीडी के जरिए घेरा, तो प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उसी एबीसीडी से पलटवार करते हुए सपा के शासनकाल को कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को वाकई एबीसीडी आती होती, तो आज उनकी पार्टी सत्ता से बाहर न होती। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जिस एबीसीडी को अपनाया, उसी ने प्रदेश की हालत बिगाड़ दी।

राजभर ने अंग्रेजी वर्णमाला को लेकर सपा शासन पर तीखे आरोप लगाए। उनके मुताबिक ए से अराजकता, बी से भ्रष्टाचार, सी से चोर और डी से दलाली यही सपा शासन की असल पहचान थी। उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने शासन में स्थायित्व नहीं दिया, भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया, अपराधियों को संरक्षण दिया और हर निर्णय में सिफारिश व दलाली को प्राथमिकता दी। उन्होंने वाई से यादववाद और जेड से जीरो बदलाव तक पूरा वर्णन करते हुए सपा की नीतियों को जातिवादी, भाई-भतीजावादी और अव्यवस्थित करार दिया।

प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खासतौर से सपा शासन में शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे, तब सरकारी स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि नकल माफिया और भर्ती घोटालों के लिए कुख्यात थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के पांच साल के शासन में एक भी ऐसा स्कूल नहीं बना, जिसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए आदर्श कहा जा सके। टूटी हुई दीवारें, गिरती हुई छतें, गंदे टॉयलेट और घटती बच्चों की संख्या, यही उस समय की शिक्षा व्यवस्था का असली चेहरा था। इसके उलट भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाए गए हैं।

अभी शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी

योगी शासन में शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी और गुणवत्ता आधारित हुई है। राजभर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था जातिवाद, तुष्टीकरण और नकल माफिया के चंगुल में फंसी हुई थी। वहीं भाजपा सरकार में ईमानदारी, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सपा राज में शिक्षा के मंदिर ढहे, भाजपा राज में ज्ञान के दीप जले। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने स्कूल बंद कराए, हमने बच्चों के लिए नए स्कूल बनाए। उन्होंने 3.45 करोड़ बच्चों को स्कूल से दूर किया, हमने उन्हें किताब और क्लास से जोड़ा।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 11,500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और 96 प्रतिशत से अधिक सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत इस साल 27 लाख से अधिक बच्चों का नया नामांकन हुआ है, जो शिक्षा के प्रति जनता के भरोसे को दर्शाता है। मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय योजना के अंतर्गत हर जिले में दो अत्याधुनिक विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें 30 करोड़ रुपए प्रति विद्यालय की लागत से केजी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार कराई जाएगी।

राजभर ने आगे बताया कि अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत सभी 18 मंडलों में स्कूल चालू हो चुके हैं, जहां 18,000 से अधिक श्रमिक और अनाथ बच्चों को मुफ्त आवासीय शिक्षा, खेल, स्किल ट्रेनिंग और आधुनिक प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में 1,722 पीएमश्री स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, आईसीटी लैब और प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग की सुविधाएं शुरू की गई हैं। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से अपग्रेड किया गया है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

किसका पलड़ा भारी

बिहार में चुनाव सिर पर हैं, मगर एनडीए पूरी तरह से अस्त-व्यस्त नजर आ रही है। कहने को मुख्यमंत्री का चेहरा फिलहाल नीतीश कुमार जरूर हैं, पर चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ने की तैयारी चल रही है। कमजोर नेतृत्व और अलग-अलग समाज के प्रतिनिधित्व की कमी एनडीए की उम्मीद को लेकर कई सवाल खड़े करती हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों उफान मार रही है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार का भविष्य तय होना है। यहां की राजनीति के साथ गंगा भी उफान पर है। बिहार इन दिनों बाढ़ से ग्रस्त है और आम जनता ही त्राहि-त्राहि कर रही है। बिहार में कितना विकास हुआ है इसकी पोल इस बाढ़ ने खोल कर रख दी है। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू अपनी छवि सुधारने के लिए आनन-फानन में सिर्फ चार स्टेशनों के लिए पटना मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं।

बिहार की राजनीति देश की अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है, अन्य राज्यों में वोट शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और विकास के नाम पर पड़ते हैं, वहीं बिहार एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां आज भी वोट जाति के नाम पर पड़ते हैं। बिहार की राजनीति में जाति एक ऐसा सत्य है जो चाहे अनचाहे हर चुनावी राजनीति में हावी रहती है। दलित वर्ग इस राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है लेकिन आज भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से यह सबसे अधिक वंचित वर्ग में गिने जाते हैं। वर्षों से यह वर्ग सत्ता परिवर्तन का निर्णायक वर्ग रहा है लेकिन अब तक सत्ता में इस वर्ग को वास्तविक भागीदारी नहीं मिली। केंद्र और राज्य दोनों में वर्तमान में भाजपा और उसके गठबंधन की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा बिहार में कोई भी दलित चेहरा सामने नहीं ला पाई है। बिहार में भाजपा प्रमुख शक्ति बना है लेकिन वह वंचित वर्गों के साथ न्याय नहीं करना चाहती है। भाजपा बिहार में आज तक मजबूत जन स्वीकार चेहरा दलित समुदाय से नहीं ला पाई है। यही नहीं दलितों की शिक्षा रोजगार और सामाजिक स्थिति के मामले में भी भाजपा रिकॉर्ड सवालों के घेरे में है।

राष्ट्रीय स्तर पर रामदास अठावले, थावरचंद गहलोत और अर्जुन राम मेघवाल जैसे दलित नेताओं को भाजपा सामने लाई तो है लेकिन बिहार में स्थिति काफी अलग है। यहां न तो ऐसा कोई चेहरा भाजपा ला पाई है न ही पार्टी ने किसी को तैयार करने की कभी कोई गंभीर कोशिश की है। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी का बिखराव भाजपा के लिए और मुश्किल पैदा करता है। चिराग पासवान की स्थिति खुद ही डगमग है और वह भाजपा के लिए एक अस्थाई दलित चेहरा नहीं बन पाए हैं। दलित समुदाय के लिए कोई व्यापक नीति या कार्यक्रम भी भाजपा की बिहार इकाई के पास नहीं है। जो दर्शाता है कि यह वर्ग उनके एजेंडे के प्राथमिकता से बाहर है। भाजपा का राजनीतिक रवैया दलितों के लिए प्राय प्रतीकात्मक रहा है। उनके घर पर खाना खाना, मंदिर में दलित पुजारी की नियुक्ति की बातें करना, या समय-समय पर कुछ आरक्षित सीटें देना। लेकिन आज का दलित समाज केवल सांकेतिक प्रतिनिधित्व से संतुष्ट नहीं है, वह भागीदारी की बात कर रहा है, नीति निर्माण में हिस्सेदारी चाहता है। दलित युवा सरकारी नौकरियां उच्च शिक्षा और सामाजिक सम्मान की मांग कर रहे हैं। उनकी आकांक्षाएं बढ़ी हैं लेकिन भाजपा के पास उनके लिए संतोषजनक उत्तर नहीं है। इसके ठीक उलट भाजपा के कार्यकाल में दलितों को प्रताड़ना ही झेलनी पड़ी है, चाहे वह मप्र में भाजपा नेता के द्वारा दलित व्यक्ति पर पेशाब करने का मामला हो, या उप्र में दलित युवक की बारात की पिटाई हो। दलितों के लिए भाजपा कभी भी मसीहा का रोल नहीं निभा पाई है। दलितों की जिंदगी में भाजपा ने खुद को विलेन बनाकर पेश किया है। दलित बेटियों की आबरू लूटी जा रही हो या सरेआम दलितों की पिटाई हो, भाजपा और भाजपा के नेता इसको लेकर कोई भी बयान टीवी की डिबेट में या सोशल मीडिया पर नहीं देते हैं। शायद जिस सनातन धर्म की बात भाजपा करती है दलित खुद को उस सनातन का हिस्सा नहीं मानते हैं। यही कारण है कि भाजपा दलितों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम या कोई ठोस कानून नहीं बना पाई है।

● **विनोद बक्सरी**

पाकिस्तान के सिंधु डेल्टा में पानी 80 प्रतिशत घटा

पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी सिंधु के डेल्टा में जिंदगी खत्म होने की कगार पर है। सिंधु का पानी ऊपर के इलाकों में नहरों और बांधों में रोक लिया गया है। इसकी वजह से सिंध प्रांत और डेल्टा क्षेत्र में पानी पहुंचना लगभग बंद हो गया है। 1950 के दशक से अब तक सिंधु डेल्टा में बहने वाले पानी में 80 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है।

दूसरी तरफ इसमें अरब सागर का खारा पानी घुस आया है। इससे यहां की जमीन खारी हो चुकी है। खेती बंद हो गई है। मछलियों की आबादी घटी है और झींगा-केकड़ों का जीवन संकट में है। डेल्टा में कभी 17 छोटी नदियां, दलदली जमीन, मैंग्रोव जंगल और मछलियों से भरे कीचड़ भरे मैदान थे। आज वह मिट्टी नमकीन, पानी जहरीला और जमीन रहने लायक नहीं बची। सिंध सरकार के मुताबिक, यहां 80 प्रतिशत पानी पीने लायक नहीं बचा। समुद्र का खारा पानी अब जमीन के अंदर तक घुस आया है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले दो दशकों में अब तक 12 लाख से अधिक लोग डेल्टा छोड़कर कराची जैसे शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। पाकिस्तान फिशरफोक फोरम का कहना है कि तटीय इलाकों से हजारों मछुआरे परिवार विस्थापित हो चुके हैं। 54 साल के हबीबुल्लाह खट्टी ने अपने अब्दुल्ला मीरबहार गांव को छोड़ दिया है। गांव छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी मां की कब्र पर आखिरी सलाम किया। वो बताते हैं, चारों तरफ खारा पानी फैल चुका है। गांव में अब बस चार घर बचे हैं। कभी 40 गांवों वाले खारो चान इलाके में अब ज्यादातर गांव समंदर निगल चुका है। 1981 में इस इलाके के आबादी 26 हजार थी, जो 2023 में घटकर सिर्फ 11 हजार बची।

सिंध प्रांत में फरवरी से ही सेव द इंडस रिवर मूवमेंट नामक गठबंधन ने विरोध शुरू कर दिया है। इसमें पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय समुदाय, एनजीओ और नीति-निर्माता शामिल हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि ये नहरें सिंधु नदी का पानी ऊपर ही रोक देंगी, जिससे सिंध और खासकर इंडस डेल्टा में खेती पर संकट खड़ा हो जाएगा। महिला संगठन सिंधियानी तहरीक की कार्यकर्ता मरियम गोपांग के कहती हैं, हम अपनी सिंधु नदी के बिना कुछ भी नहीं हैं। यह नहीं होगी तो हम मर जाएंगे।

पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी सिंधु से पानी खींचकर 4 प्रांतों में 6 नहरें बनाई जा रही हैं। यह प्रोजेक्ट ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चल रहा है। इसकी लागत करीब 28 हजार करोड़ रुपए है। इन नहरों से मिलने वाले पानी का इस्तेमाल रेगिस्तानी जमीनों को खेती योग्य बनाने में किया जाएगा। यह पानी सिंधु नदी या उसके बैराजों से लिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी नहर पंजाब के चोलिस्तान रेगिस्तान में बनाई जाएगी।

खट्टी ने खारो चान कस्बे के अब्दुल्ला मीरबहार गांव से, जहां नदी समुद्र में गिरती है, लगभग 15 किलोमीटर (9 मील) दूर, एएफपी को बताया, हम चारों तरफ खारे पानी से घिर चुके हैं। मछली पकड़ने की क्षमता कम होने पर, 54 वर्षीय खट्टी ने सिलाई का काम शुरू किया, लेकिन यह भी असंभव हो गया क्योंकि 150 घरों में से केवल चार ही बचे थे। उन्होंने बताया कि शाम के समय, इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। उस समय यहां पर आवारा कुत्तों को वीरान लकड़ी और बांस के घरों में घूमते हुए देखा जा सकता है।

खारो चान में कभी करीब 40 गांव हुआ करते थे, लेकिन ज्यादातर बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण लुप्त हो गए हैं। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, शहर की आबादी साल 1981 में 26,000 से घटकर 2023 में 11,000 रह गई है। खट्टी अपने परिवार को पास के कराची ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और जहां सिंधु डेल्टा से आने वाले आर्थिक प्रवासियों की भरमार है।

मछुआरा समुदायों के लिए काम करने वाले पाकिस्तान फिशरफोक फोरम का अनुमान है कि डेल्टा के तटीय जिलों से हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। हालांकि, एक पूर्व जलवायु परिवर्तन मंत्री के नेतृत्व वाले थिंक टैंक, जिन्ना इंस्टीट्यूट की तरफ से मार्च में आई एक स्टडी के अनुसार पिछले दो दशकों में समग्र सिंधु डेल्टा क्षेत्र से 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं।

यूएस-पाकिस्तान सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन वॉटर की तरफ से सरल 2018 में की गई एक स्टडी के अनुसार सिंचाई नहरों, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और जलवायु परिवर्तन के हिमनदों और बर्फ पिघलने पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण सन् 1950 के दशक से डेल्टा में पानी का बहाव 80 प्रतिशत कम हो गया है।

इसके कारण समुद्री जल का विनाशकारी घुसपैठ हुआ है। 1990 के बाद से पानी में नमक का स्तर करीब 70 प्रतिशत बढ़ गया है। इसकी वजह से फसलें उगाना असंभव हो गया है और झींगा और केकड़ों की आबादी पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। स्थानीय डब्ल्यूडब्ल्यूएफ संरक्षणवादी मुहम्मद अली अंजुम ने कहा, डेल्टा डूब रहा है और सिकुड़ रहा है।

तिब्बत से शुरू होकर, सिंधु नदी पूरे पाकिस्तान में बहने से पहले कश्मीर से होकर बहती है। यह नदी और इसकी सहायक नदियां देश के लगभग 80 प्रतिशत कृषि भूमि की सिंचाई करती हैं और लाखों लोगों की आजीविका का साधन हैं। नदी द्वारा समुद्र में मिलने पर जमा किए गए तलछट से बना यह डेल्टा कभी खेती, मछली पकड़ने, मैंग्रोव और वन्यजीवों के लिए आदर्श था। लेकिन साल 2019 में एक सरकारी जल एजेंसी के रिसर्च में पाया गया कि समुद्री जल के अतिक्रमण के कारण 16 फीसदी से ज्यादा उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ हो गई है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

टैरिफ वार अबकी बार आर या पार

अमेरिका की ओर से लगातार भारत को टैरिफ धमकियां दी जा रही हैं और अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर को निशाना बनाया है और नई धमकी दे डाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50-100 फीसदी नहीं, बल्कि 250 फीसदी तक टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। इसका सीधा असर इस सेक्टर से जुड़ी भारतीय कंपनियों पर भी देखने को मिला और इनके शेयर कारोबार के दौरान बिखरे हुए नजर आए। ट्रंप ने कहा कि पहले फार्मा सेक्टर पर छोटा टैरिफ लगेगा और इसे अगले 18 महीनों में सीधे 150 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा और फिर ये 250 प्रतिशत तक पहुंचेगा। राष्ट्रपति ने इसे अमेरिका के घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा कदम बताया है। इसके बावजूद विश्व के पांच बड़े देश भारत, चीन, ब्राजील, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका ट्रंप के टैरिफ के दबाव में नहीं आए हैं। ये देश अब टैरिफ वार पर अबकी बार आर या पार की तैयारी में हैं। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दबाव की रणनीति के तहत टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाए हैं। इसकी वजह यह है कि वैश्विक स्तर पर कई बड़े सेक्टर्स में अमेरिका अब शीर्ष पर नहीं है और चीन ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है। हाल के दशकों में वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति के चलते चीन-भारत समेत अन्य यूरोपीय देश अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग, इस्पात, नवीकरणीय ऊर्जा, 5जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेक्टर्स में चुनौती दे रहे हैं। इनमें से कुछ सेक्टर्स में तो चीन ने अमेरिका को पछाड़ते हुए अपना दबदबा कायम कर लिया है। इससे ट्रंप घबराए हुए हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी लगातार घाटे में जा रही है। इस नुकसान से बचने के लिए हम उन सभी देशों पर टैरिफ लगाएंगे, जो हमारे सामानों पर टैरिफ लगाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब एक महीने बाद 2 अप्रैल को भारत समेत 69 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। यह 9 अप्रैल से लागू होने वाला था, लेकिन ट्रंप ने तब इसे टाल दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि वे दुनियाभर के देशों को अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए 90 दिनों का वक्त दे रहे हैं 31 जुलाई को समझौते की तारीख खत्म हो गई। इस दिन ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया। जिन देशों ने अमेरिका के साथ समझौता किया, उन पर 10 से 20 प्रतिशत टैरिफ लगा और जिन देशों ने ऐसा नहीं किया, उन पर 25 से 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा। भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा, क्योंकि उसने ट्रंप की शर्तें नहीं मानीं। अमेरिका भारत के एग्री और डेयरी सेक्टर में एंट्री चाहता है और मांसाहारी गाय का दूध बेचना चाहता है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे किसानों के हित के अलावा धार्मिक वजहें भी हैं। साथ ही भारत अपने छोटे और मंझोले उद्योगों को लेकर ज्यादा सावधानी बरत रहा है। ट्रंप ने भारत पर पहले 26 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। 4 महीने बाद इसमें सिर्फ 1 प्रतिशत का अंतर आया। अब भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लागू है भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच कई स्तर की बातचीत हुई, लेकिन 31 जुलाई तक कोई समझौता नहीं हो पाया। अमेरिका और भारत के बीच डील न होने पर ट्रंप ने नाराजगी जताई और कहा कि वे रूस से हथियार और तेल खरीदने की वजह से भारत पर पेनल्टी भी लगाएंगे।

ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए देश विकल्प तलाश रहे हैं। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अब अमेरिका पर निर्भर न रहकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए बाजारों में सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने अपने किसानों, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और छोटे उद्योगों के लिए राहत पैकेज शुरू किए। ब्राजील ने एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और सब्सिडी दी, ताकि अमेरिकी टैरिफ का असर कम हो। चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन में जाकर ट्रंप की नीतियों की शिकायत की है। उनका कहना था कि टैरिफ के कुछ फैसले अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ हैं। भारत भी यह प्रक्रिया शुरू कर चुका है।

अमेरिका की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर पर निर्भर है। लेकिन जुलाई 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में ग्रोथ लगभग रुक गई है। इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्विस का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 50.1 पर आ गया है, जो ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्शन के बीच की लाइन है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन ठहर गया है। अमेरिका अब 1980-90 के दशक जैसा मैन्युफैक्चरिंग पावर भी नहीं है। अब इस सेक्टर में चीन ने बढ़त हासिल कर ली है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में चीन का वैश्विक विनिर्माण उत्पादन में हिस्सा करीब 30 प्रतिशत था, जबकि अमेरिका 17 फीसदी के साथ दूसरे पायदान पर रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत और चीन जैसे देशों में सस्ता श्रम और बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता को माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और टेक्सटाइल्स में चीन का दबदबा बना हुआ है। हालांकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें अमेरिका की उत्पादन क्षमता अब भी ज्यादा है। स्टील प्रोडक्शन के मामले में भारत लगातार अपने पैर पसार रहा है और चीन के बाद इस सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। साल 2023 में चीन ने वैश्विक इस्पात उत्पादन का 54 फीसदी हिस्सा उत्पादित किया, जबकि अमेरिका का हिस्सा सिर्फ 4-5 प्रतिशत रहा। स्टील उत्पादन के मामले में चीन के बाद भारत, जापान, अमेरिका और फिर रूस का नंबर आता है।

● **सुश्री नित्या**

ऑनलाइन अश्लीलता पर प्रहार

केंद्र सरकार ने हाल में आपत्तिजनक एवं अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले एप्स पर लगाम कसते हुए 25 एप्स पर प्रतिबंध लगाया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील कंटेंट और आपत्तिजनक एड दिखाने वाले एप्स की पहचान करते हुए यह कदम उठाया। ऑस्ट्रेलिया भी इस दिशा में कुछ बड़ी पहल कर रहा है। इसमें संदेह नहीं कि ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्म्स के उदय ने युवा मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला है।

एक शोध के अनुसार, औसत भारतीय युवा प्रतिदिन घंटों स्ट्रीमिंग मीडिया देखता है। उसका यह समय वैश्विक औसत से अधिक है। ओटीटी प्लेटफार्म टेलीविजन स्क्रीन से लेकर छोटे मोबाइल तक अपना कब्जा जमाए हुए हैं और युवा पीढ़ी के साथ हर आयु वर्ग को ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी भरपाई संभव नहीं। अश्लील सामग्री परोसते ये प्लेटफार्म बालकों, किशोरों, प्रौढ़ों और यहां तक कि गृहिणियों तक अपनी सहज पहुंच बना रहे हैं। इसमें डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म भी सहायक बन रहे हैं। एक्स, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म्स पर भी अश्लील सामग्री की भरमार है। अपने व्यावसायिक हितों के लिए ये प्लेटफार्म बच्चों को अपरिपक्व आयु में व्यस्कता की ओर धकेल रहे हैं। सोफी बिस्नोनेट की डाक्यूमेंट्री सेक्सी इंक अवर चिल्ड्रन अंडर इन्फ्लुएंस-यूथ वर्जन अति-कामुकता और युवाओं पर इसके हानिकारक प्रभावों का विश्लेषण करती है।

अश्लील कंटेंट लड़कियों-महिलाओं को यौन वस्तुओं के रूप में पेश करता है। जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक हेल्थकेयर के एक अध्ययन के अनुसार, सात-आठ साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन और वास्तविक जीवन में क्या हो रहा है, इसके बीच अंतर करने में कठिनाई होती है। इससे समस्याग्रस्त यौन व्यवहार (पीबीएस) हो सकता है। यह दूसरों से बातचीत करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। पीबीएस किसी के जीवन को देखने के तरीके को बहुत प्रभावित कर सकता है, जिससे किसी के लिए यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं? अश्लील कंटेंट बच्चों और युवाओं के भीतर विषाक्तता को जन्म देता है और वे हिंसा तथा अश्लीलता को अपने जीवन में सहजता से स्वीकार कर लेते हैं।

जो बच्चे-किशोर अश्लीलता, यातना, दुष्कर्म की हिंसक छवियां देख रहे हैं, उनका मनोवैज्ञानिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य जोखिम में है। बच्चों द्वारा बच्चों पर यौन हमलों में खतरनाक वृद्धि विषाक्त ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच के कारण हो रही है। 2024 में एक अध्ययन में पाया गया कि इंग्लैंड और वेल्स में बच्चों द्वारा किए गए दुष्कर्म, यौन हमलों और दुर्व्यवहार की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। एक साक्षात्कार में ब्रिटेन की राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख परिषद के बाल संरक्षण प्रमुख इयान क्रिचले ने कहा कि स्मार्टफोन के माध्यम से हिंसक अश्लील और स्त्री-द्वेषी सामग्री तक पहुंच बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। अमेरिका के 16 राज्यों ने अश्लील फिल्मों-दृश्यों को समाज के लिए विषाक्त माना। अमेरिकी राज्य यूटा की सीनेट ने अश्लीलता को जनस्वास्थ्य खतरा बताया है। यह गंभीरता से विचार करने का विषय है कि क्या हम एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, जो हमारे ही द्वारा अंधेरे में धकेली जा रही है? अपने व्यावसायिक हित साधने वाले जो कुछ भी ओटीटी प्लेटफार्म्स और डिजिटल साइट्स पर परोस रहे हैं, उसे प्रतिबंधित करने के साथ यह विचार करना भी आवश्यक है कि बच्चों की इन माध्यमों तक पहुंच क्या सहज रूप से हमने स्वयं नहीं बनाई? 2024 में प्रकाशित जोनाथन हैडट की पुस्तक द एन्क्सियस जेनरेशन: हाउ द ग्रेट रिवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड इज काजिंग एन एपिडेमिक ऑफ मेंटल इलनेस अनिवार्य रूप से माता-पिता से आग्रह करती है कि वे अपने किशोरों-बच्चों के स्मार्टफोन और डिजिटल मीडिया के उपयोग करने के तरीके में बदलाव लाएं। उनका दृष्टिकोण वर्षों के शोध पर आधारित है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समिति, इन्दौर, जिला इन्दौर

लक्ष्मीबाई नगर, इन्दौर, दूरभाष क्रमांक 0731-2411223, 2412902

Fax No.:-0731-2412040 & E-mail ID :- apmcindore@gmail.com

-: कृषकों से अपील :-

1. किसान भाई अपनी विक्रित कृषि उपज का भुगतान उसी दिन प्राप्त करें, यदि भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी लिखित सूचना अगले दिन तक मण्डी कार्यालय में अवश्य देवें अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि संबंधित कृषक को भुगतान प्राप्त हो गया है तथा इसके बाद की जाने वाली शिकायत को आपसी लेन-देन माना जावेगा।
2. किसान भाई शासन के नियमानुसार राशि रू. 2 लाख रूपये तक का नगद भुगतान प्राप्त करें तथा शेष राशि RTGS/NEFT से प्राप्त कर सकते हैं। तथा चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त न करें।
3. धोखाधड़ी से बचने हेतु किसान भाई अपनी कृषि उपज को मण्डी प्रांगण में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को ही खुली नीलाम अथवा सौदा पत्रक एप के माध्यम से ही विक्रय करें तथा मण्डी प्रांगण के बाहर किसी भी स्थिति में सीधे विक्रय न करें।
4. किसान भाई मण्डी प्रांगण में कृषक भोजन, कृषक विपणन पुरस्कार, विश्राम गृह तथा शासन की अन्य सुविधाओं का लाभ उठायें।
5. किसान भाई अपने एंड्राइड मोबाईल में गूगल प्लेस्टोर से फार्म गेट एप इंस्टाल कर, उस पर अपना पंजीयन स्वयं कर सकते हैं।

सचिव
मण्डी, इन्दौर

अपर कलेक्टर/भारसाधक अधिकारी
मण्डी इन्दौर

गीता में है सुखी जीवन का राज

आज के भागदौड़ भरे समय में खुश रहना एक मुश्किल काम है। ऐसे में आप भगवद् गीता में बताए गए उपदेशों को आत्मसात कर जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गीता में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनके द्वारा व्यक्ति मुश्किल परिस्थिति में भी प्रसन्न रह सकता है।

गीता के उपदेश असल में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया ज्ञान है। भगवद् गीता की मान्यता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसे पढ़ा और आत्मसात किया जा रहा है। गीता में वर्णन मिलता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने व्यक्ति को खुश रहने के कुछ तरीके बताए हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

भगवद् गीता में श्रीकृष्ण, अर्जुन से कहते हैं कि यदि व्यक्ति को प्रसन्न रहना है, तो उसे दूसरों की आलोचना से दूर रहना होगा। इसी के साथ बेवजह दूसरों की शिकायत करना भी छोड़ दें। तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं।

खुश रहने का मूल मंत्र

कई बार व्यक्ति हर चीज में दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। इस विषय में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है, जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि आप जैसे हैं, वैसे ही खुद को स्वीकार करें।

नहीं सताएगा कोई भी दुख

गीता का उपदेश देते समय भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति को कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यानी आपको कोई भी काम बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस सीख को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो दुख का जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाएगा।

खुश नहीं रहते ऐसे व्यक्ति

जो बीत चुका है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति अतीत के बारे में सोचता रहता है, वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इस विषय में गीता में कहा गया है कि अगर आप अतीत की स्मृतियों को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे, तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़ें।

श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए युद्ध पहला विकल्प नहीं है क्योंकि युद्ध से सृजन बाद में होता है और विनाश पहले। आप जिस उद्देश्य से युद्ध कर रहे हो, उसे पूरा होने में समय लगता है। ऐसे में शुरुआत में युद्ध व्यर्थ लगता है इसलिए युद्ध करने से पहले अपने युद्ध के उद्देश्य को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। युद्ध से पहले आपसी संवाद की जगह होती है। इस आपसी संवाद में खुले मन से अपनी बात कहने के साथ दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। जब दोनों पक्ष युद्ध की स्थिति टालने का प्रयास करेंगे, तभी शांतिवार्ता हो सकती है।

भगवद् गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है जब आपसी बातचीत से समस्या का हल न निकले, तो युद्ध एकमात्र विकल्प होता है। इसके अलावा जब कण-कण में अन्याय, अधर्म और छल-कपट का वास हो, तो भी परिस्थिति को बदलने के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाते हैं। सभी युद्धों में न्याय युद्ध सबसे ऊपर माना जाता है। हर मनुष्य का न्याय स्थापित करना युद्ध का पहला उद्देश्य होना चाहिए। न्याययुद्ध को ही धर्मयुद्ध भी कहा जाता है।

भगवद् गीता के अनुसार, युद्ध करने से पहले एक योद्धा को युद्ध की परिस्थियां, शत्रु और अपनी शक्तियों का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आधा-अधूरा ज्ञान हमेशा ही घातक होता है। जैसे, अभिमन्यु को चक्रव्यूह का आधा-अधूरा ही ज्ञान था। यही कारण था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गए लेकिन चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। इसका लाभ शत्रु पक्ष कौरव ने उठाया और वीर, साहसी और पराक्रमी होने के बाद भी अभिमन्यु विजय नहीं हो सके।

गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि अन्याय होने पर अगर आप हमेशा मौन रहेंगे और कोई ध्वनि तक उत्पन्न नहीं करेंगे, तो इससे अन्याय करने वाले लोगों का साहस बढ़ेगा। इससे अन्याय बढ़ता जाएगा, इसलिए गलत और अन्याय करने वाले के दिल में हमेशा दंड का भय बना रहना बहुत जरूरी है। कभी-कभी युद्ध टालने या फिर दूसरे युद्ध की स्थिति से बचने के लिए भी शत्रुओं के बीच दंड का भय बनाना बहुत जरूरी है।

● ओम

भक्ति या आडंबर

वृंदावन की संकरी गलियों में धूप आग उगल रही थी। मंदिर के सामने, आठ साल की गुड़िया माथे पर पसीना और आंखों में चिंता लिए, हर आते-जाते से गिड़गिड़ा रही थी-भैया, तिलक लगवा लो न, बस मां की दवा के लिए पैसे चाहिए।

लोग आते, चले जाते। कोई नजरें फेर लेता, कोई जल्दी में आगे बढ़ जाता। गुड़िया की मासूम आवाज भीड़ के शोर में खो जाती। थक-हार कर वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। दो छोटे हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति की ओर देख, रूंधी आवाज में बोली -हे भगवान, कोई तिलक नहीं लगवाता तो मैं मां की दवा कैसे लाऊं? क्या तुम्हें मेरी पुकार सुनाई नहीं देती या तुम सिर्फ बड़े आदमियों की सुनते हो?

इतना कह गुड़िया बिलख उठी और उसकी सिसकियां मंदिर की घंटियों में गुम होती रहीं।

उसकी करुण पुकार सुन, पास ही परिक्रमा कर रहा एक युवक रुक गया। उसने गुड़िया को देखा-धूल में सनी पर उम्मीद से भरी वो आंखें किसी चमत्कार की राह तक रही थीं।

युवक उसके पास आया, मुस्कराया- बहना, मुझे तिलक नहीं लगाओगी?

अविश्वास से गुड़िया ने उसे देखा और फिर युवक को तिलक लगा दिया। युवक ने बिना कुछ कहे उसके हाथ में 200 रुपए रख दिए और भीड़ में अदृश्य हो गया।

बुत्त सी बनी गुड़िया 200 रुपए के नोट को देखती रही। कुछ सेकंड बीतने के पश्चात वो उसी दिशा में भागी जिस दिशा में वो युवक गया था और कांपती आवाज में पुकारने लगी-भगवान! किधर गए तुम? भगवान, किधर गए तुम!

और भीड़ में उस युवक को ढूंढने लगी। उसे पक्का विश्वास था कि भगवान ही इंसानी रूप धरकर उसकी मदद को आए थे।

इधर युवक के कदम भी रुक गए। उसने गुड़िया की ओर देखा और सोचने लगा- क्या अब तक की मेरी पूजा, व्रत, तीर्थ-सब आडंबर था? आज किसी मासूम की मदद कर मुझे असीम शांति मिली है। शायद दूसरों की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है।

वो युवक भी किसी का भगवान बन, आज अपने भगवान को पा चुका था। नि:संदेह- ईश्वर वही है, जो किसी की पुकार का जवाब बन जाए। और भक्ति वही जो इंसानियत के चेहरे पर मुस्कान बनकर उभरे।

- अंजु गुप्ता 'अक्षरा'

अर्पिता का पहला प्रेम योग था और वह अपना योग स्टूडियो चला रही थी, लेकिन 22 साल की उम्र में एक हादसे ने उसको हमेशा के लिए व्हील चेयर का मोहताज कर दिया। इस हादसे के बाद

ये हुई न बात

पहली बार वह दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए निकली। लोगों का उसे अजीब निगाहों से देखना उसको खराब लगना ही था! तभी एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा- बेटी, आप बहुत मजबूत हो, कि इस हालत में भी दुनिया का सामना करने के लिए बाहर आई हो। इन्हीं शब्दों के जादू से वह इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में बतौर फिजिकल ट्रेनर और योग इंस्ट्रक्टर काम कर रही है। आज वह सफल एथलीट है और समर्पण से योग व काउंसिलिंग के जरिए दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर रही है।

उसके समर्पण को देखकर सब कहते हैं- ये हुई न बात!

- लीला तिवानी

शुभमन गिल का शानदार शुभारंभ

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे से पहले ज्यादातर क्रिकेट पंडितों ने शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम को कमतर आंका था और कहा था कि नए और एक कम अनुभवी कप्तान के रहने से टीम को नुकसान होगा, लेकिन गिल एंड कंपनी ने सभी के मुंह पर ताला लगा दिया है। पहले मुकाबले की बात करें तो भारत की तरफ से पांच शतकों पर इंग्लैंड के दो शतक भारी पड़े और भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। मगर दूसरे मुकाबले में भारत के 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की दूसरी पारी 271 रन पर सिमट गई। इसी के साथ 2021 में ऑस्ट्रेलिया के गाबा का घमंड तोड़ने वाली टीम इंडिया ने अब बर्मिंघम-एजबेस्टन का घमंड तोड़ दिया है। इस जीत के साथ ही शुभमन युग का शुभारंभ भी हो चुका है। इस सीरीज का परिणाम 2-2 का रहा। वर्ष 2020 में मेलबर्न टेस्ट में पदार्पण करने के बाद से ही शुभमन गिल ने दिखा दिया था कि उनमें लंबी रेस का घोड़ा बनने की क्षमता है। तकनीकी दृष्टि से मजबूत, मानसिक रूप से ठोस और तेजी से सीखने वाले गिल ने खुद को एक विश्वसनीय बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया। केएल राहुल, ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे जैसे वरिष्ठों की अनुपस्थिति और रोहित शर्मा की उम्र बढ़ने के साथ गिल को युवा नेतृत्व के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। गिल को टेस्ट कप्तानी ऐसे समय में मिली जब टीम एक बदलाव के दौर से गुजर रही थी। पुराने खिलाड़ी धीरे-धीरे बाहर हो रहे हैं और नई पीढ़ी अपनी जगह बना रही है। इससे पहले रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में गिल की कप्तानी में भारत ने पहला टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेला, जिसमें भारत ने पारी से जीत दर्ज की थी। शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी रणनीति को स्पष्ट और सटीक रखा। गेंदबाजों के स्पैल, फील्ड सेटिंग और डीआरएस के इस्तेमाल में गिल की सक्रियता नजर आई। युवा खिलाड़ियों को मौके देना और सीनियर खिलाड़ियों की सलाह सुनना, गिल ने दोनों का अच्छा संतुलन बनाए रखा। गिल, विराट कोहली जैसी ऊर्जा तो लाते हैं, लेकिन धोनी जैसी शांति भी उनके हावभाव में दिखती है। गिल की कप्तानी में भावनात्मक नियंत्रण और रणनीतिक सोच दोनों नजर आती हैं। वे मैदान पर शांत रहते हैं, लेकिन जीत के लिए जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते। इस संतुलन ने उन्हें युवा खिलाड़ियों के लिए एक भरोसेमंद कप्तान बना दिया है। गिल को कप्तानी रोहित शर्मा से मिली। एक ऐसे कप्तान से जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत को स्थिरता दी। गिल ने रोहित की कप्तानी की सकारात्मक बातों को अपनाया और अपनी शैली में उसे ढाला। किसी भी युवा कप्तान के सामने चुनौतियां होती हैं और गिल भी इससे अछूते नहीं है। उनमें कप्तानी का अनुभव घरेलू स्तर पर जरूर है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बिल्कुल अलग होता है। खासकर वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ संतुलन बैठाना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन गिल ने अब तक इसमें परिपक्वता दिखाई है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में कप्तान की रणनीतिक समझ की असली परीक्षा होती है। गिल की कप्तानी को असली कसौटी वहीं मिलेगी। शुभमन गिल की उम्र अभी मात्र 25 के करीब है। ऐसे में यदि उन्हें निरंतर समर्थन मिले, तो वे लंबे समय तक भारत के टेस्ट कप्तान बने रह सकते हैं। आने वाले वर्षों में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की कप्तानी में गिल भारत को शीर्ष पर पहुंचा सकते हैं। वे युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने वाले कप्तान बन सकते हैं। गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया अधिक स्थायित्व और नई पहचान पा सकती है। कुल मिलकर शुभमन गिल की टेस्ट कप्तानी भारतीय क्रिकेट में एक नई शुरुआत का संकेत है। वे न केवल तकनीकी रूप से दक्ष बल्लेबाज हैं, बल्कि उनमें भविष्य के महान कप्तानों वाली समझदारी और शांति भी है। उनका सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन शुरुआती कदमों से ही यह साफ हो चुका है कि गिल नेतृत्व की चुनौती को निभाने के लिए तैयार हैं। अगर टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई उन्हें लंबा मौका देते हैं तो गिल आने वाले दशक में भारत को टेस्ट क्रिकेट में एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। महज 25 वर्षीय शुभमन गिल को टेस्ट टीम की कमान ऐसे समय में सौंपी गई है, जब भारतीय क्रिकेट एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे दिग्गज धीरे-धीरे पीछे हट रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे कप्तान की जरूरत थी, जो मैदान पर स्थिरता लाए, ड्रेसिंग रूम में प्रेरणा बने और भविष्य के लिए एक विजन तैयार करे। गिल इन तीनों ही कसौटियों पर खरे उतरने की क्षमता रखते हैं। टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबी है धैर्य, ठीक वैसा ही धैर्य गिल की बल्लेबाजी में झलकता है। शायद यही गुण अब उनकी कप्तानी में भी देखने को मिल रहा है।

● आशीष नेमा

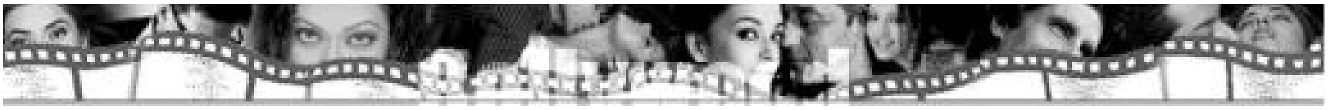

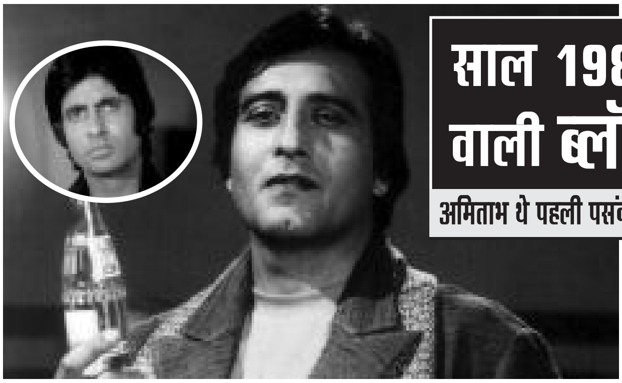

साल 1980 की तगड़ी रेटिंग वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म

अमिताभ थे पहली पसंद, विनोद खन्ना ने हीरो बन मचाया था गदर

आज से 45 साल पहले विनोद खन्ना की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। असल वो मूवी पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था।

अमिताभ बच्चन साल 1973 में रिलीज हुई जंजीर की कामयाबी से सुपरस्टार बन गए थे। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिग बी को एक दमदार फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में वही मूवी विनोद खन्ना को मिली और फिर बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मच गया था। उस फिल्म का नाम है कुर्बानी।

साल 1980 में एक्शन ड्रामा फिल्म कुर्बानी का बॉक्स ऑफिस पर खूब डंका बजा था। इसमें फिरोज खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान, कादर खान, शक्ति कपूर और अमजद खान जैसे सितारे नजर आए थे।

कुर्बानी को फिरोज खान ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी के लिए विनोद खन्ना नहीं, बल्कि महानायक अमिताभ बच्चन पहली पसंद थे। फिरोज खान ने बिग बी को फिल्म ऑफर भी की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई।

डीएनए में छपी रिपोर्ट के अनुसार, फिरोज खान ने जब अपनी फिल्म को लेकर अमिताभ बच्चन से बात की, तो उन्होंने काम करने की दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन पेंच फंस गया कि वह 6 महीने बाद की डेट्स दे रहे थे।

फिरोज खान किसी भी हाल में 6 महीने का इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन के रिजेक्ट करने के बाद विनोद खन्ना को कास्ट कर लिया। इस तरह बिग बी के हाथ से कुर्बानी जैसी बड़ी फिल्म निकल गई थी।

सिनेमाघरों में 3 महीने तक हाउसफुल चली थी फिल्म

सिनेमाघरों में रिलीज के बाद कुर्बानी ने गदर काट किया था। आईएमडीबी के मुताबिक, मुंबई के सारे थिएटर्स में फिल्म 3 महीने तक हाउसफुल चली थी। कुर्बानी में विनोद खन्ना ने अमर का रोल निभाया था और फिर फिल्म की कामयाबी से वह सुपरस्टार बन गए थे। फिरोज खान, राजेश कुमार के किरदार में दिखे थे। सिनेमाघरों में लगने के बाद कुर्बानी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। यह साल 1980 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। कुर्बानी के गाने भी सुपरहिट हुए थे। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 7.1 है। कुर्बानी उस जमाने में महज 2.5 करोड़ रुपए की लागत में बनकर तैयार हो गई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का ताबड़तोड़ बिजनेस किया था। लागत से लगभग 10 गुना ज्यादा कलेक्शन कर फिल्म ने ब्लॉकबस्टर का टैग अपने नाम कर लिया था।

79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।

सचिव भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, सांवेर, जिला-इंदौर

79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, धामनोद, जिला-धार

79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, कुक्षी, जिला-धार

> *कहां है, किसका है परिवार जरा हमें भी बताइए महज चंद अपवादों को छोड़कर आज जरा कोई ऐसा परिवार तो बताइए, जिसमें अपने बीवी-बच्चों के अलावा ताई-ताऊ, चाचा-चाची, दादा -दादी और नौनिहालों की फौज साथ-साथ रह रहे हों। सच तो यह है कि हमारे अपने मां-बाप भी विवशतावश ही हमारे साथ रहते हैं, साथ होने की सजा भी तो सह रहे हैं- अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा और जाने क्या कुछ नहीं सह रहे हैं।*

महज कहानी है...

आइए! एक और दिवस की औपचारिकता निभाते हैं, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। क्योंकि बस यही तो हमारे हाथ में है परिवार हमसे और हम परिवार से कोसों दूर हैं हम हों या आप, दूरियां बढ़ाते जा रहें हैं। मेरी बातें आपको अभी से चुभने लगी हैं, इसका मतलब है, मेरी बात सही होने जा रही है। वास्तव में जो मैं कहने जा रहा हूं, सच कहूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है अपनों की शिकायत अपनों से ही कर रहा हूं, खुद के साथ अपनों को ही नंगा कर रहा हूं। आखिर मैं भी तो परिवार दिवस मना रहा हूं। कहां है, किसका है परिवार जरा हमें भी बताइए महज चंद अपवादों को छोड़कर आज जरा कोई ऐसा परिवार तो बताइए, जिसमें अपने बीवी-बच्चों के अलावा ताई-ताऊ, चाचा-चाची, दादा -दादी और नौनिहालों की फौज साथ-साथ रह रहे हों। सच तो यह है कि हमारे अपने मां-बाप भी विवशतावश ही हमारे साथ रहते हैं, साथ होने की सजा भी तो सह रहे हैं- अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा और जाने क्या कुछ नहीं सह रहे हैं। क्या और साफ-साफ कहने की जरूरत है? यदि हां तो अनाथालयों-वृद्धाश्रमों में इतनी भीड़ का आखिर हिस्सा कौन हैं?

क्या वास्तव में इन सबके आगे-पीछे कोई नहीं है या फिर हमारी आंख का पानी सूख गया है। निजता की आड़ में, स्वतंत्रता की चाह में, बढ़ते खर्चों के साथ तरह-तरह के बहानों के साथ बढ़ती बेशर्मी, आधुनिकता का दंभ, सेवा-सत्कार से मुंह चुराने की बढ़ती प्रवृत्ति, अपने ही भाई-बहनों से ईर्ष्या, स्टेटस का डर, बढ़ती स्वार्थी प्रवृत्ति धन-संपत्ति, जमीन-जायदाद का लोभ और तरह-तरह की नाटकीयता हमें परिवार विहीन बना रही है। जाने कितने अपनों को लावारिसों की तरह मौत के मुंह में जबरन ढकेल रही है, और हमें बेहया-बेशर्म बना रही है।

फिर आप ही बताइए! आखिर परिवार दिवस का क्या मतलब है? ऊपर से अंतरराष्ट्रीय दिवस तो महज ढकोसला है पड़ोसी मुल्कों में संबंध कैसा है? आप भी जानते हैं, सबका अपना-अपना किस्सा है, जब हम एक परिवार नहीं सहेज पा रहे हैं, तब विश्व परिवार की संकल्पना क्यों कर रहे हैं शायद हम खुद को बरगला रहे हैं। या हम मुल्कों के बीच छिड़े संघर्ष को देख नहीं पा रहे? धर्म, जाति, भाषा, सीमा विवाद नित गहराते जा रहे हैं। एक देश के लोग दूसरे देश में अस्थिरता, अराजकता, आतंकवाद, हिंसा फैला रहे हैं, बिना किसी संकोच लोगों को मार-काट रहे हैं, थोक भाव में लाशें गिराने से कहां झिझक रहे हैं। आपसी सामंजस्य बढ़ाने के बजाय छोटी-छोटी बातों को बेवजह तूल दे रहे हैं, जिसके परिणाम नित हिंसक होते जा रहे हैं, वैमनस्यता का नया इतिहास गढ़ते जा रहे हैं। हर घर परिवार की एक सी कहानी है परिवार दिवस हो अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस की बात आप मानो न मानो सिर्फ बेमानी है, महज कहने-सुनने में अच्छी लगने वाली एक कहानी है।

● सुधीर श्रीवास्तव

स्वाधीनता के अमर बलिदानियों को कोटि-कोटि नमन
स्वदेशी की शक्ति से
आत्मनिर्भरता को गति देता
मध्यप्रदेश
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
79वें
स्वतंत्रता दिवस
की प्रदेशवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
स्वदेशी अभियान के साथ औद्योगिक विकास
उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयासों से ₹32 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 23 लाख से अधिक रोजगार होंगे सृजित
कमज़ोर वर्ग का उत्थान
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों को मिल रही सहायता
युवाओं का सर्वांगीण विकास
शिक्षा, कौशल निर्माण के साथ युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए मध्यप्रदेश युवा प्रेरक अभियान और आगामी 5 वर्षों में 2.5 लाख नौकरियां देने जैसे प्रयासों से युवा हो रहे सशक्त
आत्मनिर्भर होती महिलाएं
महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में प्रतिमाह ₹1250, एमएसएमई में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन, लखपति दीदी योजना और शासकीय सेवाओं में 35% तक महिला आरक्षण
खुशहाल और समृद्ध अन्नदाता
किसानों की आय में वृद्धि, जलवायु-अनुकूल खेती तथा फसल का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन, कृषि संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कृषि उद्योग समागम का आयोजन, पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से आ रही है खुशहाली
प्रातः 9:00 बजे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
से लाइव जुड़ें
❝ स्वतंत्रता दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। यह अवसर हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और योगदान को स्मरण करने तथा उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
-डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
सीधा प्रसारण webcast.gov.in/mp/cmevents

व्यापक निवेश अवसर

सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना

योजना के प्रमुख उद्देश्य

- मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी को कम मूल्य पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- ट्रांसमिशन हानि कम करना एवं सीधे खपत स्थल पर बिजली पहुंचाना
- 33/11 केवी उपकेंद्रों पर ओवरलोडिंग, लो-वोल्टेज और पावर कट की समस्या कम करना
- किसान को सिंचाई के लिये दिन में बिजली उपलब्ध कराना

नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार

- सब-स्टेशन की 100% क्षमता तक की परियोजनाओं की स्थापना
- परियोजनाओं को पीएम कुसुम-सी योजनांतर्गत उपलब्ध केंद्रीय अनुदान का लाभ लेने का विकल्प
- 1900 से अधिक विद्युत सबस्टेशन एवं 14500 मेगावॉट क्षमता और परियोजनाओं के चयन हेतु उपलब्ध
- पीएम कुसुम योजना में 3.45 लाख पम्प का लक्ष्य
- वोकल फॉर लोकल - स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश एवं रोज़गार सृजन का उचित अवसर
- वित्त पोषण की सुगमता के लिए बैंकों से समन्वय
- परियोजनाओं में AIF के तहत 7 वर्षों तक 3% ब्याज में छूट
- Reactive Power प्रबंधन से अतिरिक्त आय